हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

13 मार्च, 2003

खण्ड-1, अंक-8

अधिकृत विवरण

विषय सूची

वीरवार, 13 मार्च, 2003

	पृष्ठ संख्या
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(8)1
वाक - आउट	(8)21
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)	(8)21
नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	(8)29
ध्यानाकर्षण प्रस्तावों की सूचनाएं	(8)35
सदन की मेज पर रखे गए कागज-पत्र	(8)35
वर्ष 2003-2004 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)	(8)36
वैयक्तिक स्पष्टीकरण - श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा एम०एल०ए० द्वारा	(8)46
वर्ष 2003-2004 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)	(8)47
शोक प्रस्ताव	(8)50
वर्ष 2003-2004 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)	(8)51
वाक - आउट	(8)73
वर्ष 2003-2004 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)	(8)74
बैठक का समय बढ़ाना	(8)76
वर्ष 2003-2004 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)	(8)76
बजट 2003-2004 की अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान	(8)77

मूल्य 121

विधान कार्य— (8)83

(i) दि हरियाणा एप्रोप्रिएशन (नं० 1) बिल, 2003 (8)83

(ii) चौधरी देवी लाल यूनिवर्सिटी सिरसा बिल, 2003 (8)86

(iii) दि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी (अमैंडमैंट) बिल, 2003 (8)89

(iv) दि महर्षि दयानन्द यूनिवर्सिटी (अमैंडमैंट) बिल, 2003 (8)91

(v) दि हरियाणा म्यूनिसिपल (अमैंडमैंट) बिल, 2003 (8)93

(vi) दि पंजाब विलेज कामन लैंडज (रैगुलेशन) हरियाणा अमैंडमैंट बिल, 2003 (8)95

वाक - आउट (8)96

विधान कार्य— (8)96

(vi) दि पंजाब विलेज कामन लैंडज (रैगुलेशन) हरियाणा अमैंडमैंट बिल, 2003 (पुनरारम्भ) (8)96

(vii) दि हरियाणा पंचायती राज (अमैंडमैंट) बिल, 2003 (8)98

(viii) दि हरियाणा म्यूनिसिपल कारपोरेशन (अमैंडमैंट) बिल, 2003 (8)99

(ix) गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार (अमैंडमैंट) बिल, 2003 (8)101

(x) दि पंजाब एक्साईज (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 2003 (8)102

(xi) दि रेवेन्यू रिकवरी (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 2003 (8)103

(xii) दि हरियाणा जनरल सेल्ज टैक्स (अमैंडमैंट) बिल, 2003 (8)105

(xiii) दि हरियाणा वैल्यू एडिड टैक्स बिल, 2003 (8)106

बैठक का समय बढ़ाना (8)109

विधान कार्य— (8)109

(xiii) दि हरियाणा वैल्यू एडिड टैक्स बिल, 2003 (पुनरारम्भ) (8)109

बैठक का समय बढ़ाना (8)113

विधान कार्य— (8)113

(xiii) दि हरियाणा वैल्यू एडिड टैक्स बिल, 2003 (पुनरारम्भ) (8)113

(xiv) दि हरियाणा डिवैल्पमैंट एंड रैगुलेशन ऑफ अर्बन एरियाज (अमैंडमैंट) बिल, 2003 (8)114

HVS/C06/10/1-X-04

हरियाणा विधान सभा

वीरवार, 13 मार्च, 2003

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हॉल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में प्रातः 9.30 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री सतबीर सिंह कादियान) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष : ऑनरेबल मैम्बर्ज, अब सवाल जवाब होंगे।

Machinery of Irrigation Department

***1320 Ch. Nafe Singh Rathi :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the details of the machinery of the Irrigation and Drainage Department along with the names of places where these are lying at present together-with the cost thereof ; and

(b) whether there is any proposal under consideration of the Government to auction the useless machinery?

मुख्य संसदीय सचिव (श्री राम पाल माजरा) :

(क) सूचना सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(ख) हाँ, श्रीमान जी।

सूचना

क्रमांक	मशीनरी का नाम	संख्या	वास्तविक कुल कीमत (लाख रुपए में)	स्थान
1	2	3	4	5
1.	ड्रेगलीन	19	265.44	झज्जर, रोहतक, चरखी दादरी एच० के० बी० यमुनानगर, यू०डी०डी० पलवल, मेहम ड्रेन, मुनक, करनाल, खुर्द कला, हिसार।

[श्री राम पाल माजरा]

1	2	3	4	5
2.	एक्सकवेटर/पोकलीयन	29	333.08	वर्क्स ऑफ रोहतक, झज्जर, महेन्द्रगढ़, रिवाड़ी, भिवानी, जीन्द, पलवल, सिसाना माइनर, पानीपत, करनाल, कैथल, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, हाँसी, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा।
3.	डोजर/क्रेन ट्रैक्टर	45	257.42	रिवाड़ी वर्क्स शॉप करनाल, एच०के० बी० साईट यू०डी०डी० बल्लभगढ़, पलवल, बौदसा, करनाल वर्क्स शॉप यमुनानगर, जनसूही, कुरुक्षेत्र, सनियाना।
4.	ट्रैक्टर	13	23.96	रिवाड़ी वर्क्स शॉप नारनौल डिस्ट्रीब्यूटरी, साल्हावास, स्टोर, भिवानी, करनाल, फाल, दादूपुर।
5.	गाड़ियां जीप/कार/जिप्सी/ बस/ट्रक/टिप्पर/ पिक-अप्स	490	1059.31	रोहतक, नारनौल, महेन्द्रगढ़, रिवाड़ी, भिवानी, चरखी-दादरी, गोहाना, करनाल, कुरुक्षेत्र, गुडगावां, पानीपत, सोनीपत, पंचकूला, जगाधरी, हांसी, हिसार, टोहाना, सिरसा, फतेहाबाद, कैथल, नरवाना, दिल्ली, फरीदाबाद, साल्हावास, एच०के०बी० साईट, जीन्द
6.	मोबाईल पम्पसैट्स/ डीजल/विद्युत	1884	710.37	वर्क्स ऑफ रोहतक, झज्जर, नारनौल, महेन्द्रगढ़, रिवाड़ी, साल्हावास, लोहानी स्टोर, चरखी-दादरी वर्क्स शॉप, जीन्द, गोहाना, पलवल, नूह, होडल, सोनीपत स्टोर, करनाल, पानीपत, फरीदाबाद, सी०सी० खजुरी (करनाल) जगाधरी, एच०के०बी० साईट, दादूपुर, हिसार/ बडोपल/के०गढ़।
7.	अन्य साजो-सामान (मिसलिनियस इक्युपमैन्ट)	—	134.52	भिवानी, चरखी-दादरी वर्क्स शॉप, जीन्द, करनाल, अम्बाला, रोहतक, दिल्ली रोड, अकबरपुर नेहर स्टोर, नूह, बिन्झोल, बोलही, जगाधरी स्टोर, एच०के०बी० स्टोर, दादूपुर, करनाल, गाँव बांबला, सनियाना।

1	2	3	4	5
8.	डीजल जनरेटिंग सैट	12	19.40	साल्हावास, भिवानी, एच०के०बी० कन्ट्रोल रूम अम्बाला, बरोपड़ स्टोर, राना स्टोर करनाल फाल, पलवल।
9.	पम्प हाउसों पर लगाये गए पम्प	1523	3818.11	पम्प हाउसिज, जे०एल०एन० फीडर पर, जे०एल०एन० नारनौल, जे० एल० एन० रिवाड़ी जुई केनाल, लोहारू फीडर, फरीदाबाद, गुड़गांवा, नगल स्कीम।
	कुल योग		6621.61	अर्थात् 66.21 करोड़ रुपए

चौ० नफे सिंह राठी : अध्यक्ष महोदय, 66 करोड़ रुपये से ज्यादा की मशीनरी कई सालों से पड़ी है, उनको जंग खा रहा है और वह किसी काम नहीं आ रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सी०पी०एस० महोदय से जानना चाहूँगा कि बरसात के दिनों में जो पानी घग्गर और यमुना में बेकार चला जाता है क्या उस मशीनरी से उस पानी को रोकने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है?

श्री राम पाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो सारी मशीनरी 66 करोड़ की बताई है लेकिन मैं अपने माननीय साथी को बताना चाहता हूँ कि इसमें सारी की सारी मशीनरी यूजलैस नहीं है। वास्तविक कीमत की 27 करोड़ 33 लाख की मशीनरी अयोग्य है, जिसकी डिस्पोजल समय-समय पर हम करते रहते हैं। कुछ समय पहले उस मशीनरी में से लगभग 15 करोड़ की मशीनरी डिस्पोज ऑफ कर दी गई थी। साथ ही मेरे माननीय साथी ने जानना चाहा है कि घग्गर और यमुना में बारिश के दिनों में जो पानी बेकार चला जाता है उस पानी को रोकने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। जहां तक यमुना और घग्गर में बारिश के दिनों में पानी आ जाता है और वह कई बार खतरे के निशान से ऊपर चला जाता है और दो तीन दिन बाद खत्म हो जाता है इस तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बाकायदा सभी अधिकारियों की, असैम्बली के मैम्बर्ज की, जितने कैबिनेट के वजीर हैं उनकी मीटिंग बुलाकर उनको यह कहा कि सीमित साधनों से हमें प्रदेश के विकास के काम करके लोगों को मैक्सीमम सैटीस्फाइड करना है। इसी बात को लेकर जो ओल्ड दिल्ली ब्रांच बन्द पड़ी थी उसको चलाने के लिए और यमुना में पानी ज्यादा आ जाए तो उसको यूज करने के लिए उन पर बने पुल जो टूटे हुए थे उनको ठीक करने के लिए एक करोड़ तीन लाख रुपये खर्च किया गया है ताकि ये 50-60 दिन तक पानी सोनीपत, रोहतक, झज्जर, महेन्द्रगढ़, रिवाड़ी, भिवानी, गुड़गांव और फरीदाबाद को दिया जा सके। 2100 क्यूसिक पानी की व्यवस्था इन दिनों में करने का काम हमने शुरू किया है। इसी प्रकार से W.J.C. और मेन ब्रांच हांसी की कैपेसिटी रैस्टोर करने के लिए और कैपेसिटी बढ़ाने के लिए दो करोड़ खर्च किया जा रहा है। इसी प्रकार से सिरसा ब्रांच की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए जिसमें 1400 क्यूसिक पानी अब चलता है उसको 2400 क्यूसिक करने के लिए 3.5 करोड़ रुपये खर्च करके उसके बैंकस को स्ट्रैंग्थन किया जा रहा है और बुढेड़ा से उसका काम जून-जुलाई के महीने में पूरा किया जायेगा। इसी प्रकार से स्पीकर सर, मेन लाईन लौअर दादूपुर से इन्द्री तक एक करोड़ रुपए खर्च करके साढ़े तेरह हजार क्यूसिक से 16 हजार क्यूसिक पानी की कैपेसिटी बढ़ाने की महत्वकांक्षी योजनाएं घग्गर और यमुना नदियों पर शुरू की हैं।

[श्री राम पाल माजरा]

इसके अतिरिक्त हांसी ब्रांच की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए सफाई अभियान शुरू किया गया है जिससे उस की कैपेसिटी 4500 क्यूसिक पानी से बढ़कर 6200 क्यूसिक पानी हो जायेगी। स्पीकर सर, जमना पर इस तरह की योजनाएं बनने से 100 करोड़ रुपये का अधिक उत्पादन होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त मेरे माननीय साथी ने घग्गर में पानी आने की बात की, मैं मानता हूँ कि बरसात के दिनों में घग्गर में बाढ़ आ जाती है। उसकी रोकथाम के लिए भी हमने एक योजना बनाई है। वहां पर रंगोई खरीफ चैनल बनाने का प्रस्ताव रखा है जिससे कई गांवों को लाभ पहुंचेगा। काफी लोगों की इस बारे में मांग भी थी कि रंगोई खरीफ चैनल बनाया जाये इसके बनने से टोहना, रतिया, फतेहाबाद, दड़बा, सिरसा, नरवाना क्षेत्र के धांसवा, चिमू, कलन्द्रगढ़, चण्डोखुर्द, चण्डोकलां, सुखमनपुर, साइनाल, अहरावान, मोहमदपुर सोत्तर, हिजरावान कलां, अहाली सादार, बहुदीन, नरेलाखेड़ा, सिकन्दरपुर और बाजेखां आदि गांवों को लाभ पहुंचेगा और इस बारे में इन गांवों की मांग भी थी कि यह चैनल बनाया जाये ताकि घग्गर के पानी पर कंट्रोल करके उसका सदुपयोग किया जाये। स्पीकर सर, इस पानी पर कंट्रोल होने से यह सिंचाई में प्रयोग हो सकेगा, इससे भूमिगत जल की भी रिचार्जिंग होगी और जमीन की जो उर्वरकता शक्ति है वह भी बढ़ेगी। स्पीकर सर, इस योजना के साथ-साथ एक दूसरी योजना भी बनाई जायेगी जिसके तहत सिंचाई के काम के साथ-साथ पानी की ड्रेनेज करने का काम भी किया जायेगा यानि मल्टी परपज काम किया जा सकेगा। स्पीकर सर, इसी प्रकार से पंचकूला के इलाके में पहाड़ियों से बरसात का पानी आता है और बह जाता है उसका भी सदुपयोग करने के लिए हमने दीवानवाल मेन लाईन के पास घग्गर पर एक बांध बनाने की योजना बनाई है ताकि उस पानी को एकत्रित करके, ट्रीट करवाकर पीने के पानी की व्यवस्था की जा सके। स्पीकर सर, इस तरह से हमने यमुना और घग्गर का जो पानी बह जाता था, हमारे यूज नहीं आता था। हमने इस प्रकार की योजनाएं बनाकर कोशिश की है कि उसको रोककर सिंचाई और पीने के काम में यूज किया जा सके।

चौ० नफे सिंह राठी : स्पीकर सर, नहरों से, सिंचाई से संबंधित यह प्रश्न है इसलिए मैं आपके माध्यम से सी०पी०एस० महोदय से जानना चाहूँगा कि कितने माइनरों, कितने सब माइनरों और कितनी डिस्ट्रीब्यूट्रीज की सफाई यह सरकार आने के बाद यानी जुलाई, 1999 से आज तक हुई है और कितने की क्षमता बढ़ाई गई है तथा उस पर कितने पैसे खर्च हुए हैं। साथ में यह भी बताया जाये कि कितने की क्षमता बढ़ाने बारे प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

श्री राम पाल माजरा : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को बताना चाहूँगा कि टोटल 132 स्कीम हैं जिसमें से 76 न्यू स्कीम हैं और 46 पुरानी स्कीम हैं। जिनमें से 70 पर कार्य प्रगति पर है और 32 पर कार्य जल्दी ही शुरू होने वाला है। इस प्रकार से जुलाई, 1999 के बाद हमारी कौन-कौन सी स्कीम्ज पूरी हुई हैं और कहां-कहां माइनरों पर, सब-माइनरों पर, नहरों पर और डिस्ट्रीब्यूट्रीज पर सफाई का कार्य हुआ है उसके बारे में मैं डिटेल से बताऊंगा तो फिर कांग्रेस के साथी कहेंगे कि इतना लम्बा जवाब दे दिया। स्पीकर सर, पहले वाले दोनों मुख्य मंत्री मेरे सामने बैठे हुए हैं उनके समय में तो कोई काम हुआ नहीं और अब जब मैं हमारे समय के विकास कार्यों के बारे में बताता हूँ तो कह देते हैं लम्बा जवाब दे दिया, क्या करें हमारे समय में विकास कार्य ही बहुत हुए हैं। स्पीकर सर, इसमें हमने पूरे हरियाणा प्रदेश का ख्याल रखा है, अब वह जमाना गया जब पहले वाले मुख्य मंत्री सिर्फ अपने क्षेत्र में ही विकास कार्य करवाते थे, पैसा खर्च करते थे। अब हमने सारे हरियाणा के माइनरों, सब-माइनरों और डिस्ट्रीब्यूट्रीज की तरफ ध्यान दिया है। स्पीकर सर, हमारे समय में नहरों, माइनरों, सब-माइनरों और डिस्ट्रीब्यूट्रीज पर जो काम हुआ है उसका ब्यौरा निम्न प्रकार से हैं :—

जुलाई 1999 से अब तक पूर्ण हुई स्कीमों की सूची

क्रमांक	स्कीम का नाम	अनुमानित लागत (लाख रुपए में)	अब तक का खर्चा	हल्के का नाम
1.	मिरका माइनर का विस्तार।	100.65	79.87	आदमपुर
2.	मण्डी डिच माइनर का निर्माण।	69.16	48.30	बाड़रा
3.	नेकीपुर माइनर का विस्तार।	17.43	5.00	बाड़रा
4.	कड़ी रूपा माइनर का आर०डी० 5500 से 12900 तक का विस्तार।	41.86	11.44	बाड़रा
5.	डगरोली सब माइनर का आर०डी० 0 से 5500 तक निर्माण।	31.76	30.06	बाड़रा
6.	दुलहेड़ा डिस्ट्रीब्यूटरी की आर०डी० 53370 के साथ जुड़ने हेतु असन्ध माइनर का निर्माण।	39.81	30.11	बादली
7.	मांडोली माइनर का निर्माण।	46.25	70.00	बहादुरगढ़
8.	महमदपुर माइनर का निर्माण और धन्धसर डिस्ट्रीब्यूटरी का 00 से 7.47 कि०मी० तक का पुनर्निर्माण।	213.58	286.05	बारोदा
9.	अहुलाना माइनर का निर्माण।	185.04	204.08	बारोदा
10.	सिवाड़ा ताल लिंक चैनल का निर्माण।	212.94	99.25	बवानी खेड़ा
11.	सुन्दर डिस्ट्रीब्यूटरी का विस्तार।	8.87	12.20	बवानी खेड़ा
12.	बाड़सी माइनर का विस्तार।	12.65	10.30	बवानी खेड़ा
13.	पीली मंडोली डिस्ट्रीब्यूटरी का विस्तार।	10.86	7.50	भट्टू
14.	नई खुली माइनर का निर्माण।	—	103.50	भट्टू
15.	सम्पर्क चैनल का आर०डी० 0-2250 का निर्माण जो फतेहाबाद ब्रांच की आर०डी० 246650 के दायीं ओर से निकलेगी और ढिंगा माइनर आर०डी० 29650 बायें की तरफ गिरेगी।	36.95	34.50	भट्टू

[श्री राम पाल माजरा]

क्रमांक	स्कीम का नाम	अनुमानित लागत (लाख रुपए में)	अब तक का खर्चा	हल्के का नाम
16.	मुलीखेड़ा माइनर का आर०डी० 0-15800 तक का निर्माण जो कि फतेहाबाद की ब्रांच आर० डी० 243300-एल० से निकलेगी।	139.06	97.39	भट्टू
17.	जान्दली सब माइनर का आर० डी० 0 से 28900 पर निर्माण जो कि भूना माइनर की आर०डी० 25500 एल० से निकलेगी।	189.06	241.83	भट्टू
18.	निहाला माइनर का आर०डी० 0 से 2800 पर निर्माण जो कि दहमान डिस्ट्रीब्यूटरी की आर० डी० 14200-एल० से निकलेगी।	09.02	20.35	भट्टू
19.	पावड़ा लिंक चैनल।	408.34	406.67	भट्टू
20.	निमड़ी वाली सब माइनर का निर्माण।	255.26	45.00	भिवानी
21.	नया धीराना माइनर।	119.87	44.28	भिवानी/तोशाम
22.	आर०डी० 0 से 6000 से कुराल का बास माइनर।	55.41	58.55	दादरी
23.	माछीवाला माइनर का आर०डी० 16400 से 20400 टेल तक का विस्तार जोकि सिरसा मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी के आर०डी० 91400 एल० से निकलेगी।	15.01	12.31	दरबा
24.	आर० डी० 0 से 24800 तक नये पाना माइनर का निर्माण जो मिथरी डिस्ट्रीब्यूटरी के आर०डी० 17400 आर०डी० से निकलेगी।	165.56	131.20	डावली
25.	आर०डी० 0 से 40065 टेल तक निमला लिंक चैनल का निर्माण जो कि राजस्थान के फीडर के आर० डी० 670800 से निकलेगी।	383.57	283.77	ऐलनाबाद

क्रमांक	स्कीम का नाम	अनुमानित लागत (लाख रुपए में)	अब तक का खर्चा	हल्के का नाम
26.	आर०डी० 0 से 3.66 कि०मी० तक मिलथी सुरेरा माइनर का निर्माण जो कि शेरावाली चैनल के समानान्तर आर०डी० 75742 के बाएं छोर से निकलेगी और शेरावाली समानान्तर चैनल का पुनर्वास।	92.26	55.82	ऐलनाबाद
27.	चिलकानी ढाब माइनर का 0 से 3.66 कि०मी० तक का निर्माण।	104.59	108.31	ऐलनाबाद
28.	गोंची माइनर में छतीर डिस्ट्रीब्यूटरी की आर०डी० 31500 की बाईं ओर बचाव रेगुलेटर चैनल का लगाना।	13.90	10.49	फरीदाबाद
29.	फिरोजपुर कलां का आर०डी० 0 से 3775 तक का निर्माण।	20.85	22.10	फरीदाबाद
30.	जुगलान सब माइनर का निर्माण।	108.46	57.00	घिराई
31.	कटवाला माइनर का 11.72 से 12.76 तक विस्तार और 0 से 6.600 कि०मी० तक का लाईनिंग कराना।	75.43	72.73	गोहाना
32.	तिहार सब माइनर का 0 से 2.32 कि०मी० तक निर्माण।	20.64	34.91	गोहाना
33.	कैरियर चैनल का आर०डी० 20196 तक जो कि दिल्ली पैरलल ब्रांच की बुर्जी 145250 से निकलेगी और खान पुर माइनर आर०डी० 0 से 12720 तक जोकि ईसराना डिस्ट्रीब्यूटरी की आर०डी० 88900 दाईं से निकलेगी का निर्माण।	258.00	140.00	गोहाना
34.	जे०एल० एन० रतनथल लिंक चैनल का निर्माण।	484.32	460.11	जाटूसाना
35.	पाहलावास डिस्ट्रीब्यूटरी का निर्माण।	150.01	71.00	जाटूसाना
36.	हांसावास माइनर का निर्माण।	111.62	38.84	जाटूसाना
37.	दुबलधन माइनर का जे०एल० एन० के साथ।	200.00	89.00	झज्जर

[श्री राम पाल माजरा]

क्रमांक	स्कीम का नाम	अनुमानित लागत (लाख रुपए में)	अब तक का खर्चा	हल्के का नाम
38.	रतनथल डिस्ट्रीब्यूटरी का निर्माण	154.02	234.02	झज्जर
39.	गुगाना माइनर का निर्माण।	82.13	41.67	झज्जर
40.	गुगाना सब माइनर का निर्माण।	41.08	38.36	झज्जर
41.	इन्ताज खुर्द माइनर का 0 से 1.28 कि०मी० का निर्माण।	34.07	23.17	जीन्द
42.	जीन्द डिस्ट्रीब्यूटरी नं० 4 का आर०डी० 80564 से आर०डी० 83570 तक विस्तार।	16.90	8.13	जीन्द
43.	शादीपुर माइनर।	173.34	173.42	जीन्द
44.	रामकली माइनर।	470.94	569.25	जीन्द
45.	बुआना सब माइनर।	91.44	91.44	जीन्द
46.	बारखेड़ा माइनर।	11.22	5.84	जीन्द
47.	बिरथाना माइनर का निर्माण।	98.07	95.07	जीन्द
48.	मन्जुला सब माइनर।	91.59	91.59	कैथल
49.	सिरसा ब्रांच की आर०डी० 218700 पर बचाव चैनल का निर्माण।	101.50	40.00	कैथल
50.	घुन्धेड़ी माइनर।	294.00	20.00	कैथल
51.	बुटाना डिस्ट्रीब्यूटरी का आर०डी० 93100 से 102600 तक का विस्तार।	34.30	34.30	कैथल
52.	श्यामपुरा माइनर का निर्माण।	101.94	39.00	लोहारू
53.	शेरापुर माइनर का निर्माण।	23.12	12.06	लोहारू
54.	बौन्द माइनर का विस्तार।	77.66	61.35	मुढ़ाल
55.	रानिला माइनर का निर्माण	44.37	34.91	मुढ़ाल
56.	कलुदा सब माइनर का आर०डी० 0 से 10000 तक निर्माण जोकि न्यू सन्घा खेड़ा की आर०डी०	96.98	155.10	बरवाना

क्रमांक	स्कीम का नाम	अनुमानित लागत (लाख रुपए में)	अब तक का खर्चा	हल्के का नाम
	37500 की दाईं छोर से निकलेगी और इसके साथ सन्चा खेड़ा माइनर को आर०डी० 0 से 37500 तक उठाना।			
57.	न्यू उरीना माइनर।	465.63	416.54	नौलथा
58.	पटोदा माइनर का निर्माण।	546.34	384.00	पटोदी/जाटूसाना
59.	भाना माइनर।	100.48	83.00	पाई
60.	फरेल माइनर।	256.54	50.00	पुन्डरी
61.	कलुआना माइनर का आर०डी० 0 से 24600 टेल तक का निर्माण जोकि राजस्थान फीडर के आर० डी० 556000 के बाईं छोर से निकलेगी।	212.70	35.43	रोड़ी
62.	बछेर नयोर का आर०डी० 0 से 30400 तक का निर्माण जोकि गुरुसन माइनर की ऐक्सटैनसन की आर०डी० 587190 की बाईं ओर की छोर से निकलेगी।	116.94	203.54	रोड़ी
63.	ओढ़ा माइनर का आर०डी० 31025 से 41685 टेल तक का विस्तार जो कि कलवाना डिस्ट्रीब्यूटरी की आर० डी० 61000 के बाईं ओर से निकलेगी।	87.48	64.21	रोड़ी
64.	सुखेड़ावाला माइनर की आर०डी० 0 से 2200 तक की क्षमता को बढ़ाना जिसकी निकासी आर०डी० 433835 की बाईं छोर की बी०एम० बी० से निकलेगी जोकि आशाखेड़ा माइनर की पूर्ति करेगी।	25.02	15.77	रोड़ी
65.	गंगोली सब माइनर का 0 से 1.61 कि०मी० तक का निर्माण जिसकी निकासी जीन्द डिस्ट्रीब्यूटरी नं० 3 की आर०डी० 19.72 की बाईं छोर से निकलेगी।	22.74	21.05	सफीदों

[श्री राम पाल माजरा]

क्रमांक	स्कीम का नाम	अनुमानित लागत (लाख रुपए में)	अब तक का खर्चा	हल्के का नाम
66.	कलावती माइनर का आर०डी० 0 से 1.576 तक का निर्माण जो कि जीन्द की 16.84 कि०मी० से निकलेगी।	20.56	34.69	सफीदों
67.	मुआना माइनर 0 से 421 कि०मी० का निर्माण जोकि पांजु माइनर पर 5.65 कि०मी० से निकलेगी पांजु माइनर का 8.812 से 10.08 तक का निर्माण व विस्तार, पांजु माइनर का 0 से 5.65 कि०मी० तक का उठान।	21.95	0	
68.	घग्गर सुखचैन लिंक चैनल का आर०डी० 0 से 6675 टेल तक का निर्माण जिसकी निकासी घग्गर नदी से होगी जोकि नैशनल हाई-वे के ए० आर० ब्रिज नं० 10 सिरसा डबवाली रोड पर है।	72.41	90.13	सिरसा
69.	चेतान माइनर का आर०डी० 0 से 21500 टेल तक का निर्माण जिसकी निकासी आर०डी० 35000 बाएं एफ०बी०डी० ब्रांच से निकलेगी।	100.62	150.88	तोशाम
70.	न्यू समैन माइनर का विस्तार।	27.21	7.00	गोहाना
71.	जैनावास माइनर का निर्माण।	341.65	107.00	तोशाम
72.	भेरा डिस्ट्रीब्यूटरी का विस्तार।	83.86	78.50	तोशाम
73.	नया गौरन पुरा और दरियापुर डिस्ट्रीब्यूटरी।	272.35	152.51	तोशाम
74.	पथेरवाली माइनर का उठान।	40.26	22.64	तोशाम
75.	ढगल माइनर का उठान।	18.69	8.28	तोशाम
76.	बरसोला फीडर का निर्माण।	426.74	362.25	उचाना

अध्यक्ष महोदय, स्वीकृत स्कीमें जो शुरू की जानी हैं वे इस प्रकार हैं :—

क्रमांक	स्कीम का नाम	कुल लागत	हल्के का नाम
1.	सीड फारम माइनर आर०डी० 0 से 7700 का निर्माण करना जोकि आर०डी० 54400 दाएं राना ड्रि० से निकलेगी।	151.06	हिसार
2.	गुराना माइनर आर०डी० 0 से 13000 का निर्माण जो बरवाला ब्रांच की आर०डी० 107925 से निकलती है।	100.15	नारनौंद
3.	लादुवास माइनर आर०डी० 0 से 4000 का निर्माण जोकि भाखड़ा मेन ब्रांच की आर०डी० 153200 दाएं से निकलती है	34.61	रतिया
4.	शेरावाली ड्रि० आर०डी० 0 से 187000 की क्षमता बढ़ाने हेतु।	435.51	दरबा/ऐलनाबाद
5.	मिठ्ठनपुरा माइनर आर०डी० 0 से 17500 का निर्माण जो कि शेरावाली समानान्तर चैनल की आर०डी० 81300 बाएं से निकलती है।	107.75	ऐलनाबाद
6.	दक्षिणी घग्गर नहर रबी मौसम के लिए और समानान्तर कच्ची नहर खरीफ मौसम के लिए आर०डी० 0 से 100380 का निर्माण जोकि चौधरी देवीलाल वीयर ओटू से निकलती है।	1368.34	ऐलनाबाद
7.	गुड़िया खेड़ा माइनर आर०डी० 0 से 42500 का निर्माण जो कि बरवाली ड्रि० की आर०डी० 51400 दाएं से निकलती है।	353.10	ऐलनाबाद
8.	कवरपुरा माइनर आर०डी० 0 से 7530 जो बनमदोरी ड्रि०आर०डी० 60000 दाएं से निकलती है	60.60	दरबा/ऐलनाबाद
9.	पिंगारा माइनर आर०डी० 0 से 27300 का निर्माण जो कि राजौन्द ड्रि०आर०डी० 20000 बाएं से निकलती है।	185.75	पुन्डरी
10.	गुलियाना माइनर आर०डी० 0 से 9300 तक का निर्माण जोकि जाखोली ड्रि० की	196.11	कलायत

[श्री राम पाल माजरा]

क्रमांक	स्कीम का नाम	कुल लागत	हल्के का नाम
	आर०डी० 79545 बाएं से निकलती है, जाखोली डि० की आर०डी० 0 से 14080 की बढ़ोतरी के साथ।		
11.	जल मल चैनल की आर०डी० 0 से 18000 तक का निर्माण जिला पानीपत में सिवरेज ट्रिटमैंट प्लाट सिवाह से जल मल उपचारिक जल लेकर उपलब्ध कराकर।	180.58	नौलथा
12.	जल मल चैनल आर०डी० 0 से 7500 तक का निर्माण जिला पानीपत में सिवरेज ट्रिटमैंट प्लाट बिन्झोल जल मल उपचारिक जल लेकर उपलब्ध कराकर।	41.97	पानीपत
13.	जल मल चैनल आर०डी० 0 से 25000 तक का निर्माण, सिवरेज ट्रिटमैंट प्लाट करनाल जौन के यमुना एक्शन प्लान से जल लेकर।	214.52	करनाल
14.	जोशी डि० आर०डी० 27200 से 36700 की बढ़ोतरी।	8.00	असन्ध
15.	सिवाहा माइनर कि०मी० से 2.01 का निर्माण जोकि जीन्द डि० नं० 4 के कि० मी० 10.45 से निकलती है।	32.53	जीन्द
16.	अफताबगढ़ सब माइनर आर०डी० 0 से 6660 तक का निर्माण जोकि पाजू माइनर की आर०डी० 12000 दाएं से निकलती है।	38.23	सफीदों
17.	कोहला डि० आर० डी० 0 से 101 का निर्माण जो कि बुटाना ब्रांच की आर० डी० 95000 बाएं से निकलती है।	101.81	बड़ोदा
18.	कालवा माइनर आर०डी० 0 से 2.13 कि०मी० का निर्माण जोकि जीन्द डि० नं० 3 कि०मी० 16.76 दाएं से निकलती है।	49.14	सफीदों
19.	2-आर बड़ोदा सब माइनर आर०डी० 0 से 4200 का निर्माण जोकि बड़ोदा माइनर 27900 दाएं से निकलती है।	79.76	बड़ोदा

क्रमांक	स्कीम का नाम	कुल लागत	हल्के का नाम
20.	जल मल चैनल कि०मी० 0 से 20.5 का निर्माण, सिवरेज ट्रिटमैंट प्लाट गुड़गांव जल मल लेकर।	721.7	गुड़गांव
21.	घोब माइनर आर०डी० 0 से 4600 तक का निर्माण जोकि बन्नीवाली माइनर की आर०डी० 6595 बाएं से निकलती है।	15.35	कलानौर
22.	मैना माइनर कि०मी० 0 से 1.52 तक का निर्माण जोकि दुलेहड़ा सब ब्रांच कि०मी० 0.18 दाएं से निकलती है।	22.48	हसनगढ़
23.	नई निगाना माइनर का आर०डी० 0 से 8192 का निर्माण जो कि भिवानी सब ब्रांच की आर० डी० 75000 से निकलती है।	41.87	कलानौर
24.	एस०एल०सी० सब माइनर आर०डी० 0 से 13785 का निर्माण जोकि जे० एल० एन० फीडर की आर०डी० 329131 बाएं से निकलती है।	77.14	कोसली
25.	भिवानी सब ब्रांच आर०डी० 0 से 107200 की क्षमता बढ़ाना जो कि बुटाना ब्रांच की आर० डी० 119810 से निकलती है।	182.00	मेहम/मुंढाल/ बवानी खेड़ा
26.	जसराना माइनर आर०डी० 0 से 66600 की लाईनिंग और क्षमता बढ़ाना जोकि भालौट सब ब्रांच की आर०डी० 86170 बाएं से निकलती है।	104.56	बहादुरगढ़
27.	पाकसमा माइनर आर०डी० 0 से 16000 का निर्माण जो कि आसन माइनर की आर०डी० 18000 दाएं से निकलती है।	149.10	कलोई
28.	भालौट ड्रि०आर०डी० 0 से 59125 की क्षमता बढ़ाना जो भालौट सब ब्रांच की आर०डी० 124000 से निकलती है।	69.71	रोहतक

[श्री राम पाल माजरा]

क्रमांक	स्कीम का नाम	कुल लागत	हल्के का नाम
29.	नया सिवाना माजरा माइनर आर०डी० 0 से 32250 का निर्माण जोकि सिवाना माजरा माइनर की आर०डी० 8000 दाएं से निकलती है।	156.00	बेरी
30.	सुन्दर ड्रि० 0 से 86815 की क्षमता बढ़ाना	256.76	मुंढाल, बवानी खेड़ा, तोशाम, हांसी
31.	दादरी फीडर आर०डी० 0 से 42700 की क्षमता बढ़ाना और दादरी ड्रि० आर०डी० 0 से 11000 की क्षमता बढ़ाना	344.67	मेहम/मुंढाल भिवानी, कलानौर
32.	आजाद नगर सब माइनर आर०डी० 0 से 9290 का निर्माण जोकि पत्थेर वाली माइनर की आर० डी० 31400 दाएं से निकलती है।	37.42	तोशाम

अध्यक्ष महोदय, जो स्कीमें प्रगति पर हैं वे इस प्रकार हैं :—

क्रमांक	स्कीम का नाम	अनुमानित लागत (लाख रुपए में)	अब तक का खर्चा	हल्के का नाम
1.	कसावा माइनर का आर० डी० 0 से 39600 तक निर्माण करना जोकि ओटू लेक से निकलेगी	349.20	140.00	ऐलनाबाद
2.	बान्डाहड़ी सब माइनर का आर०डी० 0 से 7100 तक निर्माण करना जो कि चौधरी वास माइनर की आर०डी० 69000 बाएं से निकलेगी	89.15	8.00	आदमपुर
3.	कुरीयान माइनर का आर०डी० 21700 से 38130 तक विस्तार	133.50	0.00	असन्ध
4.	खुवजा नगर माइनर का आर०डी० 0 से 8800 तक निर्माण जो कि गोकुल ड्रि० की आर०डी० 16950 बाएं से निकलेगी।	100.05	31.00	बाधरा
5.	छारा सब माइनर का निर्माण।	99.36	83.70	बादली

क्रमांक	स्कीम का नाम	अनुमानित लागत (लाख रुपए में)	अब तक का खर्चा	हल्के का नाम
6.	1-आर नूना माजरा का आर० डी० 4500 से टेल आर०डी० 16000 तक विस्तार जो कि आर०डी० 7000 दाएं नूना माजरा से निकलेगी।	11.69	35.36	बहादुरगढ़
7.	न्यू बड़ोदा सब माइनर का आर०डी० 0 से 9000 तक निर्माण जोकि बुटाना डिस्ट्रीब्यूटरी की आर०डी० 41650 से निकलेगी व 1-आर बड़ोदा सब माइनर का आर०डी० 0 से 6950 जोकि बड़ोदा सब माइनर की आर०डी० 4350 दायें से निकलेगी।	102.13	27.25	बड़ोदा
8.	खन्डारी माइनर का निर्माण।	11.80	5.76	बड़ोदा
9.	चिरोद माइनर का विस्तार।	112.41	25.00	बवानी खेड़ा
10.	देवसर व रूपाना पम्प हाउस की क्षमता बढ़ाना।	29.59	22.00	बवानी खेड़ा
11.	सिवानी कनाल सिस्टम के पम्प हाउस 1 से 5 की क्षमता बढ़ाना	318.88	24.00	भिवानी
12.	निगाना कैनाल सिस्टम पम्प हाउस 1 से 2 की क्षमता बढ़ाना।	108.96	31.40	भिवानी
13.	गुजरानी माइनर के आर०डी० 28000 की पम्प हाउस की क्षमता बढ़ाना।	45.40	6.10	भिवानी
10-00 बजे				
14.	जुई कैनाल सिस्टम की पम्प हाउस 1 से 7 की क्षमता बढ़ाना।	99.79	41.33	भिवानी
15.	धाराडु माइनर	176.56	6.72	भिवानी/मुंढाल
16.	खिजरी बागपत माइनर का आर०डी० 0 से 10500 तक	205.37	0.00	छछरौली

[श्री राम पाल माजरा]

क्रमांक	स्कीम का नाम	अनुमानित लागत (लाख रुपए में)	अब तक का खर्चा	हल्के का नाम
	का निर्माण जोकि डब्लू लिंक चैनल से निकलेगी।			
17.	मनका वास माइनर का निर्माण	96.64	14.31	दादरी
18.	खेड़ी सनवाल माइनर का आर० डी० 13929 से 20530 तक निर्माण और आर०डी० 0 से 13929 से उठान	63.00	0.00	दादरी
19.	कमोद माइनर का निर्माण	176.46	139.54	दादरी
20.	बरसाना माइनर का निर्माण	71.11	0.90	दादरी
21.	गोगोरानी डिस्ट्रीब्यूटरी का 17.32 कि०मी० से 29.42 तक निर्माण व विस्तार जोकि फतेहाबाद ब्रांच की आर०डी० 265068 बाएं से निकलेगी।	235.50	236.64	दड़बा
22.	मानावाली माइनर का आर०डी० 16350 से 28150 तक विस्तार व उठान और इसका आर०डी० 40800 तक विस्तार जोकि आर०डी० 25409 बाएं सिरसा मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी से निकलेगी।	124.06	32.20	दड़बा
23.	चैहलवाला माइनर, रामपुरा, बागड़िया आर०डी० 0 से 23500 तक का निर्माण जोकि खेड़ी ड्रि० की आर०डी० 103400 दाएं से निकलेगी।	178.94	59.60	दड़बा
24.	मगला माइनर जो आर०डी० 161000 से 258000 तक जो ओटू लेक से निकलती है का विस्तार।	24.34	47.13	ऐलनाबाद
25.	सिकरोना ड्रि० आर०डी० 8500 से 21700 तक का विस्तार	37.27	55.48	फरीदाबाद
26.	धमन सब माइनर आर०डी० 0 से 20000 तक का जो धमन ड्रि० की आर०डी 15200 बाएं से निकलती है का निर्माण।	73.28	40.00	फतेहाबाद

क्रमांक	स्कीम का नाम	अनुमानित लागत (लाख रुपए में)	अब तक का खर्चा	हल्के का नाम
27.	सरघटल माइनर की आर०डी० 0 से 16633 को पक्का करना।	141.60	13.45	गोहाना
28.	नई मोई हुड्डा माइनर की आर० डी० 0 से 11133 का निर्माण जो जे०एल०एन० फीडर 70500 से निकलेगी।	64.15	12.75	गोहाना
29.	दीपल सब माइनर की आर०डी० 0 से 25500 तक का निर्माण जो दीपल माइनर की आर०डी०, 9800 बाएं से निकलेगी।	218.52	62.00	हांसी
30.	1-आर सिसर माइनर आर०डी० 0 से 15400 तक का निर्माण जो सुन्दर सब ब्रांच की आर०डी० 174875 दाएं से निकलेगी।	94.11	50.01	हांसी
31.	क्रोंधा सब माइनर की आर०डी० 0 से 1.92 कि०मी० तक का निर्माण जो जे०एस० ब्रांच की आर०डी० 9.66 कि०मी० बाएं से निकलेगी।	28.43	18.67	हसनगढ़
32.	गुराना सब माइनर का निर्माण	39.44	22.69	झज्जर
33.	पडाना सब माइनर की आर०डी० 0 से 11000 तक का निर्माण जो रामकली माइनर की आर० डी०15500 दाएं से निकलेगी।	48.86	23.36	जीन्द
34.	जीन्द डिस्ट्रीब्यूटरी नं० 7 को सीधा करना जो हांसी ब्रांच कि०मी० 61.12 बाएं से निकलती है और कि०मी० 6.49 के साथ जोड़ना।	120.52	31.46	जीन्द
35.	सुन्दर पुर माइनर की आर०डी० 0 से 1.71 तक का निर्माण जो जीन्द डिस्ट्रीब्यूटरी नं० 4 के कि०मी० 17.60 बाएं से निकलेगी।	26.81	16.51	जीन्द

[श्री राम पाल माजरा]

क्रमांक	स्कीम का नाम	अनुमानित लागत (लाख रुपए में)	अब तक का खर्चा	हल्के का नाम
36.	बरसोकरी माइनर को बढ़ाना	61.51	30.83	कलायत
37.	1-आर मोखरा माइनर (नई) की कि०मी० 0 से 15000 तक का निर्माण जो आर०डी० 106089 दाएं मोखरा माइनर से निकलेगी।	125.01	0.00	महम
38.	नई मोखरा माइनर की आर०डी० 0 से 11500 बाएं तक का निर्माण जो दादरी फीडर की आर०डी० 13000 बाएं से निकलेगी।	138.78	45.00	महम/कलानौर
39.	फोगाट माइनर।	24.17	7.57	मुंढाल
40.	थानी हरी सिंह माइनर का निर्माण जो जुई फीडर की आर०डी० 96700 बाएं से निकलेगी।	92.39	0.00	मुंढाल
41.	नई मुंढाल माइनर की आर०डी० 0 से 9000 तक का निर्माण जो मिठाथल फीडर की आर०डी० 47200 दाएं से निकलेगी और मुंढाल माइनर को कम करना।	85.67	25.00	मुंढाल/हांसी
42.	नरवाना माइनर की आर०डी० 39000 से 52000 तक को बढ़ाना।	223.09	76.53	नरवाना
43.	कलवान सब माइनर की आर० डी० 0 से 5500 तक का निर्माण जो धमतान डिस्ट्रीब्यूटरी की आर० डी० 126000 दाएं से निकलेगी।	61.46	16.60	नरवाना
44.	नई बलाना माइनर का निर्माण	196.52	40.00	नौलथा
45.	बिजावा माइनर 5047 से 8.03 कि०मी० तक को बढ़ाना	53.08	15.00	नौलथा
46.	खेड़ी सेरू माइनर की कि०मी० 0 से 7.44 तक का निर्माण जो	256.34	108.54	पाई

क्रमांक	स्कीम का नाम	अनुमानित लागत (लाख रुपए में)	अब तक का खर्चा	हल्के का नाम
	तिगराम डिस्ट्रीब्यूटरी की कि०मी० 5.30 बाएं से निकलेगी।			
47.	राजोलका माइनर का निर्माण	110.00	45.61	पलवल
48.	सचोला माइनर का निर्माण आर०डी० 0 से 8000	46.02	24.30	पटौदी
49.	पउलदबाद माइनर का निर्माण	357.90	170.40	पटौदी
50.	शेरपुर माइनर का निर्माण	215.52	98.81	पटौदी
51.	मुजफरा माइनर का निर्माण	279.32	117.76	पटौदी
52.	फरीदपुर माइनर का निर्माण	59.98	26.46	पटौदी
53.	पटौदी डिस्ट्रीब्यूटरी का निर्माण	834.50	848.64	पटौदी/जाटूसाना
54.	लोहारी माइनर का निर्माण	544.08	270.15	पटौदी
55.	खेड़ा माइनर का निर्माण	61.90	64.35	पटौदी
56.	छेतुपुर डिस्ट्रीब्यूटरी की आर० डी०76550 से 82300 तक को बढ़ाना।	30.20	14.00	रोड़ी
57.	सहीदावाली माइनर धीन्दतानियां, चौबरजा की आर०डी० 0 से 19000 तक का निर्माण जो शेरनवाली ड्रि० की आर०डी० 65638 दाएं से निकलती है।	105.39	92.27	रोड़ी
58.	घग्गर,बन्नी और सदेवा मम्मरेखा लिंक चैनल की आर०डी० 0 से 76000 तक का निर्माण जो घग्गर रिवर की आर०डी० 29500 दाएं से निकलती है।	493.81	195.00	रोड़ी
59.	सिवाना मल ड्रि० की आर०डी० 0 से 39000 तक का निर्माण जो बुटाना ब्रांच की आर०डी० 56500 दाएं से निकलती है।	512.18	107.13	सफीदों

[श्री राम पाल माजरा]

क्रमांक	स्कीम का नाम	अनुमानित लागत (लाख रुपए में)	अब तक का खर्चा	हल्के का नाम
60.	राम नगर सब माइनर की आर०डी० 0 से 8500 तक का निर्माण जो रोजला माइनर की आर०डी० 22165 बाएं से निकलती है।	71.35	25.21	सफीदों
61.	मोरथी माइनर 0 से 7.53 कि०मी० तक को पक्का करना	135.18	12.37	सफीदों
62.	लडमकी माइनर की आर०डी० 9440 से 14360 तक को बढ़ाना।	47.66	22.49	तावडू
63.	नई सागवान माइनर का निर्माण।	188.32	81.48	तोशाम
64.	गारनपुरा बास लिंक, बी०एल० फीडर की क्षमता को बढ़ाना।	426.74	598.00	तोशाम
65.	माहु ड्रि० की बढ़ोतरी।	53.16	0.00	तोशाम
66.	निगाना कैनाल रेजरवायर।	46.01	0.00	तोशाम
67.	निगाना कैनाल रेजरवायर	291.90	175.42	तोशाम
68.	महेन्द्रगढ़ कैनाल सिस्टम की क्षमता बढ़ाना	209.90	0.00	—
69.	जे०एल०एन० कैनाल सिस्टम की क्षमता बढ़ाना	272.00	39.07	—
70.	लोहारू कैनाल और बधवाना ड्रि० की क्षमता को बढ़ाना।	427.00	122.77	—

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि क्वैश्चन आवर में इतना लम्बा रिप्लाई पढ़ा जाये। (विघ्न)

श्री जगजीत सिंह : अध्यक्ष महोदय, क्वैश्चन आवर में इतना लम्बा रिप्लाई नहीं होना चाहिए। (विघ्न)

कैप्टन अजय सिंह यादव: स्पीकर सर, क्वैश्चन आवर का मजाक बना रखा है कि इतना बड़ा उत्तर दे रहे हैं। (विघ्न)

श्री राम पाल माजरा : स्पीकर सर, सिवानी माइनर पर एक करोड़ 56 लाख रुपये.....
(विघ्न)

श्री अध्यक्ष : आप तीनों एक साथ क्यों खड़े हुए हैं आप बैठ जायें।

श्री राम पाल माजरा : स्पीकर सर, सिवानी माइनर पर एक करोड़ 56 लाख रुपये खर्च किया गया है। तोशाम और दादरी फीडर की क्षमता बढ़ाई है। **(विघ्न)** स्पीकर सर, चाहे कोई बिजली का मामला हो, चाहे नहरों का मामला हो जब रिप्लाई लम्बा दिया जाता है तो ये शोर मचाते हैं कि इतना बड़ा रिप्लाई है और जब छोटा जवाब दिया जाता है तो ये संतुष्ट नहीं होते। **(विघ्न)**

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : मंत्री जी ने पूरा ब्यौरा दिया है। (शोर)

श्री अध्यक्ष : हुड्डा साहब, पहले आप तीनों को बिठाएं ये तीनों डिप्टी खड़े हैं आपका भी लिहाज नहीं करते। (शोर)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, एक तो मैंने सुझाव दिया था मेरे ख्याल से सरकार उस पर अमल करेगी।

श्री अध्यक्ष : हुड्डा साहब आप सवाल पूछें। (शोर)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने पूरा ब्यौरा दिया है। दादूपुर इन्द्री की भी चर्चा आई कि ये आगर्मैंट कर रहे हैं। दादूपुर से नलवी तक एक माइनर बनाने की योजना बनी थी, उसके लिए बहुत साल पहले जमीन एक्वायर हो गई थी। उसका क्या फेट है, वह योजना कहां अटकी हुई है वह नहर बनाना सरकार के विचाराधीन है या नहीं?

श्री राम पाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने माननीय साथी को बताना चाहूँगा कि उसके लिए एस्टिमेट टैक्नीकल एडवाइजरी कमेटी में जायेंगे, फिर पास होंगे, उसके बाद प्रशासनिक स्वीकृति मिलेगी और फिर उस पर विचार करेंगे और फिर बनायेंगे। आपने तो उसे ठण्डे बस्ते में डाल दिया था। (शोर)

वाक-आउट्स

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, माजरा जी इस सवाल की बहुत लैंग्थी रिप्लाई दे रहे हैं, इनको टू दि प्वायंट जवाब देना चाहिए। चूंकि ये लैंग्थी रिप्लाई दे रहे हैं और हमें सप्लीमैंटरी का मौका नहीं मिल रहा है इसलिए मैं एज ए प्रोटैस्ट सदन से वाक-आउट करता हूँ। (शोर)

चौ० जगजीत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं भी दलाल साहब की बात से सहमत हूँ और मैं भी इनके साथ एज ए प्रोटैस्ट सदन से वाक-आउट करता हूँ। **(इस समय माननीय सदस्य श्री कर्ण सिंह दलाल और श्री जगजीत सिंह सांगवान सदन से वाक-आउट कर गए)**

श्री अध्यक्ष : आप हाउस में सिनसियर नहीं हैं खबरें बनवाने के चक्कर में हैं। विघ्न डालने वालों को बाहर चले जाना चाहिए ताकि हाउस सुचारू रूप से चल सके। (शोर)

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)

श्री राजेन्द्र सिंह बिसला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान अपने विधान सभा क्षेत्र बल्लभगढ़ की ओर आकर्षित करवाना चाहूँगा कि वहां प्रैसटिजियस माइनर है

[श्री राजेन्द्र सिंह बिसला]

छांयसा डिस्ट्रीब्यूटरी। वह लिफ्ट इरीगेशन चैनल है। उस पर साढ़े पांच करोड़ रुपए के करीब खर्च हुआ है, उसके सारे पम्प हाउस वगैरह नये बनाए गए हैं उसकी टेल जो मेरे विधानसभा क्षेत्र बल्लभगढ़ में है वहां आज तक पानी नहीं पहुंचा है। जब उसको चलाने का प्रयास करते हैं तो बीच में कुछ ऐसा पोरशन है जहां उसकी लाइनिंग पर सब स्टैंडर्ड मैटीरियल यूज हुआ है जिससे लीकेज हो जाती है। मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि वे सैशन के बाद उच्च अधिकारियों के साथ वहां आएं। हम भी साथ होंगे और कोई ऐसा प्रबन्ध किया जाये कि उस चैनल का पानी टेल तक पहुंचे। क्या आदरणीय माजरा साहब वहां चलेंगे और उसके पानी को टेल तक पहुंचवाने की कृपा करेंगे।

मुख्य संसदीय सचिव (श्री राम पाल माजरा) : अध्यक्ष महोदय, जब आम जनता की बात सुनने के लिए हरियाणा के मुख्य मंत्री गांव-गांव में जा सकते हैं तो एक प्रतिष्ठित विधायक के कहने पर हम वहां नहीं जा सकते, ऐसी बात नहीं है। हम अवश्य ही वहां जायेंगे और जो घटिया क्वालिटी का मैटीरियल यूज होने की वजह से लीकेज वाली बात है, हम उसकी जांच करवायेंगे और जो व्यक्ति दोषी पाये जायेंगे उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे। उस चैनल का टेल तक जरूर पानी पहुंचायेंगे।

चौ० नफे सिंह राठी : अध्यक्ष महोदय, मेरी सप्लीमैंटरी अधूरी रह गई इसलिए मैं आपके माध्यम से सी०पी०एस० महोदय से जानना चाहता हूँ कि जो नई माइनर्ज हैं, सब माइनर्ज हैं, डिस्ट्रीब्यूट्रीज बननी हैं या माइनर्ज की कैपेसिटी बढ़ानी है उनकी सूची बताएं कि कौन-कौन सी हैं।

श्री राम पाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार के मुख्य मंत्री जी "सरकार आपके द्वार" कार्यक्रम में गए, लोगों ने अपनी मांग रखी तथा दरखास्तें दीं उनको एग्जामिन कर लिया गया है, मैंने सूची पढ़ दी है, बता दिया है और अवगत करवा दिया है। फिर भी किसी की कोई माइनर, डिस्ट्रीब्यूटरी रह गई हो तो वह दरखास्त दे दें हम उसको टैक्नीकली एग्जामिन करवाएंगे और वायबल होगा तो जरुर बनवायेंगे।

Construction of Mini Secretariat, Panipat

***1474. Sh. Krishan Lal :** Will the Minister for Revenue be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct the Mini Secretariat at Panipat ; if so, the time by which it is likely to be constructed ?

नगर एवं ग्राम आयोजना मंत्री (श्री धीर पाल सिंह) : जी हां। जैसे अम्बाला छावनी के नजदीक अभिगृहित की गई 181 एकड़ 1 कनाल 6 मरला भूमि के बदले में पानीपत की कैम्पिंग ग्राऊंड की 66.565 एकड़ भूमि रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्थानान्तरित की जाती है तथा इसका कब्जा राज्य सरकार को सौंपा जाता है, तथा बाकी औपचारिकताएं पूरी हो जाती हैं, पानीपत में लघु सचिवालय के निर्माण का कार्य आरम्भ कर दिया जायेगा।

श्री कृष्ण लाल : स्पीकर सर, जैसा कि मंत्री जी ने अपने जवाब में बताया है कि डिफैंस मिनिस्टरी से जमीन स्टेट गवर्नमैंट के नाम ट्रांस्फर होने के बाद लघु सचिवालय का कार्य शुरू कर दिया जायेगा। इस बारे में मैं मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि क्या पानीपत में लघु सचिवालय बनवाने के लिए इस वर्ष के बजट में पैसे का प्रावधान किया गया है। दूसरा मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूँगा कि क्या पानीपत में नये सत्र में न्यायालय की स्थापना करने का कोई मामला सरकार के विचाराधीन है और यदि है तो उसका ब्यौरा बताया जाये।

श्री धीरपाल सिंह : स्पीकर सर, जैसा कि मैंने अपना जवाब दिया है कि जैसे ही भूमि की अदला-बदली हो जायेगी यानि स्टेट गवर्नमेंट के नाम जमीन ट्रांस्फर हो जायेगी तो लघु सचिवालय का कार्य शुरू कर दिया जायेगा। जहां तक मेरे माननीय साथी ने दूसरा सवाल किया है इस बारे में मैं इनको बताना चाहूँगा कि यह प्रश्न हमारे से संबंधित नहीं है।

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी, पंवार साहब हाईकोर्ट के जस्टिस से परस्यू करके डिस्ट्रिक्ट जज वहां लाने की बात कर रहे हैं।

श्री धीरपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने बताया यह मामला रेवेन्यू विभाग से संबंधित नहीं है।

श्री भगवान सहाय रावत : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जिला स्तर पर पानीपत में लघु सचिवालय बनाने के बारे में प्रश्न पर चर्चा चल रही है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि कौन-कौन से जिलों में लघु सचिवालय बन गये हैं और कहां-कहां बनाने का विचार है। इसके अतिरिक्त मैं यह भी पूछना चाहूँगा कि क्या जिलों के बाद सब-डिविजन लैवल पर भी लघु सचिवालय बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है और यदि है तो उसकी क्या पोजीशन है? उनमें से कितने बन चुके हैं तथा कितने और बनाये जायेंगे?

श्री धीरपाल सिंह : स्पीकर सर, जहां तक सब-डिविजन लैवल पर लघु सचिवालय बनाने की बात है, इस बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसी महान सदन में घोषणा की है कि जिला स्तर पर लघु सचिवालय बनाने के बाद सभी सब-डिविजन लैवल पर लघु सचिवालय बनाने की योजना सरकार ने बनाई है। जहां तक जिलों में लघु सचिवालय बनाने की बात है, इस बारे में मैं मेरे माननीय साथी को बताना चाहूँगा कि लघु सचिवालय सभी जिलों में बनायें जायेंगे। 13 जिलों में लघु सचिवालय के परिसरों का निर्माण हो चुका है और बाकी की जगह निर्माण कार्य प्रगति पर है। अम्बाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, सोनीपत, रोहतक, भिवानी, हिसार, नारनौल, रिवाड़ी, यमुनानगर, कैथल, पंचकूला और फतेहाबाद जिलों में लघु सचिवालय बन चुके हैं। इसके अतिरिक्त झज्जर और सिरसा में परिसर का काम पूरा होने वाला है। इसके अतिरिक्त गुड़गांव, फरीदाबाद और जीन्द में भी लघु सचिवालय के परिसरों का काम शुरू हो चुका है।

Improvement in Power Supply

***1341 Shri Jasbir Mallour :** Will the Chief Minister be pleased to state the steps taken or proposed to be taken to improve the quality of power supply in Ambala District ; if so, the details thereof ?

मुख्य संसदीय सचिव (श्री राम पाल माजरा) : जिला अम्बाला में बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए एक वृहद योजना क्रियान्वयन के अन्तर्गत है जिसमें टेपला में एक नया 220 के०वी० उपकेन्द्र, भुलाना तथा दुखेड़ी में 2 नये 66 के०वी० उपकेन्द्रों का निर्माण करना शामिल है। ये सभी कार्य प्रगति की अग्रिम अवस्था में हैं तथा ये जून 2003 तक चालू होने संभावित हैं।

इसके अतिरिक्त 33 के०वी० उपकेन्द्र अम्बाला कैन्ट की क्षमता में वृद्धि की जा चुकी है। वर्ष 2003-04 के दौरान बरनाला तथा चौड़मस्तपुर में 66 के०वी० उपकेन्द्रों की क्षमता में वृद्धि करने का

[श्री राम पाल माजरा]
तथा वर्ष 2004–2005 के दौरान सौन्डा में एक नये 66 के०वी० उपकेन्द्र का निर्माण करने का भी प्रस्ताव है।

11 नं० 11 के०वी० फीडरों का पुनर्वास/द्विभाजन का कार्य भी पूर्ण किया जा चुका है। 14 नं० 11 के०वी० फीडरों का द्विभाजन का कार्य प्रगति में है।

उपरोक्त कार्यों में 44.96 करोड़ रुपए का कुल निवेश होगा।

श्री जसबीर मलौर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूँगा और हरियाणा सरकार का धन्यवाद करना चाहूँगा कि अम्बाला जिले में जो बिजली की बुरी हालत थी उसके सुधार के लिए हरियाणा सरकार ने लगभग 45 करोड़ रुपये और लगाने का फैसला किया है। इसके लिए अम्बाला जिले की तमाम जनता की तरफ से मैं सरकार का धन्यवादी हूँ। अध्यक्ष महोदय, मेरे अपने हल्के की एक बहुत बड़ी समस्या है। मेरे हल्के के दुराना गांव में पिछले दिनों माननीय मुख्य मंत्री जी गए थे तो उस समय लोगों की तरफ से एक मांग रखी गई थी कि वहां पर 66 के०वी० का सब–स्टेशन बनाया जाये और बिजली बोर्ड के अधिकारी भी वहां पर मौका देख चुके हैं और गांव की पंचायत ने भी जमीन देने का रैजोल्यूशन पास करके डिपार्टमैंट को दे दिया है। क्या मंत्री महोदय, आश्वासन देंगे कि दुराना गांव में 66 के०वी० का सब स्टेशन जल्दी बनायेंगे?

श्री राम पाल माजरा : स्पीकर साहब, किसी भी जगह पर सब–स्टेशन बनाये जाने से पहले उसकी वायबिलिटी का पता किया जाता है। अगर उससे पहले का जो सब–स्टेशन उन गांवों के साथ लगता हुआ ओवरलोडिड है जिसकी वजह से वोल्टेज कम मिल रही है, उस इलाके की जहां से मांग आ रही है यानि वोल्टेज कम मिल रही है, किसानों को डिम बिजली या पूरी फ्रीक्वैंसी की नहीं मिलती तो फिर दरखास्तें आती हैं, फिर सर्वे करवाते हैं उसके बाद वायबिलिटी को ध्यान में रखते हुए नया सब–स्टेशन बनाने पर विचार किया जाता है। जो मलौर साहब ने कहा है, उसको हम एग्जामिन करवाएंगे और इसका पहले सर्वे करवाया जा रहा है।

तारांकित प्रश्न सं० 1294

(यह सवाल पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य श्री रमेश राणा सदन में उपस्थित नहीं थे)

Controlling of Pollution in Faridabad

***1378 Sh. Rajender Singh Bisla :** Will the Chief Minister be pleased to state the details of the steps taken or proposed to be taken to check the water, air and sound pollution in the Faridabad as per direction of the Hon'ble High Court/Supreme Court ?

मुख्य संसदीय सचिव (श्री राम पाल माजरा) : माननीय सर्वोच्च न्यायालय की हिदायतों के अनुसार फरीदाबाद में जल, वायु और ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण करने बारे कई कदम उठाये हैं जिसका विवरण अनुबन्ध 'अ' में दर्शाया गया है।

अनुबन्ध 'अ'

क्रमांक	याचिका नं०	सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय द्वारा दी गई हिदायतें	कार्यवाही की गई
जल प्रदूषण			
1.	पी०आई०एल० 725/1994 सर्वोच्च न्यायालय में।	माननीय सर्वोच्च न्यायालय, भारत सरकार के आदेशानुसार जो औद्योगिक इकाइयां फरीदाबाद में हैं और अपना रिसाव सीधे तौर पर/असीधे तौर पर (जिनका रिसाव 5 किलो लिटर और ज्यादा) यमुना नदी में कर रहे हैं उन्हें जल शोधक संयंत्र लगाना चाहिए और मानकों को अपनाना चाहिए।	सभी सम्बन्धित इकाइयां,जो बन्द कर दी गयी हैं, उन्हें छोड़ कर शेष सभी ने जल शोधक संयंत्र लगा लिये हैं और उसकी मोनिटरिंग सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की जा रही है।
2.	याचिका नं० 97/ 1997 उच्च न्यायालय हरियाणा और पंजाब में।	माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने निर्णय लिया है कि फरीदाबाद कस्बे की सभी औद्योगिक इकाइयां इस याचिका के अन्तर्गत आती हैं और उन्हें जल प्रदूषण संशोधक संयंत्र लगाने चाहिएं।	उपरोक्त सभी औद्योगिक इकाइयां जो इस याचिका के अन्तर्गत आती हैं, उन सभी इकाइयों ने जल शोधक संयंत्र लगा लिए हैं और इसी आधार पर ये याचिका माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 24-7-2002 द्वारा खारिज की जा चुकी है।
वायु प्रदूषण			
1.	याचिका नं० 13029 माननीय सर्वोच्च न्यायालय, भारत सरकार	फरीदाबाद कस्बे के लिए एम्बिएंट वायु प्रदूषण रोकथाम का एक्शन प्लान तैयार करना।	ऐक्शन प्लान तैयार किया गया तथा इसे पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भेज दिया है।

[श्री रामपाल माजरा]

क्रमांक	याचिका नं०	सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय द्वारा दी गई हिदायतें	कार्यवाही की गई
2.	याचिका नं० 97/ 1997 उच्च न्यायालय हरियाणा और पंजाब में।	माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेशानुसार फरीदाबाद कस्बे में स्थित सभी इकाइयां जो इस याचिका के अन्तर्गत हैं, को वायु संशोधक संयंत्र लगाने चाहिएं।	उपरोक्त सभी औद्योगिक इकाइयां जो इस याचिका के अन्तर्गत आती हैं, उन सभी इकाइयों ने वायु शोधक संयंत्र लगा लिए हैं और इसी आधार पर ये याचिका माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 24-07-2002 द्वारा खारिज की जा चुकी है।
ध्वनि प्रदूषण			
1.	याचिका नं० 2543/2003 माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय।	इस केस की सुनवाई 12-03-2003 को होनी है।	इस याचिका के आदेशानुसार मैसर्ज ए०पी० फोरजिंग, मथुरा रोड, फरीदाबाद को 28-2-2003 को बंद करने के आदेश जारी कर दिये हैं।

श्री राजेन्द्र सिंह बिसला : अध्यक्ष महोदय, फरीदाबाद उत्तरी भारत का अति महत्वपूर्ण शहर है और मैंने अपने प्रश्न में पूछा है कि जल, वायु और ध्वनि प्रदूषण की वहां पर बहुत बड़ी समस्या है और एक चुनौती है। बदरपुर से लेकर नगर निगम का झाड़सेतली बोर्डर तक का जो एरिया पड़ता है उस बारे में मैं मंत्री जी को बताना चाहूँगा कि अगर उस रास्ते से कार के शीशे खोलकर जाएं तो उसमें इतना एयर पोल्यूशन है और इतना ध्वनि पोल्यूशन है कि अगर उसका मैडिकल चैकअप करवाएं तो डॉक्टर लिखेंगे कि यह आदमी बीमार है। स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से आदरणीय माजरा जी से निवेदन करूंगा कि इस समस्या के समाधान हेतु बड़ी गम्भीरता के साथ विचार करें यानि इसको बड़ी गम्भीरता से लेना चाहिए। जैसे वहां पर जी०टी० रोड जो जाता है उस में दिल्ली से कई हजार आटो बैन कर दिए हैं और वे लोग वहां पर आ गए हैं जिस कारण वहां पर बहुत शोर एवं पोल्यूशन है और प्रशासन उसको रोक नहीं पा रहा। मैं निवेदन करूंगा कि इस समस्या के समाधान के लिए कुछ करें। दूसरा मैं निवेदन करूंगा कि पोल्यूशन की रोकथाम के बारे में जो केस सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट में पड़े हैं उससे समस्या का समाधान नहीं है। मैं चाहता हूँ कि इसका ऐक्शन प्लान तैयार कराएं। केवल मात्र सदन को सूचना देना कि हमने केस सुप्रीम कोर्ट में भेज दिया है, ठीक नहीं है। इस समस्या का एडमिनिस्ट्रेटिव स्तर पर और युद्ध स्तर पर समाधान होना चाहिए, क्या माजरा साहब जी इस बारे में आश्वासन देंगे।

श्री राम पाल माजरा : स्पीकर साहब, मैं माननीय साथी को बताना चाहूँगा कि कोर्ट के आदेशानुसार जो 183 यूनिट थे यानि जो औद्योगिक इकाइयां थीं, जो प्रदूषण फैलाती थीं उनको ट्रीटमैंट प्लांट लगाने थे उनमें से 171 ने अपने ट्रीटमैंट प्लांट लगा लिए हैं और 12 ऐसी इकाइयां हैं जो आलरेडी क्लोजड हैं। यह तो कोर्ट के आदेश की बात है। जो बात मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार ने कोर्ट के आदेश की पालना करते हुए ऐक्शन प्लान बना करके वह सुप्रीम कोर्ट को देना है वह दे दिया है। इसको सुप्रीम कोर्ट समय-समय पर अपने स्तर पर मोनेटरिंग करता रहता है। सरकार की तरफ से जो किया जा सकता है वे कदम सरकार की तरफ से उठाए गए हैं और इस मामले में सरकार वैरीमच कनसर्न है। श्री व्हीलरज के बारे में उन्होंने जिक्र किया है 15 साल के बाद दिल्ली में रजिस्ट्रेशन न होने के कारण वे हमारे प्रदेश में आ जाते हैं। हमने वहां पर कलर कोडिंग करने का प्रावधान किया हुआ है। पांच साल तक हरा, पांच से 10 साल तक नारंगी और 10 से 15 साल तक का लाल रंग करके उनको आल्टरनेटिव डेज पर चलाने का आदेश जारी कर दिया है। वहां के डी०सी० ने आदेश जारी किए हुए हैं कि नम्बर एक जो आज चलेंगे वे कल नहीं चलेंगे और कल केवल दो नम्बर वाले ही चलेंगे जिससे डैन्सिटी ऑफ व्हीकल्ज कम रहेगी। स्पीकर सर, इसी प्रकार से उन पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है कि उनमें से 50% ही एक दिन में चल सकेंगे और बाकी के दूसरे दिन चलेंगे। यह जो सुझाव थे इनके मुताबिक ही हमने गवर्नमैंट ऑफ इण्डिया को तथा सुप्रीमकोर्ट को भी भेजे हुए हैं। इसके साथ ही पोल्यूशन कण्ट्रोल बोर्ड हरियाणा ने पोल्यूशन की रोकथाम के बारे में अपनी राय दी है और भारत सरकार से अभी सुझाव अपेक्षित हैं। (विघ्न)

श्री राजेन्द्र सिंह बिसला : अध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सी०एन०जी० लागू होना चाहिए। (विघ्न)

श्री राम पाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, फिर भी सरकार ने कदम उठाते हुए यह भी रिकमैंड किया था कि जो रजिस्ट्रेशन होंगी भार-1 की की जाएंगी। भार-1 की रजिस्ट्रेशन ही अब फरीदाबाद में होंगी इस क्षेत्र में यह भी था कि जो बसिज चलती हैं और पैसेंजर्ज को कैरी करती हैं उनकी आयु

[श्री राम पाल माजरा]

सीमा सात वर्ष कर दी गई है। इसी प्रकार से जो बसिज ऐजुकेशनल इन्स्टीच्यूट्स की हैं उनकी आयु 15 वर्ष है। इसी प्रकार से थ्री व्हीलर की भार–दो की रजिस्ट्रेशन में उनकी आयु 15 वर्ष निर्धारित कर दी गई है, जो कि बहुत ही सराहनीय है तथा बिसला जी को इसकी सराहना करनी चाहिए अब दिल्ली से आने वाले व्हीकलज जो 15 वर्ष के बाद आते थे अब वे हमारे यहां नहीं चल पाएंगे। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कोर्ट मोनिटरिंग करता रहता है और सुप्रीमकोर्ट ने हमारी इस परफोरमैंस के ऊपर हमें यह कहा कि हरियाणा प्रदेश की परफोरमैंस बहुत ही अच्छी है। स्पीकर साहब, वाटर पोल्यूशन के बारे में भी इन्होंने कहा है सुप्रीम कोर्ट ने यह माना है कि हमारे यहां से तो यमुना का पानी ठीक जाता है पर आगे जा कर दिल्ली में वह खराब हो जाता है इसके लिए उन्होंने अपना आदेश दिया है जो कि मैं यहां हाउस में पढ़ देता हूँ।

"The entire pollution takes place only in the stretch through which the Yamuna passes through Delhi, which is about 22 kms. The quality of water of the River Yamuna, when it enters Delhi, is far superior than that when it leaves Delhi and by the time Yamuna enters into Agra Canal. Delhi succeeds in reducing the dissolved oxygen level of the water to zero per cent."

यह खुद माना है कि दिल्ली के कई नाले यमुना में आकर शामिल हो जाते हैं। हरियाणा प्रदेश में यमुना का पानी ठीक पाया गया है ?

श्री पूर्ण सिंह डाबड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत माननीय सी०पी०एस० महोदय से यह जानना चाहूँगा कि हरियाणा सरकार ने जो फरीदाबाद में सैंट्रल पिट बनाई है जिसमें यह सोलिड वेस वगैरा फैक्टरीज का वेस जा करके डलना शुरू हो, जो क्लैक्टिव सरकार ने बनाया है क्या वह चालू हो गया है, अगर चालू हो गया है तो कितनी फैक्टरीज का उसमें डलना चालू हो गया है ?

श्री अध्यक्ष : दीवान साहब, आप भी अपना सप्लीमैंट्री पूछ लें। सी०पी०एस० महोदय इकट्ठा ही जवाब दे देंगे।

श्री देवराज दीवान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सी०पी०एस० महोदय को बताना चाहता हूँ कि सोनीपत में कैमिकल की वजह से पानी बहुत खराब हो चुका है। पिछले महीने मैंने एक ट्यूबवैल लगवाया था उसमें 246 फुट पर कैमिकल आ गया था। यह कैमिकल पीले रंग का था मैंने इस बारे में डी०सी० को फोन किया।

श्री अध्यक्ष : दीवान साहब, आप सवाल पूछें डी०सी० की बात न करें।

श्री देवराज दीवान : अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहूँगा कि जमीन में जो कैमिकल जा रहे हैं उसके बारे में सरकार क्या कर रही है, क्या सोनीपत में कोई पोल्यूशन चैक नहीं करता क्योंकि वहां पर धुंआ भी बहुत ज्यादा है और जमीन में कैमिकल भी भरा हुआ है।

श्री राम पाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, मेरे साथी ने जो पूछा है तो पानी के बारे में मैंने पहले बता दिया है और इसी तरह से इन्होंने विशेष पम्प हाउस के बारे में पूछा है तो इसका स्पैसिफिक सवाल से कोई सम्बन्ध नहीं है। इसमें एयर, वाटर और साउंड पोल्यूशन के बारे में नहीं बताया गया है तो उसके बारे में यह बताना चाहूँगा कि वह पब्लिक स्कूल जिसने हाईकोर्ट में रिट दायर कर रखी थी और

हाइकोर्ट में जो फैसला हुआ है उसके अनुसार मैसर्ज ए०बी० फोरजिंग्ज, मथुरा रोड की यूनिट को बंद करने के आदेश दिए हैं जो ज्यादा साउंड क्रिएट करती थी। इसके साथ ही जो फरीदाबाद के सीवरेज के बारे में मेरे साथी श्री पूर्ण सिंह डाबड़ा जी ने जो प्रश्न पूछा है तो वह अभी चालू नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष : ऑनरेबल मैम्बर्ज अब प्रश्न काल समाप्त होता है।

नियम 45 (1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

***1350. Sh. Banta Ram :** Will the Minister of State for Animal Husbandry be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government for renovation/reconstruction/strengthening of veterinary institutions in State. If so, the details thereof ?

पशुपालन राज्य मंत्री (चौ० मोहम्मद इलियास) : हाँ, श्रीमान्, राज्य के सीमित संसाधनों को ध्यान में रखते हुये, ऋण प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित दो प्रस्ताव भेजे गये हैं।

1. आर०आई०डी० एफ०-8 के अन्तर्गत नाबार्ड परियोजना
2. जे०बी०आई०सी० नई दिल्ली से जापान का ओ०डी०ए० ऋण

I & II Phase of 'Sarkar Apke Dwar' Programme

***1435. Shri Ramesh Kumar Khatak :** Will the Chief Minister be pleased to state the total number of announcements made during the first and second phase of 'Sarkar Apke Dwar Programme' togetherwith the number of announcements which have been fulfilled so far alongwith the number of announcements on which the work is still in progress.

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : 'सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम के प्रथम एवं द्वितीय चरण में कुल 33365 घोषणाएं की गई, जिनमें से 21969 घोषणाओं पर दिनांक 17-2-2003 तक कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा 7436 घोषणाओं पर कार्य प्रगति पर है।

Improvement in Power Transmission

***1328. Shri Tejvir Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state whether State Government has formulated any plan to improve the power transmission system in Kurukshetra and Kaithal Districts. If so, the details thereof ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : एक विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

कुरुक्षेत्र तथा कैथल जिलों में बिजली प्रसारण प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए वृहद योजनाएं

[श्री ओम प्रकाश चौटाला]

तैयार की गई हैं तथा क्रियान्वयन के अन्तर्गत हैं। इन योजनाओं के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्य पूर्ण किए गए हैं/निर्माणाधीन हैं।

जिला कुरुक्षेत्र :

जुलाई 1999 से 80 लाख रुपये की लागत पर झांसा में एक नया 33 के०वी० उप-केन्द्र चालू किया गया है तथा 1057 लाख रुपये की लागत पर 16 वर्तमान उपकेन्द्रों की क्षमता में वृद्धि की गई है।

जिला कुरुक्षेत्र में 6 नये उप-केन्द्र निर्माणाधीन हैं जिनकी लागत 1016 लाख रुपये है। थारा तथा कलसाना में 66 के०वी० उप केन्द्र तथा नासी, मुरथली, सैन्सा तथा गुमथला में 33 के०वी० उप-केन्द्र हैं। ये उप-केन्द्र वर्ष 2004 के अन्त तक पूर्ण होने सम्भावित हैं। 7 वर्तमान उप-केन्द्रों की क्षमता वृद्धि 669 लाख रुपये की अनुमानित लागत से करने का भी प्रस्ताव है। ये उप-केन्द्र 220 के०वी० उप-केन्द्र पेहवा, 132 के०वी० उप-केन्द्र इस्माइलाबाद, 66 के०वी० उप-केन्द्र नलवी तथा 33 के०वी० उप केन्द्र कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, बरना, किरमिच तथा झांसा हैं।

तीन 11 के०वी० फीडरों के पुनर्वास का कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा 18 ओवर लोडिड 11 के०वी० फीडरों को निकट भविष्य में द्विभाजित/त्रिभाजित किए जाने की योजना है।

जिला कैथल :

जुलाई 1999 में तीन नये 33 के०वी० उप-केन्द्र चीका, क्योतराम तथा जाखोली चालू किए जा चुके हैं तथा 8 वर्तमान उप-केन्द्रों की क्षमता वृद्धि 551 लाख रुपए की लागत से की जा चुकी है।

पांच 11 के०वी० फीडरों को सुदृढ़ करने का कार्य पूरा किया गया है तथा अन्य 6 ओवर लोडिड 11 के०वी० फीडरों को निकट भविष्य में द्विभाजित/त्रिभाजित करने की योजना है।

चीका में एक नया 220 के०वी० उप-केन्द्र, चार 132 के०वी० उप-केन्द्र पाडला, कर्णथली, चाकुलदाना तथा धागल तथा क्योडक, टीक तथा लघु सचिवालय कैथल में 33 के०वी० उप-केन्द्र निर्माणाधीन हैं जिनकी अनुमानित लागत 4908 लाख रुपए है जोकि वर्ष 2004 तक पूरे हो जाएंगे।

1161 लाख रुपये की लागत से वर्तमान 10 उप-केन्द्रों की क्षमता में वृद्धि करने का भी प्रस्ताव है। ये उप-केन्द्र 220 के०वी० उप-केन्द्र कैथल, 132 के०वी० उप-केन्द्र कौल, थाना तथा कैथल तथा 33 के०वी० उप-केन्द्र राजौंद, हाबड़ी, सीवन गेट, कैथल, फरल, डाण्ड तथा खेड़ी गुलाम अली हैं जोकि वर्ष 2004 के अन्त तक पूर्ण होने सम्भावित हैं।

Minors in Pataudi Constituency

***1344. Shri Rambir Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state the time by which Mujjafara Minor, Pataudi Minor and Lohari Minor in Pataudi Constituency are likely to start functioning ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : सभी योजनाएं 30-6-2003 तक पूरी होने की सम्भावना है।

Construction of Parallel Agra Canal

***1337. Shri Udai Bhan :** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a canal parallel to the Agra Canal from Gurgaon Feeder to Kithwari head or beyond within the boundary of Haryana for bringing water to be received from Agra Canal for use of the farmers of the State. If so, the details thereof ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : हाँ, श्रीमान जी। योजना प्रारम्भिक जांच के स्तर पर है।

———

Opening of CVDs/HCBC

***1366. Shri Suraj Mal :** Will the Minister of State for Animal Husbandry be pleased to state the number of CVDs/HCBC opened in the year 1996 to 99 and from July 1999 to January, 2003 ?

पशु पालन राज्य मंत्री (चौ० मोहम्मद इलियास) : श्रीमान जी, इस अवधि में निम्नलिखित पशु औषधालय/पशु अस्पताल एवं प्रजनन केन्द्र खोले गए हैं :—

अवधि	खोले गए पशु औषधालयों की संख्या	खोले गए पशु अस्पतालों एवं प्रजनन केन्द्रों की संख्या
1996-1999	शून्य	05
जुलाई 1999 से जनवरी, 2003	33	39

इसके अतिरिक्त दो पशु औषधालय 1996-99 की अवधि में पशु अस्पताल एवं प्रजनन केन्द्रों में अपग्रेड किये गये हैं तथा जुलाई 1999 से जनवरी 2003 तक 27 पशु औषधालय/पशुधन केन्द्र पशु अस्पताल एवं प्रजनन केन्द्रों में अपग्रेड किये गये हैं।

———

Increase in Electricity Tariff

***1319. Shri Balwant Singh Maina :** Will the Chief Minister be pleased to state :

(a) whether there has been any increase in electricity tariff during the period of the present Government in comparison to the tariff increased during the period of earlier Governments since 1991 ; and

(b) the manner in which the tariff increases compare with the increase proposed under the World Bank Reform Programme ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : (क) तथा (ख) विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

[श्री ओम प्रकाश चौटाला]

विवरण

वर्तमान सरकार तथा वर्ष 1991 से पूर्व सरकारों के कार्यकाल के दौरान बिजली दर में हुई वृद्धि निम्न प्रकार से है :—

क्र० सं०	दिनांक तथा वर्ष जब दर बढ़ाई गई थी	प्रतिशत वृद्धि	मुख्य मंत्री का नाम
1.	5-6-1992	12%	श्री भजन लाल
2.	1-2-1994	12%	श्री भजन लाल
3.	28-12-1994	25%	श्री भजन लाल
4.	1-7-1996	20%	श्री बंसी लाल
5.	15-6-1998	15%	श्री बंसी लाल
6.	1-1-2001	11.3%	श्री ओम प्रकाश चौटाला
7.	1-9-2001 (अन्तिम संशोधन)	0.8% (घरेलू, औद्योगिक तथा कृषि श्रेणियों के लोवर टैन्सन आपूर्ति उपभोक्ताओं के लिए)	श्री ओम प्रकाश चौटाला

विश्व बैंक के द्वारा सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रस्तावित औसत दर वृद्धि निम्न प्रकार से थी।

विश्व बैंक द्वारा दर में प्रस्तावित प्रतिशत वृद्धि

क्र० सं०	वर्ष	प्रतिशत वृद्धि
1.	1998-1999	14%
2.	1999-2000	15%
3.	2000-2001	21%
4.	2001-2002	17%
5.	2002-2003	7%

———

Widening of State Highway No. 17

***1349. Rao Narender Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state :

(a) whether there is any proposal under consideration of the Govt. for widening, raising and repairing the State Highway No. 17 in the Haryana boundary from Nangal Chaudhry, District Mahindergarh to Dadri, District Bhiwani ; and

(b) if so, the time by which the aforesaid proposal is likely to be implemented ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) :

(क) हां, श्रीमान जी।

(ख) इसको 12/2004 तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है।

Upgradation of Schools in Badhra Constituency

***1440. Shri Ranbir Singh Mandola :** Will the Minister of State for Education be pleased to state whether any schools have been upgraded in Badhra Constituency announcement for which was made by the Chief Minister. If so, the names thereof ?

शिक्षा राज्य मंत्री (चौ० बहादुर सिंह) : श्रीमान जी, बाढड़ा विधान सभा क्षेत्र में मुख्य मंत्री द्वारा की गई घोषणा के आधार पर निम्नलिखित विद्यालयों को स्तरोन्नत किया गया है।

प्राइमरी से मिडल (9)	मिडल से उच्च (11)	उच्च से वरिष्ठ माध्यमिक (8)
रा०मा०पा० उमरावास	रा०उ०वि० लाड	रा०व०मा०वि० द्वारिका
रा०मा०पा० डाडमा	रा०उ०वि० बाढड़ा (क)	रा०व०मा०वि० चान्दवास
रा०मा०पा० कलाली	रा०उ०वि० रामलवास	रा०व०मा०वि० झोझूकलां
रा०मा०पा० हसावासकलां	रा०उ०वि० बडराई	रा०व०मा०वि० डोहका हरिया
रा०मा०पा० कान्ड़रा	रा०उ०वि० काकडोली हुक्मी	रा०व०मा०वि० चांगरोड
रा०मा०पा० मकड़ाना (क)	रा०उ०वि० बालरोड	रा०व०मा०वि० गोपालवास
रा०मा०पा० कारीआदू	रा०उ०वि० रुद्रडोल	रा०व०मा०वि० काकडोली हुक्मी
रा०मा०पा० ककडोली हठी	रा०उ०वि० धनासरी	रा०व०मा०वि० मान्धा
रा०मा०पा० बलाली	रा०उ०वि० शीशवाला	
	रा०उ०वि० श्याम कलां	
	रा०उ०वि० बगडोली	

Repair of Chaupals

***1417. Shri Ram Kumar Katwal :** Will the Chief Minister be pleased to state whether any decision has been taken by the Government to repair the Chaupals of all sections of the Society in the State. If so, the expenditure likely to be incurred thereon during the year 2003 ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : हाँ, श्रीमान जी, सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि समाज के सभी वर्गों की चौपालों की मरम्मत करवाई जायेगी। इन चौपालों की मरम्मत

[श्री ओम प्रकाश चौटाला]

करवाने पर लगभग 38.00 करोड़ रुपये की राशि खर्च होने का अनुमान है, जो कि वर्ष 2003–2004 में खर्च की जानी प्रस्तावित है।

Laying of Water-Pipe-line

***1402. Ch. Jagjit Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether it is a fact that water pipe line has not been laid in Saraswati Vihar, Cooperative Society and Professors Colony in Charkhi Dadri ; and

(b) if so, the time by which the pipe line is likely to be laid down in the aforesaid colonies ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) :

(क) चरखी दादरी में सरस्वती विहार, सहकारी आवासीय समिति तथा प्रोफैसर कालोनी (सरस्वती विहार के साथ लगती) अस्वीकृत कालोनियां है। इस लिए पानी की पाईप लाईन नहीं डाली गई है।

(ख) उपरोक्त (क) के उत्तर के मध्यनजर इस स्थिति में प्रश्न नहीं उठता।

Construction of Bandh

***1458. Shri Kanwar Pal :** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a Bandh on river Yamuna in village Mandewala, in district Yamuna Nagar. If so, the time by which it is likely to be constructed ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : हाँ, श्रीमान जी। 30 जून 2003 तक यदि केन्द्रीय जल आयोग एवं उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के अधिकारियों की सहमति हो।

Opening of Girls College in Ambala City

***1394. Smt. Veena Chhibbar :** Will the Minister of State for Education be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to open a Government Girls College in Ambala City?

शिक्षा राज्य मंत्री (चौ० बहादुर सिंह) : जी नहीं, महोदया।

Construction on both sides of Suraj Kund Badkhal Road

***1369 Shri Krishan Pal :** Will the Minister of State for Urban Development

be pleased to state —

(a) whether any constructions have been made within 200 metre of both the sides of Surajkund Badkhal road after the judgement (Niri Report) of Hon'ble Supreme Court delivered in 1996 ?

(b) whether the above said constructions are against the judgement of Hon'ble Supreme Court ; and

(c) whether any officials have been found guilty for the above said constructions. If so, what action taken against them ?

नगर विकास राज्य मंत्री (श्री सुभाष गोयल) :

(क) जी नहीं।

(ख) —

(ग) —

ध्यानाकर्षण प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मैं एक विशेष मुद्दे पर बोलना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष : हुड्डा जी, आप बैठें। आपने कुछ लिख कर दिया ही नहीं है। (विघ्न) अगर आप लिखकर देते तो मैं उसके बारे में क्या फेट है बता देता। (विघ्न) जब आपने कुछ लिखकर ही नहीं दिया है तो आप किस बारे में बोलना चाहते हैं। (विघ्न) नहीं-नहीं आप बैठिए। (विघ्न) रूल्ज में जीरो आवर का प्रोविजन नहीं है। (विघ्न)

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक कालिंग अटैंशन मोशन नम्बर 18 और 19 नारायणगढ़ शूगर मिल को लोन देने बारे और ब्राह्मण महा सम्मेलन आरेगनाईज बाई श्री मूलचंद शर्मा के बारे में दी है उनका क्या हुआ है।

श्री अध्यक्ष : वे डिसअलाउ कर दी गई हैं। (विघ्न) आप अपनी सीट पर बैठ जाएं।

डॉ० रघुबीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, मैंने भी काल अटैंशन मोशन नम्बर 16 और 17 बेरी कांस्टीचुएंसी के गांव सीवाना में पीने का पानी उपलब्ध न होने के बारे में और Non-implementation of land consolidation process in village Dighal & Mohmmadpur Majra के बारे में है। इनका क्या हुआ है, आप इस बारे में बताएं।

श्री अध्यक्ष : वे डिसअलाउ कर दी गई हैं। (विघ्न)

डॉ० रघुबीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, वह डिसअलाउ क्यों हुई हैं आप इस बारे में बताएं। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : आप मेरे चैम्बर में आ जाना। वहां पर मैं आपको बता दूंगा। अब आप सब अपनी सीटों पर बैठ जाएं। (विघ्न) हुड्डा जी, अखबार पढ़ना और यहां पर आकर बोल देना यह पर्याप्त नहीं है। आप अपनी सीट पर बैठ जाएं। (विघ्न)

सदन की मेज पर रखे गए कागज-पत्र

Mr Speaker : Now, a Minister will lay papers on the Table of the House.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh) : Sir, I beg to lay on the Table of the House.

1. The 1st Annual Report of the Dakshin Haryana Bijli Vitran Nigam Limited for the year 1999-2000, as required under section 619-A(3)(b) of the Companies Act 1956.
2. The 2nd Annual Report of the Dakshin Haryana Bijli Vitran Nigam Limited for the year 2000-2001, as required under section 619-A(3)(b) of the Companies Act, 1956.
3. The 2nd Annual Report of the Uttar Haryana Bijli Vitran Nigam Limited for the year 2000-2001 as required under section 619-A(3)(b) of the Companies Act, 1956
4. The Audit Reports on the Accounts of the Haryana Prathmik Shiksha Pariyojna Parishad for the year 1996-97, 1997-98, 1998-99, 1999-2000, as required under rule 9.9 of D.P.E.P Manual of Administration.
5. The Report of the Comptroller and Auditor General of India for the year ended 31st March, 2002 (Revenue Receipts) of the Government of Haryana in pursuance of the provisions of clause (2) of Article 151 of the Constitution of India.

वर्ष 2003-2004 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा
(पुनरारम्भ)

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now general discussion on the Budget Estimates for the year 2003-2004 will be resumed. Now, Sh. Kapoor Chand Sharma may speak please.

श्री कपूर चन्द शर्मा (शाहबाद) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। सदन में चार दिनों से लगातार बहस हो रही है, खूब मन्थन हुआ है। सभी के विचार इसके बारे में आए। वे विचार काफी ठीक हैं और इस बजट में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। इस बजट के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। वित्तमंत्री प्रो० सम्पत सिंह ने जो 2003-04 का बजट विधान सभा में प्रस्तुत किया है उस पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। हमारे मुख्य मंत्री श्री ओम प्रकाश चौटाला जी के नेतृत्व में 3 सालों में जो उपलब्धियां हुई हैं वे इन तीन सालों से पहले आज तक कभी नहीं हुई हैं। यह बजट बहुत ही प्रसंशनीय और सराहनीय है। इस बजट में हरियाणा सरकार ने आर्थिक विकास में आधारभूत संरचना की तरफ ध्यान दिया है। उद्योग, स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा और हर प्रकार के विषय पर पूर्ण ध्यान दिया गया है। यह बजट संतोषजनक और सम्पूर्ण है। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा सरकार सामाजिक न्याय और समाज के सभी वर्गों के कल्याण एवं प्रदेश के हित में कार्य कर रही है। इस सरकार ने 'सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम के माध्यम से जो कार्य आरंभ किया है वह सर्वतः प्रशंसनीय और सराहनीय है। इससे हमारे क्षेत्र की जनता संतुष्ट है क्योंकि आज हमारे क्षेत्र में सभी जगहों पर विकास के काम हो रहे हैं। प्रथम चरण में जितने काम हुए थे वह सब पूर्ण हो चुके हैं, द्वितीय चरण में जिन कामों को करवाने की घोषणाएं की गयी थीं वे भी अब पूरी हो चुकी हैं। पहले चरण में जनता द्वारा

बहुत मांग की गयी थी लेकिन दूसरे चरण में जनता की उतनी मांगें नहीं रही और तीसरे चरण में उससे भी कम मांगें उनकी हो गयी हैं। आने वाले चरण में तो जनता की कोई मांग ही नहीं रहेगी क्योंकि जनता पूरी तरह से संतुष्ट है। अध्यक्ष महोदय, जब हम गांवों में जाते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा काम हो रहे हैं। कहीं पर हरिजन चौपालें बन रही हैं, कहीं पर वाल्मिकी चौपाले बन रही हैं, कहीं पर स्कूलों के कमरे बन रहे हैं, कहीं पर रिटेनिंग वाल बन रही है, कहीं पर फिरनी बन रही हैं और कहीं पर शमशान घाट के रास्ते और चार दीवारी बन रही हैं यानी सब जगहों पर कुछ न कुछ काम हो रहे हैं। हमारी इस हरियाणा सरकार ने खुले तौर पर पंचायतों को पैसा दिया है। इतना पैसा तो 45 सालों के राज में किसी भी सरकार ने पंचायतों को नहीं दिया है। अध्यक्ष महोदय, राजीव गांधी ने कहा था कि अगर दिल्ली से सौ रुपये चलते हैं तो नीचे के लेवल पर 16 रुपये ही काम पर लगते हैं। हमारी सरकार ने सीधा पंचायतों को पैसा दिया है। मैं अपने क्षेत्र के गांव-गांव में जाकर पैसा देकर आया हूँ। पंच, सरपंच और मुखिया को मैंने विकास के काम करवाने के लिए चैक दिए हैं और उनको कहा है कि भाई पहले आप कहा करते थे कि पैसा बहुत कम आता है क्योंकि ज्यादातर पैसा अफसर लोग खा जाते हैं लेकिन अब आप देखो कि आप तक पैसा सीधा आ रहा है और अफसर अब कोई पैसा नहीं लेगा। अब पैसा आपके पास है आप इसको बैंक में जमा करवाओ और जितना काम है उनके ऐस्टीमेट के हिसाब से उनको करवाओ। ऐस्टीमेटस के हिसाब से जितनी ईंट लगनी हैं जितना रेत लगना है जितना सीमेंट लगना है उतना लगवाओ। मैंने उनको कहा है कि अब भी अगर इनमें कमी रही तो दोष आपका ही होगा। अध्यक्ष महोदय, इस तरह से अब चारों तरफ काम हो रहे हैं। पंचायत अफसर, एस०डी०ओ०, पंचायत और बी०डी०पी०ओ० एवं डी०सी० साहब भी खुद जाकर काम को देखकर आते हैं। सब जगहों पर संतुष्टि से काम हो रहे हैं। यह प्रसन्नता और सराहना का विषय है। हमारे कुछ साथियों ने चर्चा करते हुए कहा कि हिमाचल में भाजपा का क्या हुआ। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि हरियाणा की सरकार ने अटल बिहारी वाजपेयी जी को 1996-97 में बहुमत दिया एवं 1997 में फिर बहुमत दिया और जब 1999 में चुनाव हुए तो इंडियन नैशनल लोकदल और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन ने कांग्रेस का सफाया कर दिया है इनको एक भी सीट नहीं मिली थी। जनता ने सराहा है। हरियाणा सरकार पिछले तीन सालों से चल रही है और आगे भी यह पांच साल चलेगी। इसी तरह से सैंट्रल गवर्नमैंट भी अपना समय पूरा करेगी। इन सरकारों में कोई कमी नहीं है ये सरकारें चट्टान की तरह मजबूत हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारे मुख्य मंत्री जी अनथक परिश्रम 24 घंटों में 18 घंटे काम करते हैं और केन्द्र में जो भी नीतियां लागू होती हैं उसको सबसे पहले वे हरियाणा में लागू करवाते हैं। आज सब जगहों पर हरियाणा में काम हो रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से शिक्षा का विषय है। शिक्षा के बगैर राष्ट्र और समाज की उन्नति नहीं हो सकती। यह विषय बहुत ही चिन्तनीय विषय है सोचने का विषय है। हालांकि इसमें बहुत सुधार किया गया है लेकिन इसमें अभी और सुधार करने की जरूरत है। कितना ही आदमी उच्च कुल में पैदा हो और चाहे वह कितना ही सुन्दर हो, बलवान हो लेकिन जब तक वह शिक्षित नहीं होगा तब तक उसका विकास नहीं हो सकता। कहा भी गया है—

'रूप यौवन सम्पन्ना विशाल कुल सम्भवा,
विद्या हीना न शोभन्ते निर्गन्धा इव किंशुका'।

विद्या के बगैर आदमी शोभा नहीं देता। जितना वह विद्या ग्रहण करेगा जितना वह तालीम लेगा हमारा देश उतनी ही तरक्की करेगा, उतना ही देश का उत्थान होगा, समाज का उत्थान होगा। अध्यक्ष महोदय, जितना वह विद्या ग्रहण करेगा उतनी ही देश की, समाज की कुरीतियां दूर होंगी। अध्यक्ष

[श्री कपूर चन्द शर्मा]

महोदय, आजकल के आधुनिक विद्यालयों में सामाजिक शिक्षा जरूरी है, धार्मिक शिक्षा जरूरी है। हमारी संस्कृति यह थी —

'विद्या ददाति विनयं विनयात् याति पात्रताम्,
पात्रता धनं आप्नोति तदैति सुखम।'

विद्या से मनुष्य को योग्यता प्राप्त होती है परन्तु आज जो हमें विद्या दी जा रही है वह विद्या नहीं है बल्कि चरित्रहीनता हो रही है चरित्र हनन हो रहा है। जब सामाजिक प्रदूषण दूर होगा तभी हमारा उत्थान होगा। इस ओर भी हमें ध्यान देना चाहिए। बजट पर तीन दिन से लगातार बहुत चर्चा हो रही है, मंथन हो रहा है। बजट के विषय में मैं अधिक समय नहीं लूंगा। मैं अपने क्षेत्र के विषय में कुछ बातें मुख्य मंत्री जी के समक्ष रखना चाहूँगा। सरकार फल्ड को समाप्त करने का काम कर रही है किन्तु मेरे क्षेत्र में अभी भी हर साल फल्ड आता है पिछले साल भी 15 अगस्त को फल्ड आया था। मेरे हल्के के 25-26 गांव एकदम बाढ़ से प्रभावित होते हैं। सड़क के ऊपर से पानी जाता है 3-3, 4-4 दिन पानी चलता है उसके ऊपर सरकार विशेष ध्यान दे। यह मैं अपने हल्के की मांग मुख्य मंत्री जी के समक्ष रखता हूँ। दूसरे, मेरे क्षेत्र में पानी की बहुत कमी है 350-400 फुट तक टयूबवैलों का पानी चला गया है यदि किसान फसल बो कर टयूबवैलों से सिंचाई करेंगे तो पीने का पानी नहीं मिलेगा। इस विषय में सरकार को ध्यान देना चाहिए। जहां तक दादूपुर नलवी नहर का सवाल है मेरे क्षेत्र को दादूपुर नलवी नहर कोई फायदा नहीं दे सकती, कोई लाभ नहीं दे सकती। दादूपुर नलवी नहर यमुनानगर, अम्बाला और कुरुक्षेत्र इन तीनों जिलों को फायदा देती है। हमारे पास से भाखड़ा नहर जा रही है हमें उसका पानी नहीं मिलता है। जहां तक एस०वाई०एल० का सवाल है यह हरियाणा की जीवन रेखा है। मुझसे पूर्व बोलते हुए सभी ने यह कहा है यह बहुत आवश्यक है। केन्द्र सरकार भी चाहती है कि हरियाणा को पानी मिले। आज मैं सभी भाइयों से निवेदन करता हूँ कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सभी मतभेद दूर करके एकजुट होकर एस०वाई०एल० कैनाल के पानी की समस्या का हल कराएं। इसके लिए कितने भी प्रयत्न करने पड़ें हम सरकार के साथ हैं और होना भी चाहिए। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ। आज का युग बिजली का युग है जमींदार ट्रैक्टरों से, मोटरों से काम करते हैं उनकी फसल को जब आग लग जाती है कई बार गन्ने में आग लग जाती है हमारे यहां फायर बिग्रेड उस आग को बुझाने के लिए नहीं थी आज हमारे यहां फायर बिग्रेड के लिए बिल्डिंग बन रही है इसमें दो फायर बिग्रेड लगाएंगे, कमरे बन रहे हैं इसके लिए मैं मुख्य मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ। मेरे क्षेत्र में टयूबवैल का रेट अलग-अलग है कहीं पर 45 रुपए पर हार्स पावर है कहीं पर 55 रुपए है और कहीं पर 65 रुपए है यह एक समान होना चाहिए यह जमींदारों की आवाज है। चार खेत पर 55 रुपये रेट है उससे अगले पर 65 रुपये रेट है इसकी समानता होनी चाहिए। शाहबाद से इस्माइलबाद के रास्ते में जो रेलवे फाटक है वह एक-एक घंटे या चालीस-चालीस मिनट तक बंद रहता है क्योंकि इस रूट पर गाड़ियों का बहुत ज्यादा आना-जाना है। यदि कोई डिलीवरी केस हो या कोई फट्टड़ हुआ आदमी और फाटक बंद हो उसको ले जाने के लिए कोई और रास्ता नहीं है इसके लिए मेरा अनुरोध है कि सरकार केन्द्र सरकार से मिलकर कोई न कोई उपाय अवश्य करे या तो पुल के नीचे से रास्ता बना दें क्योंकि ऊपर से पुल बनना तो बड़ा कठिन है नीचे से रास्ता बन जाए तो बहुत लाभ हो जाएगा। उससे कार, ऑटो, घोड़ा, बुग्गी, रिक्शा वगैरह निकल सकेगा। हमारी सरकार सभी क्षेत्रों में पेड़ लगा रही है यह बहुत ही उत्तम काम है इससे प्रदूषण दूर होगा और वातावरण शुद्ध, स्वच्छ होगा, यह स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। कल आयुर्वेद के विषय में बात चली थी। मंत्री महोदय ने कहा

था कि ऐलोपैथी अस्पताल के साथ आयुर्वेदिक डिस्पैंसरी खोल दें तो वहां मरीज नहीं जाएंगे। मैं दृष्टांत देना चाहता हूँ। एक होली फैमिली हास्पिटल दिल्ली में है, मिशन हास्पिटल बहुत बड़ा हास्पिटल दिल्ली में है वहां आयुर्वेदिक विभाग अलग से हैं और उस आयुर्वेदिक औषधालय में आयुर्वेदिक औषधि लेने के लिए मरीज दूर-दूर से आते हैं। 500-500 मील से लोग आकर चिकित्सा कराते हैं विशेषकर गठिया रोग की। वहां हर कमरे में 12-12 रोगी भर्ती होते हैं और हर विभाग में स्त्री और पुरुष के लिए अलग-अलग डाक्टर मिलते हैं। वे उन मरीजों की समय पर आयुर्वेदिक तेल की मालिश करते हैं और औषधि की पोटली बनाकर घण्टों सेंक करते हैं तेल लगाते हैं इससे उन मरीजों को काफी लाभ होता है। इस प्रकार की योजना हमारे प्रदेश में भी होनी चाहिए जैसे कहा गया है —

धर्मे बधे धन बधे सहज समय उपाय,
साथी सेवा देश की देसी औषध खाये।

देसी औषधि की उपज पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिये वनस्पतियों की जो उपज आज हो रही है उसमें अच्छी किस्म की वनस्पतियां होनी चाहिएं आज अच्छी हरड़ नहीं मिलती। आज हरड़ 20 रुपये किलो भी मिलती है और 1000 रुपये किलो भी हरड़ मिलती है। इतना अन्तर क्यों है अच्छी हरड़ नहीं मिलती है हमारे यहां लिखा है—

चेतकी तुधता हस्ते यावन् जिसष्ठाते देहिनः।
तावत् मिघते तत् क्षणादेवेपशु पक्षिमृगादयः॥

कहने का तात्पर्य यह है कि कोई व्यक्ति जितनी देर चेतकी हरड़ को हाथ में रखेगा उतनी देर उसे जुलाब लगा रहेगा और जितनी देर इसके वृक्ष की छाया में कोई भी पशु पक्षी बैठा रहेगा तब तक उसे भी जुलाब लगा रहेगा। ऐसी जो नस्ल हैं हल्की भी और भारी भी उनको लगाना चाहिए ताकि जनता को लाभ हो और उनका स्वास्थ्य ठीक होगा। हमारी सरकार को इस बारे विशेष ध्यान देना चाहिए। इन शब्दों के साथ अधिक समय न लेते हुए मैं इस बजट का समर्थन करता हूँ और आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया उसका धन्यवाद।

श्री अभय सिंह चौटाला (रोड़ी) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया। मैं इस बजट का तहेदिल से समर्थन करता हूँ जो हमारे वित्त मंत्री महोदय प्रोफेसर सम्पत सिंह जी ने बजट हमारे सामने रखा और एक ऐसा बजट विधान सभा में पेश किया जिस पर हमारे कुछ साथियों को छोड़कर पूरे हरियाणा प्रदेश के लोगों ने सराहने का काम किया है। आपने मुझे समय दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मैं विशेष रूप से हमारे जो साथी आज यहां पर मौजूद हैं उनसे एक आग्रह करना चाहूँगा कि जब कभी कोई भी साथी ने चाहे बजट में हिस्सा लिया, चाहे किसी साथी ने गवर्नर के अभिभाषण में हिस्सा लिया, चाहे क्वैश्चन आवर में लिया, मैंने किसी भी साथी के बीच में कभी किसी किस्म की टीका-टिप्पणी नहीं की। मुझे उम्मीद है कि वे मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे और मुझे भी बीच में ना टोककर मेरी बात को सुनने का काम करेंगे। सभी साथियों ने अध्यक्ष महोदय, विस्तार से बजट पर चर्चा की और विपक्ष के साथियों ने जब-जब बोलने का मौका दिया मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा समय आपने बोलने का विपक्ष के साथियों को दिया और विपक्ष के साथियों की हालत उस समय ऐसी होती कि जब किसी साथी का नाम आपने पुकारा तो ये कहते हुये बाहर जाने का काम किया कि आज इस चर्चा में भाग नहीं लेंगे फिर देखेंगे। फिर चर्चा में भाग लेने का काम करेंगे। किसी ने कृषि पर चर्चा की, किसी ने बिजली पर चर्चा की, किसी ने एस०वाई०एल० पर चर्चा की, किसी साथी ने स्वास्थ्य पर चर्चा की, किसी ने इन्फोर्मेशन टैक्नोलॉजी पर चर्चा की। हमारा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है। मैं सदन का ज्यादा समय न लेकर 2-3 चीजों पर

[श्री अभय सिंह चौटाला]

चर्चा करना चाहूँगा। खासकर कृषि पर क्योंकि हमारा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है और कृषि में ज्यादा साधन जुटाए जाएं तो प्रदेश में खेती बाड़ी की हालत अच्छी होगी तथा प्रदेश का विकास ज्यादा होगा। साऊथ हरियाणा के जो हमारे साथी हैं उन्होंने बार-बार इस बजट पर चर्चा की कि साऊथ हरियाणा सूखे की चपेट में है, पानी का बंटवारा पूरा नहीं है, पानी की कमी है। इस मुद्दे को लेकर सभी साथियों ने बार-बार इस पर बहस और चर्चा करने का काम किया लेकिन जब से इस प्रदेश में ओम प्रकाश चौटाला के नेतृत्व में सरकार बनी है, खासकर साऊथ हरियाणा में कृषि को बढ़ावा दिया गया और बढ़ावा भी इस रूप में दिया गया कि यहां पर एकड़ जो इन्कम हुआ करती थी, जो बीज बोया जाता था या जो बीज सरकार की ओर से मुहैया करवाया जाता था जिसकी किस्म अच्छी न होने की वजह से उस इलाके में अच्छी फसल नहीं हुआ करती थी, हमारी सरकार बनने के बाद कृषि वैज्ञानिकों को विशेष रूप से यह हिदायत दी गई कि कम पानी के खर्च में अच्छी फसल हो सके इसके लिए नए बीजों का विकास किया जाए, इससे दक्षिणी हरियाणा में लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ हो सके। उसी को ध्यान में रखकर हमारे कृषि वैज्ञानिक जो हमारी HAU से जुड़े हुए लोग हैं उन्होंने इस ओर अपने प्रयास करने शुरू कर दिए और उस प्रयास का नतीजा यह निकला कि मेरे साथी दक्षिणी हरियाणा के एम०एल०एज० यहां पर बैठे हुए हैं वे भी मुझसे विधान सभा के बाहर मिलते हैं तो मानते हैं कि हमारे यहां अच्छा बीज भेजा गया और उसकी वजह से फसल अच्छी हुई। खेती में फव्वारा सैट उपलब्ध करवाए गए हैं जिससे हमारी सिंचाई बढ़ी है और खेती की पैदावार बढ़ी है। विशेष रूप से जिस एरिया में पानी की कमी है वहां हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने बाजरा, जौ, मसर, चना और मूंग की अच्छी किस्म के बीज तैयार किए जिससे हमारी इन फसलों की यील्ड जो पहले कम हुआ करती थी, वह बढ़ी है। बाजरे की एच०एच०बी०-94 की किस्म हमने पैदा करके इसकी खेती को बढ़ावा देने का काम किया गया। अध्यक्ष महोदय, बी०एच० 93 की किस्म पैदा की जिससे कम पानी देकर ज्यादा पैदावार करने का काम किया। इसी तरह मसर का गरिमा नाम का बीज तैयार किया है जो न केवल हरियाणा में बोया जाता है बल्कि हमारे यहां से बीज को राजस्थान के लोग ले जाकर बोने का काम करते हैं। इसी तरह से चने की एच०सी०-3 एक किस्म तैयार की गई है जिससे चने की यील्ड बढ़ी है। मूंग की मुस्कान वैरायटी तैयार की गई जिससे हमारी मूंग की खेती को बढ़ावा मिला। जो मात्र 60 दिन में पक कर तैयार हो जाती है। इससे किसानों को और लाभ हुआ। कल हमारे विपक्ष के साथियों ने चर्चा में भाग लेते हुए इस मुद्दे को उठाया था कि साऊथ हरियाणा में पानी की कमी की वजह से कुछ एरिया खाली रह गया। कुछ ऐसा एरिया है जहां सूखे के कारण फसल खराब हो गई। विपक्ष के भाई कह रहे थे कि उनको एक रुपया, दो रुपये या चार रुपये मुआवजे के रूप में दिए गये। जबकि आंकड़े बताते हैं और सभी जानते भी हैं कि पिछले तीन वर्षों में पूरे हरियाणा प्रदेश में खासकर दक्षिणी हरियाणा में फसल की यील्ड में बढ़ौतरी हुई है और बढ़ौतरी भी इतनी अधिक कि पिछले 20 वर्षों में इतनी अच्छी फसल नहीं हुई। स्पीकर सर, इसका एक ही कारण है कि हमारी सरकार ने पूरे हरियाणा प्रदेश के किसानों को बिना किसी भेदभाव के बराबर और पूरी बिजली दी। मुझे कई दफा दक्षिणी हरियाणा में विशेषकर रिवाड़ी, महेन्द्रगढ़, भिवानी, दादरी और झज्जर आदि के इलाकों में जाने का अवसर मिला। मैं वहां पर गया ही नहीं बल्कि कांग्रेस के विधायकों से भी मिला उन्होंने भी इस बात को स्वीकारा है कि उनके यहां 8 से 10 घंटे किसानों को प्रति दिन बिजली मिल रही है, जिसके कारण वहां फसल अच्छी हुई है। इसके अतिरिक्त उन्होंने यह भी माना है कि सरकार की तरफ से दूसरी सुविधाएं भी किसानों को दी गई हैं, जैसे फव्वारा सैट्स के लिए सबसिडी, अच्छा बीज और खाद तथा 10 से 12 घन्टे दिन में

किसानों को बिजली आदि। स्पीकर सर, आज भी दक्षिणी हरियाणा में चाहे वह भिवानी का क्षेत्र है, दादरी का क्षेत्र है, रिवाड़ी, गुड़गांव या महेन्द्रगढ़ का क्षेत्र है वहां पर सरसों और चना की फसल सिरसा, जींद के इलाकों से अच्छी है यह तभी हो पाया है जब हमारी सरकार ने बिना किसी भेदभाव के उन्हें पूरी बिजली दी है। स्पीकर सर, इसके अतिरिक्त हमारे साथियों ने इस बात पर बहुत जोर दिया कि यदि गेहूं और चावल की फसल इसी तरह पैदा होती रही तो आने वाले समय में उसको बेचने में दिक्कत आयेगी, उनकी यह बात किसी हद तक ठीक भी है। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि जब संयुक्त पंजाब था यानि हरियाणा, हिमाचल और पंजाब तीनों एक राज्य हुआ करते थे। उस समय स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी ने हरियाणा में कृषि को बढ़ावा देने के लिए खासकर हॉर्टीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए उस समय की सरकार पर दबाव डालकर एक स्कीम लागू करवाने का काम किया था कि यदि कोई भी किसान अपने यहां बाग लगाने का काम करेगा और वह नहर से पानी लगाता है तो उसको अधिक पानी दिया जायेगा। जैसे यदि किसी किसान को 9 से 10 मिनट पानी नहर से मिलता है तो बाग लगाने वाले किसान को 35 मिनट पानी दिया जायेगा लेकिन चौधरी भजन लाल जी 1982-83 में मुख्य मंत्री थे उस समय उन्होंने वह स्कीम बंद कर दी। जबकि चौधरी देवी लाल जी ने यह स्कीम बागवानी को बढ़ावा देने के लिए लागू करवाई थी। इस स्कीम के लागू होने से ओल्ड हिसार के किसानों में जागरूकता पैदा हुई और उन्होंने अपने यहां बाग लगाने का काम भी किया। उससे उनकी इन्कम हुई और उनको लाभ भी मिला और उस समय लोगों की डिमांड भी बढ़ गई थी और वे बाग लगाने लगे थे। लेकिन अफसोस की बात है कि 1982-83 में चौधरी भजन लाल जी ने वह स्कीम बंद कर दी। उसका नतीजा यह निकला कि लोगों ने बाग लगाने बंद कर दिए और अपनी परम्परागत फसल बोने लग गये। आज ये कहते हैं कि फसल के चक्रवात को बदला जाये ताकि किसान को ज्यादा लाभ मिल सके और इन्होंने ही वह स्कीम बंद कर दी। स्पीकर सर, यदि उस समय यह स्कीम बंद न की जाती तो प्रदेश में बागवानी को बहुत बढ़ावा मिलता और उससे पैदा होने वाले फलों से किसान को और प्रदेश को फायदा होता। इतना ही नहीं बल्कि हरियाणा प्रदेश के वातावरण में भी सुधार होता और आज हरियाणा में पोल्यूशन नाम की चीज नहीं होती लेकिन यह सब इनके कारण नहीं हो पाया। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से प्रदेश के मुख्य मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि जो स्कीम स्वर्गीय चौधरी देवी लाल जी ने संयुक्त पंजाब के समय में लागू करवाई थी उसको दोबारा से लागू किया जाये ताकि प्रदेश का किसान उससे लाभ उठा सके और हरियाणा प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा फल पैदा हो सकें। किसानों को बागवानी की जानकारी देने के लिए नर्सरियां बनाई जायें जिस प्रकार से पिछले वर्ष 29 लाख पौधे देने का काम किया गया था उसी तरह किसानों को आगे भी पौधे दिए जायें तथा जो भी किसान बाग लगाने का काम करे उसे पानी अधिक दिया जाये।

चौधरी भजन लाल : आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। यह ठीक बात है कि मैंने 1981-82 में बागों का पानी बन्द किया। बागों के नाम से पानी ज्यादा मिलता है। खास करके हिसार, सिरसा, फतेहाबाद में पानी का ज्यादा इस्तेमाल करते थे क्योंकि बाग के नाम से चार गुणा पानी ज्यादा मिलता है। इसलिए हमने कहा कि, नहीं क्योंकि कुछ एरिया ऐसा है जैसे मेवात का एरिया है दक्षिणी हरियाणा है वहां पानी कम है। (विघ्न)

11-00 बजे

श्री अध्यक्ष : नहीं, आप बैठिए।

श्री अभय सिंह चौटाला : चौधरी भजन लाल जी ने अभी प्वायंट आफ आर्डर पर यह बात कही कि मैंने 1982 और 1983 में पानी बन्द करने का काम किया। एक बात तो पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाती है कि चौधरी भजन लाल किसान के इतने बड़े हितैषी हैं, ये सबसे बड़े किसान विरोधी हैं इसका

[श्री अभय सिंह चौटाला]

इस बात से अन्दाजा लगाया जा सकता है कि जो पानी किसान को मिलता है जिससे प्रदेश की पैदावार बढ़ती है, जिससे प्रदेश को लाभ होता था उस स्कीम को चौधरी भजन लाल ने बन्द किया। न केवल बन्द किया अगर इस किस्म की कोई बात थी, चौधरी भजन लाल जी यह कहना चाहते थे कि चौधरी देवी लाल जी के बाग थे। चौधरी भजन लाल जी को मैं यह कहना चाहता हूँ कि चौधरी देवी लाल जी के बाग थे, हमारे पास बाग चौधरी भजन लाल आज के नहीं सन् 1956 के लगे हुए हैं, आपको शायद इस बात का ज्ञान नहीं है। (विघ्न)

चौधरी भजन लाल : स्पीकर सर *******

श्री अध्यक्ष : चौधरी भजन लाल जी, आप बगैर परमिशन के बोल रहे हैं इसलिए इनकी कोई बात रिकॉर्ड नहीं की जाये।

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : स्पीकर साहब, बाग हमेशा नहर आने पर ही लगा करते हैं। इनका बताने का मकसद केवल एक था कि हमारे बाग तब लगे हैं जब ये राजनीति में कहीं दिखाई नहीं देते थे।

चौधरी भजन लाल : स्पीकर सर ********

श्री अध्यक्ष : चौधरी भजन लाल जी, आप बिना परमिशन के बोल रहे हैं, इसलिए इनकी कोई बात रिकॉर्ड न की जाये।

श्री अभय सिंह चौटाला : आप राजनीति में कहीं नहीं थे बल्कि आपने उस वक्त में पानी बन्द किया था। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : आप तो खेतों का पानी भी बन्द कर दोगे। आपको क्या फर्क पड़ता है। बागों का पानी बन्द कर दिया तो खेतों का भी बन्द कर देते।

पशु पालन राज्य मंत्री (चौ० मोहम्मद इलियास) : आन ए प्वायंट ऑफ ऑर्डर सर। अध्यक्ष महोदय, चौधरी भजन लाल जी यह कह रहे हैं कि जहां पानी कम था वहां पर पानी दिया है जिनमें मेवात का क्षेत्र भी शामिल था। चौधरी साहब से मैं यह पूछना चाहता हूँ कि 82 से लेकर के जब तक आप मुख्य मंत्री रहे हरियाणा प्रदेश के, मेवात को कहां से पानी दिया और कौन-कौन सी डिस्ट्रीब्यूटरीज से दिया। आपने कौन सा एडीशनल पानी दिया। स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से चौधरी साहब को बताना चाहता हूँ और पूरे हाउस को बताना चाहता हूँ कि आदरणीय मुख्य मंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के कार्यक्रमों के कारण ही मेवात के अन्दर जहां खेतों में भी पानी नहीं था, नहरों का जाल बिछाया गया है। यह सब कुछ ओम प्रकाश चौटाला जी के कारण ही हुआ है इसके लिए मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ।

वित्त मंत्री (प्रो० सम्पत सिंह) : अध्यक्ष महोदय, चौधरी भजन लाल जी ने जो जवाब अभी दिया है वह वाजिब नहीं है इन्होंने यह कहा है कि कुछ लोग बाग के नाम पर पानी का गलत और अनुचित इस्तेमाल कर रहे थे इसलिए बन्द कर दिया। अगर कुछ लोग अनुचित इस्तेमाल कर रहे थे तो

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

उनको बन्द करते लेकिन एज ए पॉलिसी मैटर जो इन्होंने बंद किया इससे ज्यादा हरियाणा का और कोई अहित नहीं हो सकता। (विघ्न) आज क्रोप की डाईवर्सिफिकेशन की बात चल रही है 130 लाख टन से फालतू अनाज आज हरियाणा में पैदा हो रहा है। गेहूँ और चावल को आज कोई पूछ नहीं रहा है। अगर सही मायनों में बागों को प्रोत्साहन दिया गया होता तो यह नौबत नहीं आती। इस मौसम के अन्दर भी आज विदेशों से अपने कण्ट्री में कितने ही फ्रूटस मंगवाए जाते हैं। आज साथ लगते ऐशियन कण्ट्रीज से कितना ही फ्रूट हमें इम्पोर्ट करना पड़ता है क्यों करना पड़ता है क्योंकि हर सीजन के अन्दर आज हम उनको जरूरत के मुताबिक तैयार नहीं कर पाते हैं। अदरवाईज ग्रीन हाउसिज वगैरा तैयार करके अगर वे बने रहते और बागवानी में बढ़ौतरी होती तो आज यह दिन देखना न पड़ता और क्रोप डाईवर्सिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती। केवल यह बहाना कर लिया कि कुछ लोग अनुचित इस्तेमाल कर रहे थे और यह स्थिति उसके बाद ही पैदा हुई। अध्यक्ष महोदय, अगर इनको चौधरी देवी लाल के परिवार से कोई पोलिटिकल रंजिश थी तो कोई बात नहीं थी ये उनके बाग का पानी बंद कर देते। (विघ्न) लेकिन सारे हरियाणा का एज ए पॉलिसी मैटर जो बागों का पानी बंद किया उससे ज्यादा और कोई क्राईम नहीं हो सकता। (विघ्न)

चौधरी भजन लाल : स्पीकर साहब, आप मेरी बात सुनें। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : भजन लाल जी, क्या यह आपके बोलने का तरीका है ? (विघ्न) आप बैठें। (विघ्न) आप इजाजत लेकर खड़े हों और तभी बोलें। (विघ्न) बिना इजाजत के आप कैसे खड़े हो सकते हैं, आप अपनी सीट पर बैठें। (विघ्न) इस तरह से आप बीच में किस हैसियत से खड़े हैं। (विघ्न)

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से खड़ा होने का हमारा हक है और अपनी बात कहने का भी हमें हक है आप मेरी बात सुनें। (विघ्न एवं शोर) अध्यक्ष महोदय, यह आपका ठीक तरीका नहीं है जब कोई कहने वाली बात होगी तो हम खड़े होंगे। (विघ्न एवं शोर) आपको हमारी बात सुननी चाहिए। (विघ्न एवं शोर) मैं अपनी सीट पर खड़ा हूँ।

श्री अध्यक्ष : भजन लाल जी, आप अगर अपनी सीट पर नहीं बैठते तो आप बाहर चले जाएं। (विघ्न एवं शोर) मैं आपको वार्न करता हूँ। आपको अपनी सीट पर परमिशन लेकर खड़ा होना चाहिए। (विघ्न एवं शोर) आप इतने पुराने पार्लियामैंटेरियन हैं लेकिन आपको यह नहीं पता कि किस टाइम क्या बोला जाता है, अब आप बैठिये। (विघ्न एवं शोर) भजन लाल जी, आप किस हैसियत से खड़े हैं आपको पता ही नहीं ? हुड्डा साहब, आप इनको कुछ समझाएं। ये बूढ़े हो गए हैं लेकिन अभी तक इनको कुछ पता नहीं है। (विघ्न एवं शोर) इनको यह भी नहीं पता कि प्वायंट ऑफ ऑर्डर पर खड़ा होना है इनको पता तो कुछ है नहीं। (विघ्न एवं शोर) भजन लाल जी, आपको यह पता ही नहीं कि आप किस बात पर खड़े हैं। आपको बोलने की कोई इजाजत नहीं है इसलिए आप बैठें। (विघ्न एवं शोर) जब आपकी सरकार होती थी तो सारी ब्रीफिंग होकर आ जाती थी और आप हाउस में खड़े होकर बोल देते थे। आपको खुद को तो कुछ करना धरना आता नहीं और वैसे ही खड़े हो जाते हैं। हर मिनट पर हर बार आप खड़े हो जाते हैं, अब आप बैठें। (विघ्न एवं शोर)

श्री अभय सिंह चौटाला : चौधरी भजन लाल जी, आप मेरा समय क्यों खराब कर रहे हैं, आप अपनी सीट पर बैठें ताकि मैं अपनी बात कह सकूं। (विघ्न एवं शोर)

श्री अध्यक्ष : भजन लाल जी, आपको खुद को तो कुछ पता ही नहीं है कि किस टाईम पर क्या करना चाहिए। (विघ्न एवं शोर)

श्री अभय सिंह चौटाला : चौधरी साहब, मुझे तो तीन साल में आज पहली बार बोलने का मौका मिला है। (विघ्न एवं शोर)

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात सुनें। (विघ्न एवं शोर)

श्री अध्यक्ष : चौधरी साहब, आपको दो बार बोलने का समय दिया। आपका नाम बोलने वालों की लिस्ट में नहीं था फिर भी मैंने आपको बोलने के लिए समय दिया। (विघ्न एवं शोर) आपने अपने वक्त पर गलत काम किए हुए हैं अब आपको तकलीफ क्यों हो रही है? (विघ्न एवं शोर)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मुझे तो तीन साल में पहली बार खड़े होकर बोलने का मौका मिला है और चौधरी भजन लाल जी मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। चौधरी साहब, आपकी लड़ाई जहां पर है वहां पर निपटा लेना लेकिन अभी आप मेरी बात तो सुन लें। (विघ्न एवं शोर) मेरी बात आपको सुनने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए मैं कोई ऐसी बात नहीं कहूँगा जो गलत हो। मैंने तो 1981-82 की बात बताई है और मैंने जो बात कही उसको आपने मान लिया। (विघ्न एवं शोर) आपने माना है कि आपने पानी बंद किया क्यों बंद किया? (विघ्न एवं शोर) आपको मेरी बात सुननी तो पड़ेगी। (विघ्न एवं शोर) इस बारे में एक दफा पहले भी बात आई थी तो आप कहने लगे कि मेरी कुश्ती कहीं और है आप वहीं पर कुश्ती लड़ लियो और देख लियो लेकिन जब मैं बोल रहा हूँ तो बीच में टोकाटोकी क्यों करते हो। (विघ्न एवं शोर) अध्यक्ष महोदय, माजरा साहब ने ठीक बात कही थी इनको ही नहीं चौधरी बंसी लाल जी को भी हियरिंग मशीन लेकर देनी पड़ेगी।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, इनको ज्ञान नहीं है कि इनकी लड़ाई न तो उनसे है और न मेरे से है इनकी असली लड़ाई तो यहां पर है। (हंसी)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, अभी चौधरी भजन लाल जी ने स्वीकार किया है कि 1982-83 में जो बागों को पानी दिया जाता था उसको इन्होंने ही बंद किया था। चौधरी भजन लाल जी ने यह भी कहा है कि कुछ लोग उस पानी का मिस-यूज कर रहे थे। अध्यक्ष महोदय, अगर कुछ लोग उस पानी का मिस-यूज कर रहे थे तो वे उन लोगों का पता करके उनको पानी देना बंद करते। इन्होंने तो सभी का पानी बंद कर दिया। इनको तो यह चाहिए था कि जो वहां पर किसान थे, बाग लगाना चाहते थे, उनको तो पानी देते ताकि फसल का चक्रवात चलता रहता। इनको इस बात का ज्ञान नहीं था क्योंकि इन्होंने कभी खेती करी ही नहीं है। ये तो सन् 1956 और 1957 में घी और चुनरी बेचा करते थे। इनको इस बात का पता ही नहीं है कि खेती क्या होती है और राजनीति क्या होती है।

चौधरी भजन लाल : हाँ, मैं घी और चुनरी बेचा करता था यह मैं मानता हूँ लेकिन मैं थारे की बता दूंगा तो प्रोब्लम होगी। ....

श्री अध्यक्ष : भजन लाल जी, आप अपनी सीट पर बैठ जाएं। (विघ्न) आप बीच में न टोकें। (विघ्न)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैंने तो यही कहा है कि ये घी और चुनरी बेचा करते थे। (विघ्न) घी और चुनरी के अलावा इन्होंने चने की ब्लैक करी थी।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : चौधरी भजन लाल जी मुझे बीच में दखल तो नहीं देना चाहिए

था। लेकिन अभय ने जो कहा है कि आप घी और चुनरी बेचा करते थे इसमें कोई बुराई नहीं है। उसमें आपको महारत हासिल हुई इसलिए आपने पहले इन्दिरा को बहकाया था और अब की बार सोनिया को बहका कर आए हो। आप यह इसलिए कर सके हो क्योंकि आपका तो औरतों से ही सम्पर्क रहा है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : भजन लाल जी, आप बैठिए। हुड्डा साहब, आप इनको बिठाएं। ये इस तरह से बार-बार न खड़े हों। (शोर एवं व्यवधान) अभय सिंह जी को बोलने दें।

चौधरी भजन लाल : मैंने कब इनको बोलने से रोका है?

श्री अभय सिंह चौटाला : आप ही तो मुझे बोलने से रोक रहे हैं। आप बार-बार बीच में बोलने के लिए खड़े हो जाते हैं।

चौधरी भजन लाल : आप मुझे गाली देंगे तो मैं उसका जवाब दूँगा।

श्री अभय सिंह चौटाला : मैंने कब आपको गाली दी है। भजन लाल जी, सदन का एक भी सदस्य यह बता दे कि मैंने आपको गाली दी है। मैंने तो आपका नाम ही लिया है। अगर आपका नाम लेना ही गाली है तो यह तो वही बात हो गई जो चौटाला साहब ने रेलवे स्टेशन वाली कही थी। अध्यक्ष महोदय, ये किसानों के कितने बड़े हितैषी रहे थे और कितने बड़े हितैषी हैं, यह मैं सदन में बता देता हूँ। सन् 1981-82 में चौधरी भजन लाल जी की सरकार थी। उस समय किसानों को 22 रुपये प्रति क्विंटल का गन्ने का भाव मिलता था और इन्होंने उसको 2 रुपये कम करके 20 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया था। इसके साथ ही 1984 में भी आपकी सरकार थी उस समय भी गन्ने का भाव 20 रुपये प्रति क्विंटल ही था। उसके बाद 1987 से लेकर 1991 तक चौधरी देवी लाल जी मुख्य मंत्री थे। उन्होंने अपने राज में 21 रुपये प्रति क्विंटल तक गन्ने के भाव बढ़ा कर किसानों को राहत देने का काम किया था। उसके बाद चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के नेतृत्व की सरकार आई तो इन्होंने गन्ने के 95 रुपए प्रति क्विंटल के भाव को 15 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बढ़ाकर के 110 रुपये प्रति क्विंटल का भाव देकर फिर से किसानों को राहत देने का काम किया था। हमने किसानों को दाम बढ़ाकर लाभ ही नहीं दिया है बल्कि इसके अलावा जो किसानों के गन्ने की पिछली पेमैन्ट 25 करोड़ रुपये के लगभग शूगर मिलों की तरफ बकाया थी उसको भी किसानों को दिलवाने का काम हमारी सरकार ने ही किया है। इसके अलावा हुड्डा साहब ने बोलते हुए कहा कि नारायणगढ़ की मिल को एच०एस०आई०डी०सी० से 7 करोड़ रुपये का लोन दिलवा कर किसानों की जो पेमैंट बकाया थी उसके लिए दिए गए हैं। उन्होंने उस समय यह कहा था कि हरियाणा प्रदेश को लुटाया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, कल ये कह रहे थे कि पेमैंट नहीं हो रही है जिसकी वजह से वहां का किसान परेशान है। आज जब किसान की पेमैंट की बात आ रही है तो ये प्रदेश को लुटाने की बात कर रहे हैं।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष जी, मैंने यह नहीं कहा। मैंने यह कहा था कि जैसे मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि हम यमुनानगर के मिल को इस वास्ते मदद नहीं करते कि इससे पूंजीपति को मदद हो जाएगी जबकि हम पूंजीपति की मदद नहीं करना चाहते। यदि आप किसान को सबसिडी देते हैं तो हम उसके लिए आपकी प्रशंसा भी करेंगे।

श्री अध्यक्ष : हुड्डा साहब, डायरैक्ट नहीं दे सकते। लोन ही दिया जा सकता है फैक्टरी को और फैक्टरी लोन लेगी तो आगे पेमैंट करेगी। अपने फंड से पहले भरेगी न। आपको कानून का तो पता ही होगा इसलिए आप बैठ जाएं। उन्होंने बहुत क्लीयर बात ही कही है इसलिए इसमें बहस न करें।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, यह चर्चा दोबारा आ गयी। मुझे अफसोस तो इस बात का है कि विपक्ष के नेता प्रोपर-वे में कोई भी चीज सदन में प्रस्तुत नहीं कर सकते।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : मौका ही कहाँ मिलता है।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : मौका तो आपको मिलता है। अगर इनको वोट ऑफ नो कान्फिडैंस लाने का मौका मिलता है तब इनको रूल्ज का ज्ञान नहीं होता है, जब उस पर चर्चा करने का वक्त मिलता है तो ये उस पर वोटिंग से पहले ही वाक-आउट करके चले जाते हैं यानी कोई भी चीज प्रोपर समय में ये प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं। ये ऐसा क्यों नहीं कर पाते हैं मैं इसके कारण में नहीं जाना चाहता। चूंकि यह जिक्र दोबारा से आ गया इसलिए मैं स्पष्ट करना चाहूँगा। भजन लाल जी भी यहां पर बैठे हैं। जहां तक हरियाणा प्रदेश की सरकार की बात है तीन ऐसे अदारये हैं जो लोगों को कर्जा देते हैं। वे हैं—एच०एस०आई०डी०सी०, फाईनेंशियल कॉरपोरेशन और हमारे कोपरेटिव बैंक्स। मौजूदा सरकार में इन तीनों अदारों ने ही मुनाफा कमाया है। लोगों को ज्यादा कर्ज दिये हैं जिस शूगर मिल का जिक्र किया गया, शायद इनको जानकारी नहीं, इस शूगर मिल को एच०एस०आई०डी०सी० की तरफ से पहले भी कर्जा दिया गया था। एच०एस०आई०डी०सी० उसमें भागीदार है और जिसको कर्जा दिया जाता है तो जैसा कल भांगे राम जी ने तथा दूसरे मैम्बर्ज ने कहा था कि कर्जा देते वक्त उसके सारे असैट्स चैक किए जाते हैं और पूरी तरह से उसकी सारी सम्पत्ति को देखकर ही कर्जा दिया जाता है। उन छोटे-छोटे किसानों का पैसा डूब न जाए उसको ध्यान में रखकर और इन जैसे लोगों के बहकाने की वजह से वहां लॉ एंड आर्डर की स्थिति खराब न हो जाए उसको दृष्टिगत रखकर बाकायदगी से एच०एस०आई०डी०सी० के बोर्ड की मीटिंग हुई और बाकायदगी से कैबिनेट ने उसकी मंजूरी दी है और यह जानकर के, यह देखकर के कि उनका पैसा डूब न जाए पूरी तसल्ली करने के बाद ही कर्जा दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो ये चाहते हैं कि किसान को उसका पैसा मिले और दूसरी तरफ से यह भी कहते हैं कि सरकार किसानों को कर्जा देकर अपना पैसा लूटा रही है। अध्यक्ष महोदय, सरकार अपना पैसा लुटाने से पहले बाकायदगी से सारी जांच पड़ताल करती है कि तेरा पैसा मय सूद के वापस आने की स्थिति में भी है या नहीं। बड़ा सोच विचार करके ही निर्णय लिया जाता है। इसलिए हुड्डा साहब, आप सोचकर ही फैसला लिया करो। ऐसी अनर्गल बातें कहकर सदन का समय खराब नहीं करना चाहिए।

वैयक्तिक स्पष्टीकरण —

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा एम०एल०ए० द्वारा

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी ने मेरा नाम लिया है इसलिए मुझे इस बारे में पर्सनल एक्सप्लेनेशन देने का अधिकार है।

श्री अध्यक्ष : हुड्डा साहब, आप कैसे खड़े हो गये?

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मैं पर्सनल एक्सप्लेनेशन पर खड़ा हूँ।

श्री अध्यक्ष : हुड्डा साहब, आप पहले बोलना शुरू कर देते हैं और बाद में परमिशन मांगते हैं। (विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने मेरा नाम लिया है इसलिए मेरा अधिकार है

कि मैं इस बारे में अपनी बात क्लीयर करूँ।

श्री अध्यक्ष : नहीं नहीं, ऐसा कोई अधिकार नहीं है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का ऐतराज नहीं है कि लोन दिया जाए। एच०एस०आई०डी०सी० का काम है लोन देना वह चाहे पचास करोड़ दे या सौ करोड़ दे लेकिन उस बारे में स्टेट गवर्नमैंट को गारंटी देनी चाहिए।

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, मैं इनको एक बात और बता दूं इसको थोड़ा-सा और स्पष्ट कर दूं। स्टेट गवर्नमैंट हर उस अदायरे को गारंटी देती है जो स्टेट से जुड़े हुए हैं। स्टेट गवर्नमैंट मार्केटिंग बोर्ड को भी गारंटी देती है, स्टेट गवर्नमैंट बिजली बोर्ड को भी गारंटी देती है, स्टेट गवर्नमैंट हुड्डा को भी गारंटी देती है, स्टेट गवर्नमैंट अपने सारे कारपोरेशंज को भी गारंटी देती है। लेकिन पूंजीपति को गारंटी नहीं दी गई है। अध्यक्ष महोदय, मैंने बताया है कि एच०एस०आई०डी०सी० का पहले से भी उस पर कर्जा है और उसके असैट्स को देखकर ही उसको लोन दिया गया है। हुड्डा साहब, अगर आपको नहीं पता तो आप भजन लाल जी से पूछ लिया करो। मिल को गारन्टी नहीं दी गई। जब मैं आपको मोटे दिमाग वाला कहता हूँ तो आप बुरा मानते हैं। (शोर एवं व्यवधान) जल्दी से बात आपकी समझ में आती नहीं है। भजन लाल और कैप्टन सयाने लोग हैं ये आपको सुझाना नहीं चाहते हैं ये चाहते हैं कि मूर्ख बना रहे तो ठीक है।

वर्ष 2003-04 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा
(पुनरारम्भ)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहूँगा कि इस प्रदेश के बनने से पहले जो स्कीम लागू थी उसको नये सिरे से लागू किया जाए ताकि किसानों को उसका लाभ मिल सके और जो इलाका इस किस्म का है जहां पानी की कमी है या जहां नहर का पानी नहीं है उसके लिए हौर्टीकल्चर डिपार्टमैंट इस किस्म के फलदार पौधे तैयार करे जिनमें पानी की कम से कम जरूरत होती हो जैसे आंवला है, बेरी है। इस किस्म की नर्सरियां डिवैल्प करके हरियाणा में बाग लगवाएं ताकि किसान को ज्यादा लाभ मिल सके। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे अपने बाग हैं मैंने बागों की खेती की है भजन लाल जी, आप भी सुन लें मैंने बाग 3 हजार रुपए पर एकड़ के हिसाब से भी बेचा है और 5 हजार रुपये पर एकड़ के हिसाब से भी बेचा है और ऐसी स्थिति भी देखी है कि जब बाग को कोई खरीदने वाला नहीं होता था लेकिन आज हमारे यहां पैदा होने वाले जो फ्रूट हैं, वे पर एकड़ 70 हजार या 1 लाख रुपया तक किसान को देने का काम करते हैं। हमारे यहां की जो कीनू की किस्म है वह एक लाख रुपये पर एकड़ के हिसाब से बिकती है उससे किसान को सीधा-सीधा लाभ मिलता है इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करता हूँ कि ये स्कीम दोबारा से चालू करें ताकि किसान को इसका लाभ मिल सके। इसी तरह से पिछले दिनों चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के नेतृत्व में इस हरियाणा प्रदेश की सरकार बनने के बाद किसान को उसके पशुओं की नस्ल के सुधार हेतु बोर्ड का गठन किया गया है क्योंकि हमारे प्रदेश में खेती की जोत लगातार कम होती जा रही है किसान के पास आमदन का एक माध्यम तो खेती होता है और दूसरा माध्यम पशु है। हमारी सरकार बनने के बाद विशेष रूप से इस बोर्ड का गठन करके किसान को बहुत लाभ पहुंचाया गया है। उत्तम किस्म के पशुओं के मालिकों को प्रोत्साहन दिया गया है ताकि वे अच्छे से अच्छे पशु तैयार करें। मैं सरकार से आग्रह करना चाहूँगा कि जो 12

[श्री अभय सिंह चौटाला]

लीटर दूध और 15 लीटर दूध के पशुओं के लिए इनामात रखे गए हैं उसमें 10 लीटर दूध के पशु भी शामिल कर लिए जाएं ताकि किसान और अच्छे पशु तैयार कर सके और ज्यादा पशु पाल सके जिससे किसान को लाभ हो। हमारे वक्त में जो स्कीम लागू की गई थी खासकर पशुओं को प्रोत्साहन देने के लिए उन पशुओं के मालिकों को जो नकद इनामात दिए गए वह पिछली सरकारों के समय में चाहे वह चौधरी भजन लाल जी की सरकार हो या चौधरी बंसी लाल जी की सरकार हो, अच्छे पशु पालकों को कोई इनाम नहीं दिया गया, उसी की वजह से जो अच्छे पशु थे, जो अच्छी नस्ल थी, वह कम हुई उसको हमने नये सिरे से बढ़ाने के लिए 1 करोड़ 86 लाख रुपये के नकद इनाम देकर किसान को सीधा लाभ पहुँचाया। कुछ साथी जिक्र कर रहे थे कि सूखे की मार की वजह से हरियाणा प्रदेश के किसानों के पशु मर गए या वे पशुओं को लेकर पलायन कर गए। इस बात की चर्चा कुछ साथियों ने की। मैं उनकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि हरियाणा प्रदेश के अन्दर छः हजार से कुछ अधिक गांव हैं जिनमें से 5622 गांवों की आबादी में हरियाणा सरकार की ओर से पशुओं के कैम्प लगाये गये जहां जो भी कोई पशु बीमार थे उनका इलाज किया गया अगर बीमार नहीं थे तो उनका चैक-अप कराया गया ताकि किसानों को उसका लाभ हो सके और पशुओं को किसी दूसरी जगह ले जाना न पड़े। इसी तरह से नये हास्पिटल बनाये गये। वैटरनरी डॉक्टर्ज की नियुक्ति की गई, वी०एल०डी०एज० की नियुक्ति की गई। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि पशुओं के मामले में भी ध्यान दें ताकि ज्यादा से ज्यादा अच्छी किस्मों के पशु पैदा हो सकें और किसानों को ज्यादा लाभ मिल सके। इसके लिए सरकार अपनी ओर से प्रयासरत है। सरकार की ओर से हिसार में इस किस्म का सैंटर भी बनाया जा रहा है जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोग जाकर ट्रेनिंग ले सकेंगे। मैं तो कहता हूँ कि न केवल हिसार में ही बल्कि करनाल, अम्बाला साईड में भी इस किस्म का सैंटर बनाया जाये जिससे किसान उसमें ट्रेनिंग ले सकें। किसान उसमें यह सीख सकें कि किस प्रकार से अच्छी किस्म के पशु पाले जाते हैं और किस प्रकार से उनके दूध में बढ़ोतरी की जा सकती है। इसलिए इस साईड में भी ऐसे सैंटर बनाये जायें जिससे किसानों को लाभ हो सके। मेरे साथियों ने और भी बहुत सी बातों पर चर्चा की। कुछ साथियों ने स्पोर्टस पर चर्चा की। चौधरी भजनलाल जी, स्पोर्टस पर आप छींटाकशी कर रहे थे। कुछ छींटाकशी दूसरे साथियों ने भी इस पर की। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि हरियाणा प्रदेश में 1991 से 1996 तक स्पोर्टस की हालत क्या थी, (विघ्न) सन् 1996 से 1999 तक स्पोर्टस की हालत क्या थी, (विघ्न) इसके बारे में मैं बताऊंगा कि 1996 से 1999 तक जब चौधरी बंसीलाल जी स्पोर्टस की हालत क्या थी, और 1999 से लेकर 2003 तक हमने इस प्रदेश के स्पोर्टस को किस तरह से बढ़ाया है इसकी जानकारी आपको रोजाना अखबारों में मिलती है और अगर आप टेलीविजन देखते हैं तो हरियाणा प्रदेश के खिलाड़ी कहीं न कहीं अच्छा प्रदर्शन करते हुये आपको नजर आयेंगे और न केवल अपने देश में बल्कि चाहे मानचेस्टर के कॉमन वैल्थ गेम हों, चाहे बुशान के गेम हों आज हमारे देश की क्रिकेट की टीम दक्षिणी अफ्रीका में खेलने के लिए गई है सब जगह हरियाणा के खिलाड़ी आपको अच्छा प्रदर्शन करते हुए नजर आयेंगे। मैं ज्यादा समय न लेता हुआ मोटी-मोटी एक ही बात का जिक्र करना चाहूँगा। सन् 1991 से 1996 तक जब चौधरी भजन लाल जी इस प्रदेश के मुख्य मंत्री थे उस समय ओलम्पिक में भाग लेने वाले जो हमारे हरियाणा प्रदेश के प्लेयर्ज थे उनको इनामात के तौर पर स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी को एक लाख रुपये, रजत पदक जीतने वाले खिलाड़ी को 75 हजार रुपये और कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ी को 50 हजार रुपये दिये जाते थे। जब चौधरी बंसी लाल की सरकार आई उस समय भी यही पैसा दिया जाता

था। लेकिन जब से हमारी यह सरकार चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के नेतृत्व में बनी है हरियाणा प्रदेश के खिलाड़ियों को अध्यक्ष महोदय ओलम्पिक में विजयी होने वाले खिलाड़ी को एक करोड़ रुपये नकद पुरस्कार देने का काम किया है। जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने इस बात की घोषणा की थी कि हम ओलम्पिक खेलों में विजयी होने वाले खिलाड़ी को एक करोड़ रुपये देंगे तो विपक्ष के लोगों ने अखबार के माध्यम से कहा था कि ये तो घोषणा करते हैं ये घोषणा करने वाले मुख्य मंत्री हैं। लेकिन खुशकिस्मती हमारे प्रदेश की है और इस भारतवर्ष की है कि जब सिडनी में वर्ष 2000 में ओलम्पिक गेम्स हुए थे उस वक्त मैं भी सिडनी गया हुआ था, हमारे प्रदेश की महिला और हमारे प्रदेश की बहू कर्णम मल्लेश्वरी ने ब्रोंज मैडल जीतकर भारतवर्ष का नाम ऊंचा किया था। हमारे प्रदेश के मुख्य मंत्री ने तुरन्त उसी वक्त टेलीफोन करके उस महिला को अपनी ओर से बधाई दी और उसको प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने कहा कि जब आप एयरपोर्ट से भारत की धरती पर कदम रखोगी तो हम आपको अपनी ओर से 25 लाख रुपये देकर सम्मानित करेंगे। उन्होंने न केवल उसको 25 लाख रुपये दिये बल्कि साथ ही 25 लाख रुपये का प्लाट भी दिया ताकि वह और लोगों को अच्छी ट्रेनिंग दे सके। दूसरी तरफ आपकी हालत यह थी कि आपने एक-एक लाख रुपये की घोषणा की और आपकी उस घोषणा से हरियाणा प्रदेश के किसी खिलाड़ी को विश्वास ही नहीं था कि आप इनाम दे सकते हैं। इसलिए हमारे खिलाड़ियों का मनोबल टूटा। न केवल हमारे खिलाड़ियों का मनोबल टूटा बल्कि हमारे हरियाणा प्रदेश के खिलाड़ी हरियाणा प्रदेश से पलायन करके राजस्थान, रेलवे, सी०आर०पी०एफ०, बी०एस०एफ० में चले गए। हमने खेल नीति बनाकर उनको हरियाणा प्रदेश में वापिस लाने का काम किया। खिलाड़ियों की 3 प्रतिशत नौकरियों में आरक्षण जो चौ० देवी लाल जी ने दिया था उस आरक्षण के तहत उनको नौकरियां मिला करती थीं, इन्होंने उस आरक्षण को खत्म किया और हमने उसको लागू करके अपने उन खिलाड़ियों को दोबारा हरियाणा प्रदेश में लाने का काम किया और उसका नतीजा यह है कि जो आज नेशनल खेल हुए हैं आपके वक्त जहां हमारे प्रदेश का 14वां स्थान था और उस वक्त हमारे टोटल मैडल 37 थे। 1993 में पूना में जो नेशनल गेम्स हुए थे आप उस समय प्रदेश के मुख्य मंत्री थे हरियाणा की सिर्फ 11वीं पोजीशन थी और टोटल 37 मैडल आए थे। 1999 में जब बंसी लाल जी मुख्य मंत्री थे इम्फाल में नेशनल गेम्स हुए उसमें हरियाणा प्रदेश की 14वीं पोजीशन थी। आज हमारे वक्त में वर्ष 2000 में जब लुधियाना में नेशनल गेम्स हुए उसमें हरियाणा प्रदेश की छठी पोजीशन आई और हरियाणा के हिस्से 17 गोल्ड मैडल, 20 रजत और 28 कांस्य पदक आये। कुल मिलाकर 65 पदक हमारे प्रदेश के खिलाड़ियों ने जीतने का काम किया। वर्ष 2000 में हैदराबाद में जो गेम्स हुए उसमें हमारी 7वीं पोजीशन थी अब इस बात पर भी आप कुछ न कुछ कह देंगे कि पहले छठी पोजीशन थी अब 7वीं पोजीशन है तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि हमारे मैडलों की संख्या बढ़ी है। हमारे गोल्ड मैडल 19, सिल्वर मैडल 23, कांस्य मैडल 32 हुए और कुल मिलाकर हमें 74 मैडल मिले। जो हमारी खेल नीति की वजह से ही हैं और उसी की वजह से ही हमारे खिलाड़ी जो हरियाणा से पलायन कर रहे थे या छोड़कर चले गए थे वे हरियाणा में रुके और उन्होंने हरियाणा प्रदेश में नौकरियां हासिल की और उन्होंने हरियाणा प्रदेश में अच्छे खेलों का प्रदर्शन करके इस प्रदेश का नाम बढ़ाया। आप दोनों के समय में जितने मैडल मिले थे अकेले 2000 के हैदराबाद के नेशनल गेम्ज में हमने उससे भी ज्यादा मैडल अब की बार प्राप्त किए हैं। इसी तरह से आपके वक्त में 1993-94 में जो अन्तर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ी हरियाणा प्रदेश के थे उनकी संख्या दो थी। बंसी लाल जी के वक्त में 1996-97 में उनकी संख्या नौ थी। आज 2002-2003 में उनकी संख्या 27 है यह भी हमारी खेल नीति का नतीजा है। आपके वक्त में हरियाणा प्रदेश के

[श्री अभय सिंह चौटाला]

युवाओं को किस तरह से गुमराह किया जाता था, वह मैं आपको बता देता हूँ। बंसी लाल जी बैठे नहीं हैं वे कहते थे कि हम गैस एजेंसीज देंगे, पेट्रोल पम्प देंगे, खाद डिपो देंगे और बसों के परमिट देंगे। बसों के परमिट जिन लोगों को दिए गए उनकी हालत इस किस्म की थी कि उनकी बसों में शराब की थैलियां होती थीं। **(इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए)** जो बच्चे स्कूलों में पढ़ने चाहिए थे और जो हमारा भविष्य हैं जिनको लेकर सब चिन्तित थे, उनके हाथ में कापी, किताब, पैंसिल होनी चाहिए थी, उनके बैग में शराब की थैलियां मिला करती थीं। हमने दोबारा नई खेल नीति बनाकर युवाओं में जागृति पैदा की और एक खेल नीति बनाई और वह ऐसी नीति बनाई जिससे गांव स्तर के लोग जुड़े। 1987 के अन्दर चौ० देवी लाल जी के वक्त में गांव के स्तर पर, ब्लाक के स्तर पर और स्टेट के स्तर पर जो ग्रामीण खेल होते थे उनको भी पहले वाली सरकारों ने बंद करने का काम किया। उपाध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त हरियाणा ओलम्पिक संघ की यह जिम्मेवारी होती थी कि वह साल में एक बार खेल मेले का आयोजन करेगा और उसमें राज्य के सभी खिलाड़ी हिस्सा लेकर अपना प्रदर्शन करेंगे लेकिन विपक्ष के भाईयों ने अपनी सरकार के समय में उस मेले को भी बंद करवा दिया। अब हमारी सरकार ने उन खेलों को बढ़ावा देने के लिए नये सिरे से योजनाएं शुरू की हैं। हरियाणा ओलम्पिक संघ ने न केवल स्टेट गेम्ज का आयोजन करवाया बल्कि ग्रामीण खेलों का आयोजन भी पंचायत डिवैल्पमैंट विभाग की तरफ से करवाया गया जिसका परिणाम यह हुआ कि गांवों में रहने वाले खिलाड़ियों ने भी उसमें हिस्सा लिया और अपनी क्षमता के अनुसार प्रदर्शन करके इनामात हासिल किए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से चौधरी भजन लाल जी को कहना चाहूँगा कि वे स्वयं तो सुबह छः बजे उठते नहीं होंगे लेकिन अपनी पार्टी के दूसरे सदस्य जो सुबह पांच या छः बजे उठते हैं उनसे पूछ लें कि आज हरियाणा में किसी भी सड़क पर सुबह निकल जाओ वहां 100 से ज्यादा संख्या में लड़के एक्सरसाईज करते हुए मिलेंगे, दौड़ लगाते हुए मिलेंगे जबकि चौधरी भजन लाल जी और चौधरी बंसी लाल जी के वक्त में ऐसे हालात थे कि नौजवान लड़के सुबह-शाम घर से बाहर नहीं निकलते थे। उस समय उनको डर होता था कि यदि वे घर से बाहर निकलेंगे तो उनके खिलाफ शराबबंदी की आड़ में पर्चा दर्ज किया जायेगा और उन्हें बिना बात अंदर कर दिया जायेगा या किसी और मामले में झूठा पर्चा दर्ज हो जायेगा। उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह से इन्होंने अपने समय में नौजवानों की बहुत दुर्गति और दुर्दशा कर रखी थी यही कारण है कि आज इनकी भी दुर्गति हुई और आज ये वहां बैठे हुए हैं और आगे भी होगी। उपाध्यक्ष महोदय, अंत में मैं माननीय प्रो० सम्पत सिंह जी का जिन्होंने बहुत ही अच्छा बजट पेश किया उसके लिए उनको धन्यवाद करता हूँ और बजट का समर्थन करता हूँ। इसके साथ-साथ मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया और अपने विपक्ष के भाईयों का भी धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे बोलते हुए बीच में इन्ट्रप्ट नहीं किया। धन्यवाद।

शोक प्रस्ताव

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : उपाध्यक्ष महोदय, यदि आप अनुमति दें तो मैं भरे मन से तीन लोगों के प्रति एक शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहूँगा जो आज हमारे बीच में नहीं हैं। स्वतंत्रता सेनानी श्री दलीप सिंह, गांव कलवाड़ी, खण्ड कनीना के रहने वाले थे। वे अपने गांव के सरपंच भी रहे। गत दिनों से वे बीमार चल रहे थे और 82 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। सिपाही रमेश, गांव बडनपुर, जिला जींद का रहने वाला था। रमेश सियाचिन ग्लेशियर में तैनात था। हिम स्खलन से उनकी मौत हो गई। ए०एस०आई० मेहर सिंह, गांव मुढलाना, जिला सोनीपत का रहने वाला था। मेहर सिंह इण्डो-तिब्बत पुलिस बल में ए०एस०आई० के पद पर कार्यरत थे। चीन सीमा पर

जोशी मठ में ग्लेशियर के नीचे दबने से उनका निधन हो गया। आज हमारे देश की सीमाओं के दो सुरक्षा प्रहरी और एक स्वतन्त्रता सेनानी हमारे बीच में नहीं रहे। मैं उनके परिवार के लोगों के प्रति, उनके दोस्तों और मित्रों के प्रति सदन की हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वह उन्हें अपने चरणों में स्थान दे।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा (किलोई) : उपाध्यक्ष महोदय, शोक संतप्त परिवारों के प्रति मुख्य मंत्री जी ने जो भावनाएं व्यक्त की हैं मैं पूरे विपक्ष की तरफ से उन भावनाओं का समर्थन करता हूँ और शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी पार्टी की तरफ से संवेदना प्रकट करता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : मुख्य मंत्री जी ने और लीडर ऑफ दी अपोजीशन ने अपनी जो भावनाएं शोक संतप्त परिवारों के प्रति प्रकट की हैं इनसे संबंधित परिवारों को सदन की तरफ से अवगत करवा दिया जायेगा। अब मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करूँगा कि दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए खड़े होकर दो मिनट का मौन धारण करें **(इस समय सभी माननीय सदस्यों ने खड़े होकर दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए दो मिनट का मौन धारण किया।)**

वर्ष 2003-2004 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री उपाध्यक्ष : अब मैं सुभाष गोयल जी से रिक्वैस्ट करूँगा कि वे बजट पर बोलें।

शहरी विकास मंत्री (श्री सुभाष गोयल) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, आदरणीय प्रोफैसर जी ने बहुत ही अच्छा बजट प्रस्तुत किया है। माननीय मुख्य मंत्री ने हरियाणा प्रदेश के विकास के लिए हरियाणा बनने के पश्चात् से हरियाणा के शहरों के विकास के लिए, हरियाणा के शहरीकरण के लिए पिछले वर्षों की तुलना में पहले की सरकारों ने पहले कभी इस बात की कोशिश नहीं की कि हरियाणा प्रदेश की अपनी ही अर्बन डिवैल्पमैंट पॉलिसी होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, माननीय श्री ओम प्रकाश चौटाला के दिशा निर्देश में, उनकी रहनुमाई में, हरियाणा प्रदेश में पहली बार हरियाणा अर्बन डिवैल्पमैंट पॉलिसी बनाई गई है। उस अर्बन डिवैल्पमैंट पॉलिसी के तहत एक कालोनाइजर के लिए एक लाइसेंसिंग पॉलिसी माननीय मुख्य मंत्री जी ओम प्रकाश चौटाला जी के निर्देश में बनायी है। लाइसेंसिंग पॉलिसी का मतलब है कि हरियाणा प्रदेश में जो अवैध कालोनियां स्थापित होती जा रही थी, उनका निर्माण न हो। मुख्य मंत्री ओम प्रकाश चौटाला जी के दिशा निर्देश में इन्होंने यह चाहा कि हम हरियाणा प्रदेश में हर नगरवासी को उनकी जरूरतों के मुताबिक उनकी आज की आकांक्षाओं के मुताबिक हर सहूलियत प्रदान कर सकें, सहूलियतें देने के मद्देनजर यह लाइसेंसिंग पॉलिसी बनाई गई जिसके तहत हरियाणा प्रदेश में अवैध कालोनियों का निर्माण रूका। इसके पश्चात् एच०आर०डी०एफ० की तर्ज पर हरियाणा प्रदेश में हरियाणा अर्बन इन्फ्रास्ट्रैक्चर डिवैल्पमैंट फण्ड की स्थापना की गई जिसके द्वारा हम हरियाणा प्रदेश में शहरों के सौन्दर्यकरण के लिए शहरों की सफाई के लिए, शहरों में पार्कों की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, शहरों की आबादी में आज के मुताबिक हर प्रकार की सहूलियतें प्रदान करने के लिए पैसा खर्च कर सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, हमारी पार्टी की सरकार आने के पश्चात् माननीय ओम प्रकाश चौटाला के दिशा निर्देश में चुंगी की कुप्रथा को समाप्त किया गया और तह बाजारी को समाप्त किया गया। इन दोनों के समाप्त करने के पश्चात् आज विपक्षी बैंचिज की तरफ से यह आवाज आ रही थी कि 6-6 महीने से वहां के कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रही।

[श्री सुभाष गोयल]

मैं माननीय सदस्यों को आपके माध्यम से जानकारी देना चाहूँगा कि हरियाणा प्रदेश में किसी स्थान पर किसी कमेटी में 6 महीने से ज्यादा की तनख्वाह कोई बाकी नहीं है। हाँ 1-2 महीने की कहीं हो सकती है और वह भी वहां के एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राऊंड की कोई बात हो सकती है लेकिन वह भी नहीं होगी। मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि जब चुंगी व्यवस्था लागू थी तब कर्मचारियों की छः महीने और साल भर की तनख्वाह रुका करती थी। आज चुंगी व्यवस्था समाप्त करने के पश्चात् हमारे हरियाणा में एक हाऊस टैक्स पॉलिसी बनायी जिसके बारे में हमारे विपक्षी भाईयों ने बहुत धुआंधार प्रचार किया और लोगों में भ्रांति फैलायी और उसमें लोगों ने भी उनका उस वक्त साथ दिया लेकिन बाद में हरियाणा प्रदेश के लोगों को पता लगा कि यह पॉलिसी हकीकत में उनकी भलाई के लिए है क्योंकि पहले लोग समझते थे कि यह जो पैसा लिया जाता है यह पैसा उनके विकास के कार्यों पर नहीं लगता। हरियाणा प्रदेश की जनता ने जब यह देखा कि हरियाणा सरकार उसका समुचित विकास करने के लिए, शहरों का सौन्दर्यकरण करने के लिए, शहरों में समुचित व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, सड़कों की व्यवस्था ठीक करने के लिए कृतसंकल्प है तब उनकी समझ में आया कि ये विपक्ष के लोग भ्रांति फैला रहे हैं। माननीय चौटाला साहब ने शहरों में तकरीबन 452 कि०मी० लम्बी सड़कों का सुधारीकरण किया। मैं इस बात को मानूंगा कि अभी सारी की सारी सड़कें नहीं सुधरी हैं। हम एक रात में या कुछ वक्त में विश्वकर्मा बन कर सभी सड़कों का सुधार नहीं कर सकते लेकिन हमारे मुख्य मंत्री जी के दिशा निर्देश हैं और हम भी प्रयासरत हैं कि हम प्रदेश के हर नागरिक को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करें और इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने हमें गाहे बगाहे निर्देश दिए हुए हैं कि जहां-जहां पानी की मार है, वे सड़कें आर०सी०सी० की बनवाई जाएं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदन के सदस्यों की जानकारी के लिए यह अवगत करवाना चाहूँगा कि आप लोगों की जानकारी में भी अनेक ऐसी कमेटियां हैं जहां पर आर०सी०सी० रोडज बनवाई गई हैं और आगे भी तारकोल की जगह पर हम दूसरी तरह की सड़कें बनवा रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, हमने हाउस टैक्स को रैशनेलाइज किया है। हमने उसको यूनिफोर्म किया है और रिकवरी का आलम यह है कि भरपूर रिकवरी हुई है। उपाध्यक्ष महोदय, आज तक 50% से ज्यादा कभी रिकवरी नहीं हुई थी वहां आज काफी रिकवरी हुई है। जो रिकवरी हुई है इसके बारे में मैं इस चार्ट में दर्ज कुछ आंकड़े यहां पर प्रस्तुत करना चाहूँगा। पंचकूला में 96.80% रिकवरी हुई है। कालका में 88.44% और पिंजौर में 76.17% रिकवरी हुई है। मांगे राम जी, आप भी वित्त मंत्री रहे हैं और वाणिज्य व्यापार आदि से सम्बन्धित रहे हैं, मैं यह आंकड़े यहां पर आपके रूबरू प्रस्तुत कर रहा हूँ, इन आंकड़ों में अगर कोई अतिश्योक्ति हो तो मैं आपको जवाबदेह हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से शाहबाद में 78%, थानेसर में 85%, पेहवा में 90.96%, लाडवा में 93.56%, पानीपत में 81.46%, समालखा में 52.78%, गुड़गांव में 93.88%, सोहना में 75.68% फिरोजपुर झिरका में 70.98%, नूह में 93.85%, मेरे अपने क्षेत्र हांसी में 86.66% टैक्स रिकवरी हुई है। मांगे राम जी, आप पूर्व वित्त मंत्री भी रहे हैं 54.58% रिकवरी आपके अपने जीन्द में हुई है इस कम रिकवरी का कारण यह है कि आप लोग रिकवरी में रुकावट डाल रहे हैं जबकि आपको इस बारे में अपेक्षित भूमिका निभानी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, इनकी सोच गलत है इसलिए इनको सही दिशा में सोचना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि यदि हरियाणा प्रदेश का समुचित विकास चाहते हैं तो सभी मिलकर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के द्वारा जो विकास के कार्य करवाए जा रहे हैं उनमें उनका सहयोग करें। हम वचनबद्ध हैं कि हरियाणा प्रदेश के शहरों को और ज्यादा सुन्दर बना सकते हैं और ज्यादा सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करते हुए आपका धन्यवाद करता हूँ तथा अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

Mr. Deputy Speaker : Now, the Finance Minister will give his reply on the Budget Estimates for the year 2003-2004.

वित्त मंत्री (प्रो० सम्पत सिंह) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इसी महीने की 10 तारीख को हरियाणा प्रदेश के बजट प्रस्ताव विधान सभा के सामने रखे थे। इन बजट प्रस्तावों पर काफी सदस्यों ने चर्चा की। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको तथा माननीय स्पीकर महोदय को बधाई देता हूँ तथा आपका तथा माननीय स्पीकर महोदय का आभार प्रकट करता हूँ कि हरियाणा असैम्बली के इतिहास के अन्दर पहली बार बजट पर लगभग 50 सदस्य बोले हैं इसके लिए आप दोनों बधाई के पात्र हैं। बड़े अच्छे माहौल में बजट पर चर्चा हुई। सिंगल सिटिंग्ज होते हुए भी पब्लिक इन्ट्रस्ट में आपने 2-2 सिटिंग जितने टाइम में हाउस का समय कन्वर्ट किया ताकि हर मैम्बर बजट प्रस्तावों पर ज्यादा से ज्यादा कन्ट्रीब्यूट कर सके, इसके अंदर अपनी बात कह सके, अपने सुझाव दे सके और अगर बजट की कोई रचनात्मक आलोचना है तो वह भी कर सकें। जो मैम्बर्ज बोले हैं उन सभी की सारी बातें मैंने नोट की हैं। डिप्टी स्पीकर सर, आप जानते हैं कि जिस किस्म के मंदी के हालात देश में चल रहे हैं, देश ही में क्या पूरे विश्व में मंदी के हालात चल रहे हैं। उससे हम भी अछूते नहीं रह सकते हैं। यह तो आज के हालात हैं। लेकिन जिन हालातों में मुख्य सेवक का पद आदरणीय ओम प्रकाश चौटाला जी ने सम्भाला था, सत्ता सम्भाली थी उसको हमने ही देखा है क्योंकि हम वहां से चल कर आए हैं, रिक्वर होकर आए हैं। आज मैं सदन में यह कह सकता हूँ कि हम आज उन हालातों से उबर चुके हैं। उस समय सारे प्रदेश की अर्थ व्यवस्था डगमगा चुकी थी, राजनैतिक अस्थिरता थी, सामाजिक ढांचा बुरी तरह से बिगड़ चुका था और सारे का सारा इन्फ्रास्ट्रक्चर समाप्त हो चुका था। ऐसे हालातों में आकर मुख्य मंत्री जी को मुख्य सेवक का पद सम्भालना पड़ा था और मैं इनके इस काम की दाद देता हूँ कि इन्होंने रात दिन मेहनत करके, एफर्टस करके इस सत्ता को सम्भाला तथा हम आज के दिन उन चीजों से उभर आए हैं। डिप्टी स्पीकर सर, जिस दिन मुख्य मंत्री का पद इन्होंने सम्भालना था उससे एक रात पहले से बहुत चिन्तित थे। आज पंचायत मैम्बर के लोग मर कट जाते हैं, एक-एक पर्ची के लिए लड़ मरते हैं, वहीं पर जिस आदमी ने प्रदेश का मुख्य मंत्री बनना हो और पहली रात यह महसूस कर रहा हो कि इन हालातों में मैं प्रदेश को कैसे सम्भालूंगा। वरना लोग तो मुख्य मंत्री के पद को प्राप्त करके खुशी मनाते हैं। लेकिन उनके दिमाग पर, उनके माथे पर चिन्ता थी कि आज जिस हालात में हमारा प्रदेश गुजर रहा है उनको कैसे ठीक किया जाए। चूंकि उनकी रगों में चौधरी देवी लाल जी का खून दौड़ रहा है कि चौधरी देवी लाल जी ने इस प्रदेश का निर्माण किया है व इस प्रदेश को अस्तित्व में लेकर आए। इस प्रदेश को आज पुनर्जीवित करना है। इस प्रदेश को आज दोबारा ऊपर उठाना है। यह उनका दायित्व था और इस दायित्व से ये चिन्तित थे। पहले चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी सोच रहे थे कि इन हालात में कैसे सत्ता सम्भालेंगे, यह दायित्व कैसे निभाएंगे। उस वक्त हम सब वहीं पर बैठे थे। तो सभी लोगों ने कहा कि आपको यह जिम्मेवारी निभानी पड़ेगी क्योंकि प्रदेश के लोगों के प्रति आपकी जिम्मेवारी बनती है। डिप्टी स्पीकर सर, हमने मुख्य मंत्री जी को यह भी कहा कि चौधरी देवी लाल जी के जो अधूरे सपने हैं और जो उनका सपना गरीबों, दलितों, किसानों और आम व्यक्ति के उत्थान के प्रति है वह आपको पूरा करना पड़ेगा। लोगों की इनके प्रति जो भावनाएं थीं उनको पूरा करने के लिए इन्होंने दिलेरी से इस पद को सम्भाला है। डिप्टी स्पीकर सर, सबसे पहले प्रदेश के सामाजिक और आर्थिक ढांचे को ठीक करने की तरफ ध्यान दिया।

[प्रो० सम्पत सिंह]

प्रदेश का राजनैतिक ढांचा बुरी तरह से बिगड़ चुका था। लोग इधर-उधर भाग रहे थे, रात को कहीं जाते थे और दिन में कहीं और जाते थे। बहुत बुरे हालात प्रदेश में हो गए थे। उसको सुधारने का काम हमारी हरियाणा की सरकार ने मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में किया है और इसका श्रेय मुख्य मंत्री जी को जाता है। जिस तरह से सामाजिक हालात बिगड़ चुके थे, भाई-बहन, मां-बाप के रिश्ते खत्म हो गए थे और रिश्तेदारियां खत्म हो गई थीं उनको ठीक किया है। लोग हाई कोर्ट में केवल रजिस्ट्री करवाने के लिए जा रहे थे क्योंकि जमीनों की डिकरियां खत्म कर दी गई थीं, कोर्टस में केसिज चल रहे थे तो हमने उन हालात को खत्म करने का काम किया है और आज यह सरकार उससे निकल कर बाहर आई है। वह सामाजिक ढांचा जो मद्य-निषेध नीति के कारण बिगड़ गया था, बाप-बेटा और मां-बेटा की शर्म खत्म हो गई थी। छोटे-छोटे बच्चे जिनके बस्तों में किताबें होनी चाहिए थी उनके बस्तों में शराब की थैलियां भरवा दी गई थी। उसको ठीक करने का काम हमारी सरकार ने किया है। डिप्टी स्पीकर साहब, इससे जघन्य अपराध क्या हो सकता है कि महिलाओं की इज्जत होनी बंद हो गई थी, उनको अपमानित करने का काम किया गया था। डिप्टी स्पीकर सर, अगर आज किसी को इल्लीगल और इजी मनी मिलती है तो आज लालायित कौन नहीं हो जाता है। ईवन स्मगलर किस्म के लोग महिलाओं को भी शराब की थैलियां छुपाकर देते थे और उनको बोर्डर पार करवाया करते थे। यूथ अगर एक बार इललीगल ऐक्टिविटीज की तरफ चला जाएगा तो उसको इललीगल ऐक्टिविटीज से इममोरल ऐक्टिविटीज की तरफ बढ़ने में देर नहीं लगेगी। वह तो वक्त रहते प्रदेश बचा लिया गया, प्रदेश को संभाल लिया गया वरना उसको इममोरल की तरफ जाने में देर नहीं लगती। डिप्टी स्पीकर सर, इस तरह के हालात उस समय प्रदेश के हो गये थे। जो छोटे-छोटे बच्चे थे जिनके ऊपर क्रिमिनल केसिज बन रहे थे उन केसिज को हमारी सरकार ने विदड्रा करके उनको मेन स्ट्रीम में लाने का काम किया क्योंकि जब तक सामाजिक ढांचा ठीक नहीं होगा, यूथ ठीक नहीं होगा, तब तक प्रदेश का विकास नहीं हो सकता, अर्थव्यवस्था में सुधार नहीं हो सकता। ऐसे हालातों में से ओमप्रकाश चौटाला जी ने प्रदेश को निकाला है। आप जानते हैं कि उस दौरान जो मद्य निषेध नीति लागू की गयी उससे मैं मानता हूं कि कुछ लोग जरूर करोड़पति बन गये, लखपति बन गये लेकिन प्रदेश कंगाल हो गया, प्रदेश का दिवालिया निकल गया और सारे विकास के काम खत्म हो गये, सब ढांचा चरमरा गया। चाहे सड़कों का हो, चाहे बिजली का हो, चाहे पानी का हो या चाहे रोडवेज का हो, हर ढांचा खत्म हो गया था। ऐजुकेशन समाप्त हो गयी थी। आप चाहे सोशल वैलफेयर का जिक्र करें, चाहें फूड एंड सप्लाई का जिक्र करें, चाहे किसान का जिक्र करें, चाहे किसान की फसल की खरीद की बात करें और चाहे आप खरीद मूल्यों की बात करें हर चीज धीरे-धीरे समाप्त होती जा रही थी। उन चीजों को लाइन पर लाने का अगर काम किया है तो वह आपकी इस सरकार ने किया है इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी है बहुत कष्ट उठाने पड़े हैं। भजन लाल जी, मुस्करा रहे हैं लेकिन इनको इन चीजों का नहीं पता। जो ये काम अपने लाभ के लिए करते हैं उनको जरूर किसी तरह की चिन्ता नहीं होती है लेकिन जब स्टेट की तरफ देखते हैं, प्रदेश की तरफ देखते हैं, लोगों की तरफ देखते हैं तो चाहे स्वाभाविक रूप से आपके पास पैसा है या नहीं, साधन है या नहीं आपको उनके लिए काम करना ही पड़ेगा। डिप्टी स्पीकर सर, ऐसी स्थिति में लोगों की जो मंशाएं हैं, लोगों की जो अपेक्षाएं हैं वह कैसे पूरी होंगी उसके लिए ही वित्तीय प्रबन्धन में हमारी इस सरकार ने सुधार किया है और ऐसे कदम उठाए हैं जिससे वित्तीय प्रबन्धन में और ज्यादा सुधार हो। सर, मैं यह नहीं कहता कि आज हम घाटे में नहीं हैं या हमारे ऊपर कर्जा नहीं है लेकिन जिस तरह की दुनिया में आज हम गुजर रहे हैं वह

ग्लोबलाइजेशन और लिबरेलाइजेशन का वक्त है। आज आइसोलूशन में हम नहीं रह सकते, आपको पूरी दुनिया के साथ जुड़कर रहना ही पड़ेगा। आज हरियाणा को केवल पंजाब या दिल्ली के साथ ही नहीं जुड़ना होगा बल्कि हरियाणा को आज अमरीका, यूरोप एवं एशियाई कंट्रीज के साथ भी जुड़ना पड़ेगा। उनसे भी आपको मुकाबला करना पड़ेगा। इस तरह की पॉलिसी आने के बाद हालात में जितना खुल्लापन आया है, उस खुल्लेपन की स्थिति में आज प्रदेश की सरकार ने श्री ओम प्रकाश चौटाला जी के नेतृत्व में काम करके जैसी स्थितियां बनायी हैं वह सराहनीय हैं। डिप्टी स्पीकर सर, यह बात मैं नहीं कह रहा हूँ बल्कि आज जो हिन्दुस्तान के अंदर 29 स्टेट्स हैं उन 29 की 29 स्टेट्स के बारे में हम कह सकते हैं कि यदि फाईनैंशियल मैनेजमैंट किसी स्टेट का बैस्ट है तो वह हरियाणा प्रदेश का है। मैं आपके सामने इसके सबूत भी दूंगा। पूरी कोशिश की गयी, हर क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने वाला संतुलित बजट बनाया गया है। चाहे बिजली की बात हो, चाहे पानी की बात हो, चाहे सड़क की बात हो या चाहे रोडवेज की बात हो, मूलभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए 43.4 परसैंट बजट का पैसा रखा गया है। मांगे राम जी कह रहे हैं कि बस्ता खोलो, मैं बस्ता ही खोल रहा हूँ। आज हरियाणा प्रदेश की जो टोटल ग्रोथ यानी जी०डी०पी० है वह 5.1 परसैंट है और जो नेशनल जी०डी०पी० है वह 4.4 परसैंट है यानी जो नेशनल जी०डी०पी० है उससे हरियाणा की जी०डी०पी० ज्यादा है। इसलिए यही कारण बजट के अच्छे संकेत का हो सकता है कि जो पहले सारा बोझ कृषि पर ही होता था। 70-80 परसैंट से फालतू लोगों का बोझ कृषि झेल रही थी यानी सारा पैसा कृषि क्षेत्र से आता था। सारा खजाना सारे का सारा कंट्रीब्यूशन किसानों का था। आज एक अच्छा सूचक है जिसको मांगे राम जी, आप तो वित्त मंत्री रहे हैं, आप जानते हैं कि टृशरी सैक्टर और सैकेण्ड्री सैक्टर ये दो

12-00 बजे

सैक्टर हैं इनमें बढ़ोतरी हो रही है, उनका कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है और वह सराहनीय है। मैंने आंकड़ों के टाइम बताया था कि जहां 1993-94 में आपका सैकेण्ड्री सैक्टर कंट्रीब्यूट कर रहा था तब वह 26.2 था आज वह 28.1 है। इसी तरह से टृशरी सैक्टर जिसे ट्रेड और मैन्यूफैक्चरिंग भी कहते हैं वह 31.3 था आज वह 40.3 हो गया है। इसका मतलब यह है कि अर्थव्यवस्था ठीक चल रही है, सुचारू रूप से चल रही है। हालांकि हमारे सामने टारगेट्स बहुत थे, समस्याएं बहुत थीं और हमारी सरकार से लोगों को अपेक्षाएं भी बहुत थीं ऐसे हालात में जो मैंने बजट पेश किया उस बजट पर कर्ण सिंह दलाल साहब ने कहा कि पहले ऐक्सपर्ट्स की राय ले लेते और मांगे राम जी ने भी यही कहा था। किसी और ने उनकी इस बात पर गौर किया हो या न किया हो लेकिन मैंने उनकी बात पर गौर जरूर किया है। मैं अर्थशास्त्री नहीं हूँ मैं क्लेम भी नहीं करता हूँ मैं तो पोलिटिकल साईंस का स्टूडैंट रहा हूँ। मुख्य मंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने मुझे यह जिम्मेदारी सौंपी थी तब भी मुझे बड़ा महसूस हो रहा था कि मैं कैसे निभा पाऊंगा। I am a learner. मेरा सीखने का प्रयास रहता है जहां से भी मुझे कुछ सीखने को मिलता है मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उसे सीख सकूं। उपाध्यक्ष महोदय, बजट के बारे में जो प्रतिक्रियाएं आई हैं उनके मैं तीन उदाहरण देना चाहता हूँ। गुप्ता जी, आप सी०आई०आई० को तो जानते हैं, आप पी०एच०डी० चैम्बर ऑफ कॉमर्स को भी जानते हैं उनके मेरे पास लैटर्ज आए हैं वैसे तो अखबारों में भी बहुत सारी टिप्पणियां आई हैं लेकिन मैं अखबारों को कोट नहीं करूंगा। जो मेरे नाम से बजट के बारे में चिट्ठी आई हैं। एक तो पी०एच०डी० यानी पंजाब, हरियाणा एंड दिल्ली के चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज जो है उनकी तरफ से चिट्ठी आई है—

[प्रो० सम्पत सिंह]

"P.K. Jain
President
12th March, 2003

Prof. Sampat Singh,
Honourable Finance Minister,
Haryana, Chandigarh

Honourable Sampat Singh Ji,

At the outset, we in the PHDCCI compliment and congratulate the State Government for presenting a balanced budget. The State Government has endeavoured to maintain a judicious balance amongst the various segments of the economy.

Rs. 700 Crores budget allocation for modernising the power transmission and distribution systems is indeed greatly appreciable. This will ensure regular and quality power supply to industry.

Switching over to state VAT from April, 2003 is also a bold initiative as this historic decision shall increase revenue in the long run, reward industry and trade complying with the law, benefit the consumers, minimize scope for evasion attract new investments on the basis of economic advantages and bring about transparency in tax administration.

We also compliment you for accepting our suggestion for rationalising the organisational structure of government departments and State PSUs. It is a healthy beginning, which will correct the fiscal imbalance.

The commitment of the State Government to introduce fiscal reforms in substantiated by the announcement to make aided higher educational institutions financially self-sustaining with new courses being self-financing.

Thanks and regards

Yours Sincerely,
P.K. Jain
President"

मांगे राम जी, आप ऐक्सपर्टस की बात करते हैं। ये सारे के सारे ऐक्सपर्टस हैं। इसी तरह से उपाध्यक्ष महोदय सी०आई०आई० की तरफ से चिट्ठी आई है जो कि मैं पढ़ देता हूं:—

"Dear Prof. Sampat Singh Ji,

Haryana Budget : 2003-2004

At the outset, I would like to congratulate you, on behalf of the entire CII Haryana State Council, on presenting a forward-looking budget at this year's Budget Session of the Haryana Assembly. We are happy to note that the Budget has outlined a slew of measures aimed at revenue mobilization, reducing expenditures and simplification of rules & procedures. This is in line with the recommendations made in our Pre-Budget Memorandum which was personally handed over to you by Mr. S.K. Bijlani, Chairman, CII Northern Region, when he called on you a few days

ago. CII had strongly recommended the rationalization of tax rates by implementing VAT on April 1, 2003, dispensation of the tax based incentives to industry and simplification of rules and procedures. We are extremely pleased to note that all these and many more such suggestions found their way through the budget.

The State has also done a commendable job of managing its finances by reducing the fiscal deficit to 3.29% of GSDP from 4.58% in the last year, according to CII Northern Region. Marginal improvement in tax-GSDP ratio, from 8.32% in last year to 8.38% in the current year, is a welcome sign nevertheless. Also praiseworthy is the reduction in salary expenditure to 48.69% of the revenue receipts from 51.24% in the last year. Such efforts at raising tax and non-tax ratios to GSDP, as well as curtailing expenditures, clearly need to be accelerated however for long-term reductions in the fiscal deficit.

We also deeply appreciate the creation of a "Consolidated Sinking Fund" and a "Guarantee Redemption Fund" by the Government for meeting payment obligation of State debt and guarantees. Additionally, the proposed measure to utilize Debt Swap Scheme of the GOI for retiring high cost central loans for Rs. 308 crores during current year with low cost loans, is what CII has consistently advocated. It will significantly reduce the burgeoning yet non-productive interest payments."

मांगे राम गुप्ता जी, आपने भी ऐडवोकेसी की थी कि महंगे इंट्रस्ट पर लोन लिया हुआ है लेकिन सस्ते इंट्रस्ट पर लोन लेकर 308 करोड़ रुपये बचाये हैं उसको मांगे राम गुप्ता जी ने एप्रिसिएट किया था।

"Some of the other proposals relating to rationalization of surplus staff in Government departments by redeployment instead of retrenchment; e-governance push via IT enabling 34 departments, and training 8000 employees; allowing private participation in infrastructure development; setting up of SEZ and FIPB for attracting foreign investment and boosting exports; comprehensive plan for diversification in agriculture, and the increased outlays for enhancing social and economic infrastructure, are also highly welcome. We in CII Northern Region and the Haryana State Council would like to work closely with the State Government for the successful implementation of these proposals.

I would like to congratulate you once again and I look forward to welcoming you at the Annual Session of the CII Haryana State Council on 25th March at Gurgaon."

और फिर ये कह रहे हैं, यह मैं नहीं कह रहा हूं आप कहेंगे कि आप तो वैसे ही कह रहे हैं ये तो देश की जो ब्रेन हैं जो इंटलैक्च्यूअल हैं जो बजट के बारे में सोचते हैं जो भविष्य के बारे में इकोनोमिक्स के बारे में सारे देश को अपने साथ जोड़ते हैं। चौधरी भजन लाल जी, आप वाला वक्त नहीं रहा अब। अब तो नये नौजवान लड़के जो प्रोफैशनल है, स्पेशलिस्ट हैं वे लोग आ गये हैं लेकिन वह बात तभी बनेगी जब आप इनके साथ चलते रहेंगे इनके पीछे लगे रहें। इसी प्रकार गुड़गांव की सी०आई०आई० की चिट्ठी आई है जिसमें लिखा है :—

[प्रो० सम्पत सिंह]

"Honourable Sir,

We in the Gurgaon Chamber of Commerce compliment and congrantlate you and your team for giving a growth orientation and reformist focus to the State Budget. Reforms in education, industrial and electricity areas are indeed appreciable. The other proposals such as implementation of VAT, rationalization of the organizational structure etc. is also very inspiring."

यह चिट्ठी इनकी आई है। तो डिप्टी स्पीकर सर, ये बातें ऐसे ही नहीं आई। फिर कई मैम्बर्ज़ ने वार्षिक योजना का जिक्र किया। अलग-अलग मैम्बर ने अपने तरीके से जिक्र किया कि वार्षिक योजना इनकी घट रही है। डिप्टी स्पीकर सर, वार्षिक योजना आपको भी मालूम है कि जब हमने सरकार संभाली थी तो 2530 करोड़ रुपये की पहली वार्षिक योजना हमें मिली और आते ही जब हमने रिसोर्सिज देखे कि ये 2530 करोड़ रुपये कहां से आयेंगे। रिसोर्सिज थे नहीं, इतना बड़ा गैप था। हम उसको रियलिस्टिक लिमिट तक लेकर आये। हम यह नहीं चाहते और दिखाना नहीं चाहते कि हमारी प्लॉन बढ़ी हो। हरियाणा पहली स्टेट होगी जिसने अपनी प्लॉन खुद जा कर करवाई हो वरना तो आज तक लोग अपने आंकड़े दिखाते रहे हैं हां ये ठीक है कि हमारी प्लॉन 25 सौ करोड़, 27 सौ करोड़ या 3 हजार करोड़ रुपये की है और अल्टीमेटली वह खातों में तो 31 मार्च के बाद सामने आ ही जाती है। हम यह नहीं चाहते थे कि इस तरह की बात करें और इनफलेटिड फिगर हम दें, नहीं। हमने उसी वक्त उसको घटाया, उसी वक्त रियलिस्टिक बनाया। पिछली बार जब हम प्लॉनिंग कमीशन के सामने अपनी 1922 करोड़ 50 लाख की प्लॉन लेकर गए थे वह अपने आप में एक इतिहास बन गया उस वक्त प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन आनरेबल पंत साहब ने 1922 करोड़ 50 लाख रुपये की बजाय 2034 करोड़ की प्लॉन बना दी उन्होंने इसलिए बना दिया कि आज हरियाणा प्रदेश प्रोग्रैसिव स्टेट है, लोग काम करें, मेहनत करें। इतना रैवेन्यू ये लोग जेनरेट करें कि Government of India उनकी मदद करेगी इसलिए उन्होंने बढ़ा दी हालांकि हमने कहा था इतना काफी है लेकिन उन्होंने इसको बढ़ा दिया हम चाहते थे कि यह पूरी हो। जो यह पूरी नहीं हुई है मैं वह रीजन भी बता देता हूँ। इसमें कमी रही है इसमें कोई दो राय नहीं है लेकिन कुछ ऐसे खर्चे आ जाते हैं जिनको निभाना पब्लिक के प्रति आपकी अपनी जिम्मेवारी है। मेरे भाई कृष्ण पाल जी बैठे हैं जो कह रहे थे कि सैंटर की तरफ से मदद आई, हां ठीक है मदद आई इसमें कोई दो राय नहीं। सैंटर में हमारी अपनी सरकार है, एन०डी०ए० की सरकार है और वाजपेयी जी देश के प्रधान मंत्री हैं। ओम प्रकाश चौटाला जी पहले नेता थे जिन्होंने चुनाव के रिजल्ट आने से पहले उनको समर्थन जारी किया था वे उनकी पूरी इज्जत करते हैं। लेकिन केन्द्रीय करों में चालू वित्त वर्ष के दौरान हमें 90 करोड़ रुपये कम मिला जो हमारा एक्सपैक्टिड था उससे 90 करोड़ रुपये कम मिला। अब उसमें हम क्या प्रयास कर सकते थे कि नहीं मिला। उनकी अपनी रिकवरी कम हुई होगी। इसी तरीके से अब पैंशन भोगियों के लिए 128 करोड़ रुपये के अतिरिक्त खर्चे की व्यवस्था करनी पड़ी। उपाध्यक्ष महोदय, भूतपूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं को दी जाने वाली वित्तीय सहायता 200 रुपये प्रतिमास से बढ़ाकर 400 रुपये प्रतिमास किए जाने के कारण 6.37 करोड़ रुपये की राशि की व्यवस्था की गई। सहकारी चीनी मिलों के गन्ना उत्पादकों की बकाया राशि हेतु 98 करोड़ रुपये ये देने पड़े अब अगर ये ना दें तो कह देंगे कि किसानों को मार दिया सहकारी मिलों को पिछले बजट वर्ष के अन्दर ये 98 करोड़ रुपये दिये।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : ये पैसा आपने उनको लोन दिया होगा।

प्रो० सम्पत सिंह : हुड्डा साहिब, ये पैसा दिया है लोन नहीं। लोन के बारे में तो आप जानते हैं कि शुगर कोआपरेटिव मिलों को जो लोन दिया जाता है, मैं बींग ए फाईनांस मिनिस्टर या और मिनिस्टर होने के नाते कहना नहीं चाहता आप ये बात खैर कह सकते हैं। जो लोन दिया जाता है वह पब्लिक इन्ट्रस्ट में है। बाद में उसका जो रिजल्ट निकलता है वह भी आपको मालूम है, मांगे राम जी को मालूम है लेकिन वह हमें किसानों के लिए देना पड़ा। जब किसान को पेमैंट हमें करनी है (विघ्न) पहले 98 करोड़ ये दिए और इसी तरह से सार्वजनिक क्षेत्र में जो प्रतिष्ठान हैं उनमें भी कर्मचारियों के लिए 92 करोड़ रुपया मुआवजे का दिया। इस प्रकार 400 करोड़ रुपये से ऊपर यह पैसा निकल जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, फिर भी प्लॉन को 1800 करोड़ रुपये के नजदीक यह सरकार रख दे तो यह सरकार की हिम्मत है। हमने पब्लिक इन्ट्रस्ट के लिए पैसा खर्च किया वैसे नहीं किया कि इधर-उधर पैसा खर्च कर दो। वार्षिक योजनाएं जो अब हमने रखी हैं वह 21 सौ करोड़ रुपये की रखी है। इसमें पिछले साल के 1800 करोड़ के मुकाबले में 16.7 प्रतिशत अधिक है, उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह भी आपको बताया कि हम ज्यादा खर्चा बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर को डिवैल्प करने पर लगा रहे हैं जोकि ग्रोथ ओरियंटिड होगी जिससे कल को आमदनी होगी। उपाध्यक्ष महोदय, आज सरकार सड़कें बना रही है ट्रांसपोर्ट के अन्दर बसें खरीद रही है, आज बिजली का इन्फ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहे हैं, आज पानी की सुविधाओं के लिए Modernization of Canals जो हैं उनको बढ़ा रहे हैं इससे आपकी ग्रोथ होगी आपकी इनकम बढ़ेगी। यह कर्जा ऐसा है जिससे इनकम जैनरेट होगी ताकि कर्जा चुकाया जा सके। अगर फिजूल खर्चे के लिए आप कर्जा लेते हैं तो गलत बात है जैसे एक आदमी अपनी फसल उगाने के लिए कर्ज लेता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, कारखाना चलाने के लिए कोई कर्ज लेता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन ब्याह शादी के लिए या दारू पीने के लिए कोई कर्जा लेता है तो वह डूबता है। हमने बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर डिवैल्प करने के लिए कर्जा लिया है और इसको बढ़ाया भी है और हर साल बढ़ाते रहे हैं जैसे पहले यह 42.13 प्रतिशत था, रिवाईज करके 43.26 प्रतिशत किया है और इस बार 43.4 प्रतिशत किया है। शुरू में जब हम चले थे 2001-2002 में तो यह 38.37 था इसको हमने बढ़ाया है। इसके साथ-साथ सामाजिक सुरक्षा सबसे जरूरी है। चौ० देवी लाल जी का यह सपना था कि बुजुर्गों, विधवाओं और अपंगों को सामाजिक सुरक्षा मिलनी चाहिए। उनके एक आदेश, उनकी एक इच्छा पर सरकार ने उसको दुगुना कर दिया। आज 330 करोड़ रुपये की पेमैंट सोशल वैलफेयर के लिए स्टेट एक्सचैकर से निकल रही है। डिप्टी स्पीकर सर, ये तो योजनागत खर्च हैं इसके अतिरिक्त एच०आर०डी०एफ० के तहत भी हरियाणा प्रदेश के गांव-गांव का विकास हो रहा है। चाहे किसी गांव में शीशे जैसी सड़क बनाने की बात है, चाहे गांव की गलियां पक्की करने की बात है या कोई दूसरे विकास कार्य करने की बात है ये काम आज के दिन एच०आर०डी०एफ० के तहत किए जा रहे हैं। मैं इस बारे में ज्यादा न बताते हुये आंकड़े बताना चाहूँगा कि जिस दिन से, 24 जुलाई, 1999 से माननीय मुख्य मंत्री जी चौटाला साहब की सरकार बनी है उस दिन से लेकर 28.2.2003 तक एच०आर०डी०एफ० के तहत 445.19 करोड़ रुपये हरियाणा में विकास कार्यों पर खर्च किए गये हैं। जबकि चौधरी बंसी लाल जी के तीन साल के कार्यकाल में एच०आर०डी०एफ० के तहत केवल 141 करोड़ रुपये खर्च हुए थे। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारे समय में साढ़े तीन या चार गुणा अधिक पैसा खर्च करके विकास कार्य किए गये हैं। डिप्टी स्पीकर सर, हमें केन्द्र से काम के बदले अनाज योजना के तहत जो अनाज मिलता है उसके बारे में मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को बताना चाहूँगा कि यह स्कीम हमारे यहां माननीय मुख्य मंत्री जी के प्रयासों से शुरू हुई थी। इस स्कीम के तहत हमारे लिए जो अलौटिड अनाज था हमने उससे अधिक लिया है और इस बार सैकिंड एडीशनलिटी भी ले रहे हैं

[प्रो० सम्पत सिंह]

तथा हरियाणा प्रदेश पहला प्रदेश होगा जो यह काम कर रहा है। डिप्टी स्पीकर सर, इसी तरह से विपक्ष के भाइयों ने बजट घाटे के बारे में बात की कि घाटा बहुत हो गया, इसको कैसे पूरा किया जायेगा और भी कई बातें इस बारे में इन्होंने कहीं। इस बारे में मैं इनको बताना चाहूँगा कि इनको यह भी सोचना चाहिए कि 1997 में एक रुपये की वैल्यू क्या थी और आज क्या है ? डिप्टी स्पीकर सर, 1997 में 104.55 करोड़ रुपये और 1998-99 में 150 करोड़ रुपये का बजट घाटा था और यह बढ़ते हुए अब 780 करोड़ रुपये रिवाईज्ड एस्टीमेट्स में हो गया। लेकिन इस बार हमारे द्वारा पहली बार प्रयास किया गया है कि इस बार इस बजट घाटे को 780 करोड़ से कम करके 670 करोड़ रुपये पर लाया जाये। हमारे से पहले किसी ने इसे कम करने का प्रयास नहीं किया। इसके लिए इन्हें हमारी सराहना करनी चाहिए। डिप्टी स्पीकर सर, इसके अलावा और भी वित्तीय एडीशनल्टिज हैं जो प्लॉन से निकलती हैं। इन छोटी-छोटी बातों के बारे में मैं यहां क्या बात करूं लेकिन इनमें से एक बात बहुत महत्त्व की है जनता के लिए कि 6.37 करोड़ रुपये हमारी सरकार ने एडीशनल असैसमैंट एक्स-सर्विसमैन और उनकी विधवाओं को पैंशन देने के लिए की है जहां पहले भूतपूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं को 200 रुपये प्रति माह पैंशन मिलती थी उसको हमने 400 रुपये प्रति माह करने का काम किया है। मेरे कहने का मतलब यह है कि आज पब्लिक इंट्रस्ट के सारे काम हो रहे हैं। डिप्टी स्पीकर सर, हुड्डा जी ने कह दिया कि बजट घाटे को पूरा करने के लिए सरकार टैक्स लगायेगी और पिछली बार भी एल०ए०डी०टी० लगा दी गई थी, स्टैम्प ड्यूटी बढ़ा दी थी, यात्री टैक्स बढ़ा दिए थे। इस बारे में मैं बताना चाहूँगा कि एल०ए०डी०टी० बढ़ाई नहीं गई बल्कि 4 प्रतिशत से कम करके 2 प्रतिशत की गई है। Not less than the status of Leader of the Oppossion भूपेन्द्र सिंह हुड्डा साहब को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी कोई और ऐसी बात करता तो कोई बात नहीं थी लेकिन हुड्डा साहब ऐसी गलत बात करें यह ठीक नहीं है। डिप्टी स्पीकर सर, इसके अतिरिक्त मैं यह भी बताना चाहूँगा कि इस साल न स्टैम्प ड्यूटी बढ़ाई गई और न ही यात्री टैक्स बढ़ाया गया। इनको इस तरह की गलत बात नहीं करनी चाहिए। डिप्टी स्पीकर सर, जहां तक बजट घाटे को पूरा करने की बात है, इस बारे में मैं चौधरी भजन लाल जी को, हुड्डा जी और गुप्ता जी को बताना चाहूँगा कि इसका हमने दूसरा तरीका ढूंढ लिया है। डिप्टी स्पीकर सर, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जिन लोगों ने हरियाणा में नाजायज कब्जे सरकारी जमीन पर कर रखे हैं वह 12595 एकड़ 2 कनाल और एक मरला है। वे कब्जे हम हटवा रहे हैं। ये कब्जे दूर होते ही हमारा घाटा अपने आप एक मिनट में दूर हो जायेगा। इस बारे में मैं विपक्ष के साथियों से भी निवेदन करूंगा कि वे सरकार का साथ दें, सरकार की मदद करें। (शोर एवं व्यवधान)

एक आवाज : डिप्टी स्पीकर सर, क्या ये उस जमीन को बेचकर घाटा दूर करेंगे ?

प्रो० सम्पत सिंह : गुप्ता जी, उस जमीन को बेचेंगे नहीं, वहां पर इन्फ्रास्ट्रैक्चर डिवैल्प करेंगे, मार्किटिंग एक्टीविटीज डिवैल्प करेंगे, रैजिडैंशियल और ऐग्रीकल्चर एक्टीविटीज डिवैल्प करेंगे। जब ऐसी एक्टीविटीज डिवैल्प करेंगे तो अपने आप इनकम होगी। मैं कहता हूँ कि और कोई टैक्स लगाने की जरूरत नहीं है, इसी से घाटा पूरा हो जायेगा। गुप्ता जी, 11वें वित्त आयोग ने जो सुजैशन सभी स्टेट्स को दिए हैं उसी नीति पर सरकार चल रही है। उसी नीति पर हम चल रहे हैं। उसी नीति की पालना करते हुए जो जरूरी पद नहीं हैं उन्हें नहीं भर रहे और जो जरूरी हैं उनको बाकायदा भर रहे हैं ताकि सरकार का काम न रुके, विकास के काम न रुकें। जिस किसी पद की जरूरत होगी उसकी भर्ती करेंगे। हमने अब तक 29 हजार पदों की भर्ती की है और गैर जरूरी भर्ती नहीं करेंगे। रैशनेलाईजेशन हो रही है। आल मोस्ट हर डिपार्टमैंट में रैशनेलाईजेशन हो रही है और उससे और

पद लाये जा रहे हैं। अभी तक 20 हजार पदों का पता लगा है उनकी नियुक्ति की जायेगी। वेतन व्यय भी कम हुआ है। हमारा वेतन खर्च जो पिछले वर्ष राजस्व प्राप्तियों का 51.24 था वह अब 48.69 पर आ गया। मैं इस वक्त के वेतन खर्च का ब्यौरा बताना शुरू नहीं करूंगा। मैं 1998-99 से बताना शुरू करूंगा जब हमने सरकार सम्भाली थी। उस वक्त वेतन पर 65.88 परसैंट खर्च आ रहा था। इसको घटाते-घटाते हम 48.69 पर ले करके आये हैं। इससे पता चलता है कि हमने कितनी बचत की है। उपाध्यक्ष महोदय, कोई काम सफर न करे उस बारे में भी मैं बताना चाहूँगा। इस बारे में 27 फरवरी के इकोनोमिक टाइम्स अखबार में लिखा है कि स्टेट्स की क्या पोजीशन हो रही है। कुछ स्टेट्स में तो पैंशन तनख्वाहों से भी ज्यादा बढ़ रही है। इस अखबार में इस खबर का हैडिंग है "State sit on pension power cake" यह हालत हो रही है और उसमें और एग्जाम्पल दिया है आर०बी०आई० के मुताबिक Study of State finances by RBI reveals a troubling story last year 30,000 retired school teachers in West Bengal took to the streets because the Government failed to pay their pension. 30 हजार कर्मचारियों को वैस्ट बंगाल सरकार पैंशन नहीं दे पायी जिससे वे लोग सड़कों पर आ गए और वहां के वित्त मंत्री ने कहा कि हमारी लायबिलिटीज 1200 करोड़ रुपये की हैं जो हमारे बस की बात नहीं हैं। मुझे पिछली बार केरल में जाने का मौका मिला। उस वक्त ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर अरोड़ा साहब भी मेरे साथ थे। वहां पर तीन महीने से मुलाजिम स्ट्राइक पर थे, उनको तनख्वाह नहीं मिल रही थी। आप जानते हैं कि वहां पर यूनियन बहुत मजबूत है। यदि वहां पर सरकार में लैफटिस्ट आते हैं तो इन्टक का और यदि कांग्रेस आती हैं तो सीटू का बहुमत होता है। वहां पर एंथनी जी बुद्धिजीवी मुख्य मंत्री हैं। उन्होंने कहा कि हड़ताल करो आपकी मर्जी है परन्तु मेरे पास देने के लिए पैसा नहीं है 31 मार्च तक। उन्होंने कहा कि मैं अपनी प्लॉन 20 परसैंट कर पाया हूँ, यदि पूरी तरह से काम नहीं हो पाया तो मैं फाईनैंस कमीशन से प्रताड़ित होऊंगा और मेरी सैंट्रल एड बन्द हो जायेगी और मेरी सारी प्लॉन खत्म हो जायेगी। इसलिए मैं 31 मार्च तक पैसा नहीं दे सकता। आपने इस काम के लिए आना है तो 31 मार्च के बाद आना। बाद में इस बात पर वहां के कर्मचारियों को मानना ही पड़ा। यह उस स्टेट की पोजीशन है लेकिन हरियाणा प्रदेश में विशेषकर मुख्य मंत्री जी के दिशा निर्देश में मिल रही नीतियों के कारण कर्मचारियों को एक दिन भी तनख्वाह या पैंशन के बिना नहीं रखा गया यानि इनकी पेमैंट लेट नहीं हुई। यहां पर कर्मचारियों को पे व पैंशन टाइम पर मिल रही है। यदि एक तारीख को छुट्टी हुई तो 30-31 को पे मिली है और फरवरी का महीना है तो 28 तारीख को भी पे मिली है। इसी तरह से पैंशन भी सही समय पर मिल रही है। पैंशन में कोई डिले नहीं हुई। यहां पर मैं बताना चाहता हूँ कि जो कर्मचारी रिटायर होते हैं उनके बैनिफिटस भी देने के लिए टाइम बाऊंड किया हुआ है ताकि कर्मचारियों को पहले की तरह लटकना न पड़े। यह सरकार कर्मचारी हितैषी है और उनका बराबर पूरा ध्यान रखा जाता है। डिप्टी स्पीकर साहब, जो घाटा बढ़ रहा था उसको कंट्रोल किया है। आप सुन कर हैरान होंगे कि जब हम शुरू में प्लॉनिंग कमीशन के पास गए और मुख्य मंत्री जी साथ गए तो हम प्लॉनिंग कमीशन से सुनकर हक्के-बक्के रह गए। उन्होंने बताया कि हरियाणा में 1000 पर 16 मुलाजिम हैं और देश की एवरेज 4-6 के करीब बैठती है। चाहे यू०पी० की सरकार है, या दूसरी स्टेट्स हैं उनकी बातें भी मैं बताना चाहता हूँ। पंजाब जो हमारा बड़ा भाई है वहां पर उनकी पोजीशन साढ़े चौदह परसैंट के आसपास है और राजस्थान नैक्स्ट है जहां की थर्ड पोजीशन है। वहां पर 8 प्वायंट समथिंग है। मेरे कहने का मतलब यह है कि हमारा इन्फ्रास्ट्रैक्चर बढ़ा है क्योंकि हमारा सिस्टम बढ़िया है। इस वक्त हमारी सरकार 3332 करोड़ रुपये मुलाजिम के वेजिज पर खर्च कर रही है। बिहार सरकार में 1432 करोड़ रुपये

[प्रो० सम्पत सिंह]

खर्च किए जा रहे हैं। जबकि वह हमारे से बहुत बड़ी स्टेट है। इस प्रकार से आंध्र प्रदेश भी हमारे से कई गुणा बड़ा है, वहां पर कर्मचारियों की तनख्वाह पर 1789 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। केरल में 84 करोड़ रुपए और तमिलनाडु जोकि बहुत बड़ी स्टेट है उसमें 1982 करोड़ रुपये वेतन में जा रहा है। हमारे यहां इतने बड़े वेजिज जा रहे हैं उसके बावजूद भी आज हरियाणा प्रदेश में चहुंमुखी विकास हो रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, यह तो कोई न कोई अजूबा ही है वरना यह कैसे हो सकता है यह तो एक करिश्मा ही है। इस चहुंमुखी विकास का सारा का सारा श्रेय माननीय मुख्य मंत्री जी को जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, यह राजस्व लक्ष्यों की प्राप्ति के कारण ही हुआ है। सी०आई०आई० और चैम्बर्ज ऑफ कॉमर्स के सभी भाइयों की तरफ से जो चिट्ठियां आई हैं उनमें से एक तो मैंने पढ़ कर सुना ही दी है कि किस-किस प्रकार सारा कुछ हुआ है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि यह जो इन्होंने कहा है कि जो यह गैप रखा है इस बार रैवेन्यू रिसीट इतनी है आगे इतनी बढ़ कर आपकी हो जाएगी, तो क्या आप नये टैक्स लगाएंगे इसलिए आप रैवेन्यू रिसीट बढ़ा रहे हैं। तो मैं इनको बताना चाहूँगा कि ऐसी बात नहीं है। हुड्डा साहब, यह सब नये टैक्सिज की वजह से नहीं है। जो मैनेजमैंट है, जो ऐडमिनिस्ट्रेशन है अगर वह आपके काबू में है, आपके अपने हाथ में है तो व्यापारी, ट्रेडर, मैन्यूफैक्चरर्ज, इण्डस्ट्रियलिस्टस और पब्लिक आपको स्पोर्ट करती है तो आपका बढ़ता है अन्यथा नहीं बढ़ता है। 1998-99 में जब चौधरी बंसी लाल जी की सरकार थी और विरासत में हमें जिस किस्म की सरकार मिली थी उसमें 3% सेल्ज टैक्स में इन्क्रीज थी और वह 3% भी जैसे थी वह भी मैं बता देता हूँ। गुप्ता जी, आप तो इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं और जानते हैं कि फिगर्ज में कैसे हेरफेर करते हैं। अप्रैल का पैसा मार्च में लेकर अप्रैल के टैक्सिज 3% मार्च में लेकर यह किया गया था अदरवाईज वह माईनस एक परसैंट पर आ रहा था उस समय टैक्सिज की रिकवरी की यह पोजीशन थी। हमारी सरकार आने से पहले यह पोजीशन थी कि सेल्ज टैक्स की रिकवरी माईनस एक परसैंट थी। उपाध्यक्ष महोदय, इसका मतलब यह है कि सरकार पब्लिक से कट ऑफ हो गई थी, व्यापारी, ट्रेडर, मैन्यूफैक्चरर्ज और इण्डस्ट्रियलिस्टस से बिल्कुल कट हो गई थी। सरकार अपने प्रशासनिक अधिकारियों से बिल्कुल कट ऑफ हो गई थी। उपाध्यक्ष महोदय, उन कट ऑफ चीजों को जोड़ना आसान काम नहीं था उन सबको इकट्ठा करना और पब्लिक में विश्वास पैदा करना। ट्रेडर्ज में विश्वास पैदा करना, उनको इन्सैंटिव देना, अपने मुलाजिमों की पीठ थपथपाना, इन सारी बातों को मिला कर मुलाजिमों की मेहनत की वजह से ट्रेडर्ज के सहयोग की वजह से, मैन्यूफैक्चरर्ज और इण्डस्ट्रियलिस्टस सब के सहयोग की वजह से और माननीय मुख्य मंत्री जी के कुशल नेतृत्व की वजह से उनके आशीर्वाद से हरियाणा प्रदेश में आगे जो इन्क्रीज हुई है, 23% फिर 30%, फिर 14.5% फिर 12.5% और फिर 15% इन्क्रीज हुई है। मेरे कहने का मतलब यह है कि सारा पैसा जो था उस समय की सरकार में अविश्वास की वजह से नहीं आ रहा था। ऐसी बात नहीं है कि पैसा आता नहीं था पैसा आ जरूर रहा था लेकिन व्यापारी, ट्रेडर, मैन्यूफैक्चरर्ज, इण्डस्ट्रियलिस्टस का जो अपना टैक्स का पैसा होता है वह अपना हिसाब रखता है कि कहां पर देना है। वह फिर सरकार पर निर्भर करता है कि पैसा प्राइवेट जेब में रखे या पब्लिक एक्स चैकर में जमा करवाये, यह सब सरकार पर निर्भर करता है। उस वक्त जो भी सरकार होगी उस पर डिपैंड करेगा। इससे आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि सारे का सारा सौदा बंद हो गया था। हम मानते हैं कि एक्साईज का कम हो गया क्योंकि प्रोहिबिशन था लेकिन सेल्ज टैक्स की रिकवरी का माईनस में जाना एक बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात थी। आज सरकार का एक-एक पैसा पब्लिक की जो मनी है वह सारी की सारी सरकारी खजाने

में जाती है न कि प्राइवेट लोगों की जेबों में जाती है। उपाध्यक्ष महोदय, इस वजह से यह सारे का सारा बढ़ा है। इसके लिए मैं अपने सरकारी अधिकारियों, ट्रेडर्ज को और सभी टैक्स पेयर्ज को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने एक अच्छा माहौल बनाया इसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, फिर केन्द्रीय सहायता की बात आई। (विघ्न) केन्द्रीय सहायता के लिए फाईनैंस कमीशन बैठता है मदद देने के लिए कि किस स्टेट को कितना हिस्सा मिलेगा। डिप्टी स्पीकर सर, हमें पहले जो राशि मिलती थी वह केन्द्रीय करों में हिस्से के मुताबिक मिलती थी। मैं विशेषकर अपने साथी श्री कृष्णपाल गुर्जर जी को बताना चाहता हूँ कि केन्द्रीय करों में पहले हमें 1.238% मिलती थी और क्योंकि बैटर परफौरमैंस हमने कर ली और हरियाणा प्रदेश के लोगों को हमने तरक्की में आगे बढ़ा लिया और हरियाणा प्रदेश का हमने विकास कर लिया। इसलिए विकसित प्रदेशों को प्रताड़ित करने का एक फार्मूला केन्द्र सरकार ने बना लिया और बीमार स्टेट्स की मदद करने के लिए जुट गए। जो बीमार स्टेट्स हैं जिनकी माली हालत खराब है चाहे मध्य प्रदेश और चाहे बिहार है या कोई और स्टेट है, हर बीमार स्टेट को अतिरिक्त पैसा देना शुरू कर दिया और जो प्रगतिशील प्रदेश हैं इस फैसले से उनको चोट लगी है और हमारा हिस्सा रह गया है .944%। कहां डिप्टी स्पीकर सर, घाटा 1.238% और कहां पर घाटा .944% रह गया। यह हमारा घटा है और जो 2000–2005 की पंचवर्षीय योजना का शेयर 1100 करोड़ रुपये कम मिलेगा। यह एड का नुकसान हुआ है। पिछले साल एक सौ करोड़ रुपये कम हो गया और इस साल 90 करोड़ रुपये कम हो गया। हमारे रिसोर्सिज को कट करते जा रहे हैं। गवर्नमैंट ऑफ इण्डिया ने सोच लिया है कि स्टेट का क्या है, स्टेट ने तो कुछ बोलना है नहीं, काटते जाओ। डिप्टी स्पीकर सर, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा और यह बहुत सीरियस ईशू है कि पेट्रोल पर सैस लगा है। पेट्रोल की सेल स्टेट के अन्दर होती है उस पर एक रुपए का सैस लगा दिया, अच्छी बात है। इसके लिए फार्मूला बनाया गया है कि पेट्रोल से जो आमदनी होगी इसका 50 प्रतिशत गवर्नमैंट ऑफ इण्डिया को और 50 प्रतिशत स्टेट गवर्नमैंट को मिलेगा क्योंकि गवर्नमैंट ऑफ इण्डिया को भी नैशनल हाई–वेज की मरम्मत पर खर्चा करना पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारी स्टेट से पिछले साल 285 करोड़ गए थे और उस हिसाब से हमें उस 285 करोड़ रुपये का कम से कम 142.50 करोड़ रुपये मिलने चाहिएं थे लेकिन वही फार्मूला बीमार स्टेट का और प्रगतिशील स्टेट का हो गया। टोटल में से आधा बांट तो दिया लेकिन वह बीमार स्टेट्स को चला गया है और हमें 25 करोड़ रुपये ही मिले हैं, हमें सवा सौ करोड़ रुपए की चपेड़ लगी है। हमारे मुख्य मंत्री जी ने प्रधान मंत्री जी से और जसवन्त सिंह जी से रिक्वैस्ट करी थी और उन्होंने इनकी बात को मान भी लिया और खाद के बढ़े हुए दाम वापिस ले लिए हैं इसके लिए हम उनके धन्यवादी हैं और मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। (विघ्न) जहां तक डीजल के दामों की बात है तो इसमें 50 पैसे सैस के बढ़ाए हैं और यह भी रोड सैस है। (शोर एवं व्यवधान) लेकिन मेरा यह कहना है कि ये जो यूजर्ज चार्जिज हैं उनको वापिस लेने पड़ेंगे, कोई सरकार चाहे आपको खुल कर कहे कि यूजर्ज चार्जिज न लेने से विकास होगा तो ऐसा नहीं है। अगर यूजर्ज चार्जिज वापिस नहीं लेंगे तो विकास नहीं होगा। आज जितने भी विकासशील देश हैं वहां पर यूजर्ज चार्जिज लगाए जाते हैं, चाहे यूरोप में जाएं या अमेरिका में जाएं वहां पर कितने ही डालर गाड़ियों के डैश बोर्ड में रखे हुए होते हैं क्योंकि उनको जगह–जगह पर टोल टैक्स इत्यादि देना पड़ता है। वह क्यों देना पड़ता है क्योंकि वहां के लोगों को सर्विसिज मिलती है तो सर्विस चार्जिज तो देने ही पड़ेंगे। लेकिन ये कहते हैं कि इस 50 पैसे से पेट्रोल से फालतू रैवैन्यू आएगा। क्यों? क्योंकि डीजल की कंजम्पशन पेट्रोल से ज्यादा है, 70/30 प्रतिशत के करीब है। अगर यह पैसा आएगा तो हम कोशिश करेंगे कि हमें 50

[प्रो० सम्पत सिंह]

प्रतिशत हिस्सा मिल जाए अगर यह मिल गया तो काम बन जाएगा। डिप्टी स्पीकर सर, इन्होंने खाद के रेट की बात करी है और किसी ने मुख्य मंत्री जी से शंका व्यक्त करी है ये खाद के रेट कैसे घटेंगे। तो इन्होंने कहा कि खाद के रेट घटेंगे। उसने फिर कहा कि कैसे घटेंगे तो मुख्य मंत्री जी ने कहा कि मुझे घटाने आते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि अगर इन्होंने कह दिया कि घटेंगे तो घटेंगे। डिप्टी स्पीकर सर, यह जो कर्जे की बात है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि कर्जे बढ़ रहे हैं। अगर विकास करेंगे, इन्फ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेंगे तो कर्जे बढ़ेंगे ही। मैंने ये फिगर्ज रात को बड़ी मेहनत करके बनाई हैं मेरे पास कोई बनिया नहीं था लेकिन मेरा हिसाब ठीक है। 31-3-1996 में कर्जा 4235 करोड़ रुपये था, 1997 में 4814 करोड़ रुपए था। यह 13.7 प्रतिशत बढ़ा था जब बंसी लाल जी ने सरकार सम्भाली थी। 31-3-1998 को 5642 करोड़ रुपये कर्जा बढ़ा था यह 17.4 प्रतिशत इन्क्रीज हुआ था। फिर 6808 करोड़ रुपये कर्जा हुआ और यह 21.2 प्रतिशत एक साल में बढ़ा है। 13 से 21 प्रतिशत तीसरे साल में बढ़ा और हमारे राज में 22 से 25 प्रतिशत तक बढ़ा है यानि कि 3 प्रतिशत इन्क्रीज हुई है मांगे राम जी। यह बड़ी कम्युलेटिव है। 31-3-2000 का 12129 है। ये आंकड़े आपके पास भी हैं कोई छुपे हुए नहीं हैं। यह जो मैं पढ़ रहा हूँ यह पब्लिक डाकुमैंट है। कोई सम्पत सिंह का डाकुमैंट नहीं है। कहां इन्होंने 13.7% से 21.2% यानि कि 8% तीन साल में फालतू कर्जा लिया है। हमने तो 22% से 25% लिया यानी तीन परसैंट फालतू लिया। हम कर्जा चुकाने की हैसियत भी रखते हैं। हम कैपिटल असैटस तैयार कर रहे हैं। हमारा बजट ग्रोथ औरिएन्टिड बजट है इसलिए यह इसको और घटाएगा। डिप्टी स्पीकर सर, इसमें जो ऋण शामिल हैं उनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। पिछली सरकारें ऊंची ब्याज दे रही थीं लेकिन अब तो जैसा मैंने कहा कि कम ब्याज वाली राशि लेकर कुछ तो ऋण हम चुकता करेंगे। हमने 300 करोड़ रुपये से ऊपर चुकता किया भी है। अच्छी बात इसमें यह है कि सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 27 परसैंट कर्जा है जोकि प्रबन्धनीय सीमाओं में है जबकि पंजाब में यह 40 परसैंट है और दूसरे स्टेट्स में यह तीस परसैंट है लेकिन हरियाणा में 27 परसैंट ही है इसलिए मैं कह रहा था कि Haryana is the best financially-managed State. इन्हीं आंकड़ों के आधार पर मैं कह रहा था। डिप्टी स्पीकर सर, इसी तरह से डैटस स्कीम हमने लागू की है और ऋण निवारण कोष की भी स्कीम हमने लागू की है तो इन सब चीजों से यह पूरा हो जाएगा। गुप्ता जी को चिन्ता करने की जरूरत नहीं है इसी तरह से utilization of funds under rural development scheme by different States. लगातार दो साल से रूरल डिवैल्पमैंट पर जितनी सैंट्रल स्पोंसर्ड स्कीम्ज हैं उनको लागू करने का जो परसैंट है वह देश में सबसे हाईएस्ट है वह 100 परसैंट से भी ऊपर है। इसलिए हरियाणा सरकार इसके लिए बधाई की पात्र है। जहां तक काम की बात है काम का तो कमाल ही हो गया। गुप्ता जी, आप हैरान होंगे कि 'सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम के खर्च का जो ब्यौरा है वह मैं आपको बता देता हूँ। 5255 करोड़ रुपये 'सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम में हैं। यह राशि थोड़ी नहीं है। यह राशि तो मोटे-मोटे हैड की है इसमें छोटे-मोटे काम जैसे कहीं टूटी लग गयी, कहीं शमशान घाट की चारदीवारी बना दी वह इसमें शामिल नहीं हैं। इसी तरह से हुड्डा साहब ने जिक्र किया कि ऐग्रीकल्चर का बजट कम कर दिया। डिप्टी स्पीकर सर, एग्रीकल्चर का बजट कम नहीं है। इन्होंने एक फिगर बताई और कहा कि वर्ष 2000-2001 में एग्रीकल्चर पर 951.84 करोड़ रुपये खर्च किए दिखाए हैं और 2003-2004 में 576.61 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है तो क्या इस साल एग्रीकल्चर का बजट कम किया है? लेकिन मैं इस फिगर्ज को क्लीयर करना चाहता हूँ। यह क्यों था यह इसलिए था कि expenditure due to slow

lifting of food stocks by FCI thus a backlog of Rs. 55.50 crores in the year 2000-2001 and Rs. 487 crores in the year 2001-2002. इस वजह से था। सर, ये यही फिगर्ज पढ़ रहे हैं लेकिन इन्होंने कोरसपोंडिंग पीरियड को नहीं देखा है। हर साल ऐग्रीकल्चर पर बजट बढ़ा है। इसी तरह से इरिगेशन पर, पावर सैक्टर पर हर चीजों पर बजट बढ़ाया गया है। सर, ये कहां से स्टेटिस्टिकल डाटा ले आते हैं इससे काम नहीं चलेगा। इन्होंने यह भी कहा इंडस्टीज के अंदर कनैक्शन रिड्यूस हुए हैं और इंडस्ट्रीज बढ़ी नहीं है इंडस्ट्रीज कम हुई हैं। सर, इन्होंने अपने आंकड़े कनैक्शन के आधार पर बता दिए हैं और कहा है कि अब 62314 कनैक्शन रह गये हैं इसलिये इन्होंने कहा कि इंडस्ट्रीज घटी है। डिप्टी स्पीकर सर, और कारण तो गए दूर सबसे बड़ी बात मैं इनको बता दूं। इसका खामियाजा तो आज तक एच०एफ०सी० के ओफिसर्ज भुगत रहे हैं। केवल एच०एफ०सी० का पैसा खाने के लिए पोलिटिकल लोगों से मिलकर लूट मचा रखी थी। अपनी इंडस्ट्रीज की रजिस्ट्रेशन तो लोग करवा लेते थे लेकिन अपनी इंडस्ट्री नहीं लगाते थे। उससे पैसा ले लिया, लेकिन इंडस्ट्री लगी नहीं और वे पैसा खा गए तो इसलिए अब इस तरह के नम्बर्ज खत्म हो गये हैं और ये उन्हीं नम्बर्ज का जिक्र कर रहे हैं। जो आज स्टेट में इंडस्ट्रियल पावर कंजम्पशन है उससे आप अंदाजा लगायें कि कितनी इंडस्ट्रीज बढ़ी हैं। इंडस्ट्रियल कंज्यूमर इन्क्रीज होकर 2882 हुए हैं। 1998 में यह दिसम्बर के अंत तक 3825 हो गये थे। अब तीन महीनों के आंकड़े नहीं हैं। इसी तरह से इंडस्ट्रियल पावर कंजम्पशन लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में 1998-99 की तुलना में 2001-2002 में 35.69 परसैंट बढ़ी है। **(इस समय श्री अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए)** इसका मतलब इंडस्ट्रीज बढ़ी हैं तभी जाकर 35 परसैंट से फालतू कंजम्पशन बढ़ी है। इसी तरह से 153 लार्ज एवं मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज और 4127 स्माल स्केल इंडस्ट्रीज लगी हैं जिसमें 8 हजार करोड़ रुपये की इन्वैस्टमैंट लगी है और जिनमें एक लाख अड़सठ हजार लोगों को रोजगार मिला है। अध्यक्ष महोदय, मैं इंडस्ट्रीज के बारे में एक बात और बताना चाहता हूँ। विपक्ष के साथियों ने फौरेन टूर का भी जिक्र कर दिया कि विदेशों में मुख्य मंत्री जी टूर पर जाते हैं। क्यों न जाएंगे। अपने प्रदेश के हित के लिए जाना पड़ेगा तो जाएंगे। आज भी मुख्य मंत्री जी सुबह 5 बजे उठकर रात के दो बजे तक गांव हो या शहर, हर आदमी की दुख तकलीफ और दर्द सुनने के लिए उसके घर दरवाजे पर जाते हैं। विदेशों में प्रदेश के नाम के लिए गए थे। जिस प्रदेश का नाम खत्म हो गया था। हिन्दुस्तान के मैप पर हरियाणा प्रदेश का नाम ही नहीं था आज यह नाम दुनिया के नक्शे पर आ चुका है कि हरियाणा प्रदेश भी कोई प्रदेश है। इसके लिए मैं आदरणीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देता हूँ। That is the best destination in the investment. यह मैं नहीं कहता यह जापानीज कम्पनी के, कोरियन कम्पनी के और दूसरी बड़ी-बड़ी मल्टीनेशनल कम्पनियों के लोग कहते हैं। हर कांफ्रैंस में यह बात कहते हैं सी०आई०आई० वाले कोई कांफ्रैंस करते हैं या पी०एच०डी० चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज वाले करते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाले कोई कांफ्रैंस करते हैं तो कहते हैं कि हरियाणा प्रदेश में उद्योग लगाने में फायदा है। यही नहीं एक जगह तो एक जापानीज जिसे हमारे प्रदेश का नाम पता नहीं था वह अपनी भाषा में कहने लगा कि ये जो ग्रीन टरबन वाले हैं इनकी स्टेट में उद्योग लगाने में फायदा होगा। इस तरह की बातें अब होने लगी हैं, इससे बढ़कर हमारा और क्या सौभाग्य होगा। अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी किसी बीमारी का इलाज करवाने या दूसरे कामों के लिए विदेश नहीं गए थे। एक पड़ौसी राज्य के मुख्य मंत्री एक बार 15 दिन के लिए फौरेन गए थे उनकी सहयोगी टीम उनको लंदन में ढूंढती रही लेकिन वे मिले ही नहीं। जब हम लोग मुख्य मंत्री जी के साथ जाते हैं तो ये सुबह आकर हमें जगाया करते हैं कि तुम लोग तैयार नहीं हुए मैं तो तैयार हो गया हूँ और एक मीटिंग की जगह दस-

[प्रो० सम्पत सिंह]

दस मीटिंग करते हैं। अध्यक्ष महोदय, आज का युग पब्लिसिटी का युग है। आपको अपना प्रोडक्ट बेचना हो, अपने यहां इंडस्ट्रीज लगानी हों, मार्केटिंग करनी हो, बिजनेस आपको आगे बढ़ाना हो तो स्वाभाविक है कि लोगों को कनविंस करना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, प्रदेश का माहौल काफी बिगड़ा हुआ था उसे सुधारने में टाइम लगता है। मुख्य मंत्री जी के प्रयासों से हमारे यहां 28345 करोड़ की औद्योगिक परियोजनाएं क्रियान्वित हो रही हैं। फौरेन इन्वैस्टमैंट के 2251 करोड़ रुपये के सीधे विदेशी निवेश के 217 प्रस्ताव आज स्वीकृत हो चुके हैं और सामने बैठे साथियों के समय में इस तरह के कोई प्रस्ताव आने का मतलब ही नहीं था। जहां तक औद्योगिक प्लॉट्स देने की बात है, हमारी सरकार के समय में चौधरी बंसी लाल जी की सरकार के समय से 6 गुना ज्यादा प्लॉट दिये गये हैं और चौधरी भजन लाल के टाइम से ढाई गुना ज्यादा प्लॉट दिये गये हैं इसके लिए टोटल इन्फ्रास्ट्रक्चर एच०एस०आई०डी०सी० और हुड्डा ने तैयार किया। 1991 से 1996 तक 110 करोड़ का इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ। 1996–99 तक 261 करोड़ का तैयार हुआ और हमारे समय में 24 जुलाई, 1999 के बाद दिसम्बर, 1999 से अब तक 861 करोड़ रुपये का इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ है। इस प्रकार 5–5, 6–6 गुना ज्यादा इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ है। अध्यक्ष महोदय, आपको जानकर हैरानी होगी कि चार अमेरिकन कम्पनीज हैवीलैंट, इन्फो यू०एस०ए०, ग्लोबल वैन्टेज और अमैक्स ये लोग पहले बैंगलौर में उद्योग लगाने के लिए जाना चाहते थे बाद में हमारे मुख्य मंत्री जी के जाने के बाद कहने लगे कि बैंगलौर को भूल जाओ और हरियाणा में आ जाओ। वे आज हमारे प्रदेश में आ रहे हैं। हैदराबाद का नाम कुछ समय पहले साइबराबाद के नाम से मशहूर हो गया था लेकिन आज हरियाणा प्रदेश साइबराबाद को पीछे छोड़ चुका है और तीसरे नम्बर पर हरियाणा प्रदेश आ चुका है। भजन लाल जी, आपने 560 एकड़ जमीन पर एक मंडी का नवम्बर, 1994 में शिलान्यास कर दिया था उस पर उसके बाद न तो आपने कुछ किया न चौधरी बंसी लाल जी ने उसको संभाला। अब हमारी सरकार ने वहां 22 करोड़ रुपये की लागत से इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है इस पर 70 करोड़ रुपये की लागत से समेकित फूड प्रौजैक्ट लग रहा है और उसका काम शुरू हो गया है। यदि आप लोग कहें तो मैं बाहर से आने वाली इन इंडस्ट्रीज के सभी के नाम गिना दूं। (शोर)

श्री अध्यक्ष : कर्ण सिंह जी, आप बैठ जाएं। विदाउट परमीशन न बोलें।

प्रो० सम्पत सिंह : स्पीकर साहब बिजली के बारे में बोलते समय इन्होंने दो बातें कहीं। एक तो रेट के बारे में और एक टी० एंड डी० लोसिज के बारे में। बिजली का जहां तक सवाल है, इसके बारे में काफी जिक्र आ चुका है। वर्तमान सरकार ने पिछली सरकारों के मुकाबले बिजली के क्षेत्र में चाहे वह जनरेशन में हो, चाहे ट्रांसमिशन में हो चाहे डिस्ट्रीब्यूशन के क्षेत्र में हो एक रिकॉर्ड तोड़ काम किया है। जितना इन तीन सालों में बिजली डिपार्टमैंट में जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन पर खर्च हुआ है उतना पिछले 30 सालों में काम नहीं हुआ है। बिजली का बहुत तेजी से काम हो रहा है और फिर चलते-चलते पर्सनल आक्षेप भी करते हैं कि मुख्य मंत्री जी हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम की परचेज कमेटी को चेयर करते हैं। स्पीकर सर, इस कमेटी को चेयर करने से हरियाणा प्रदेश के बिजली बोर्ड पर पहले जो खर्चा लगता था उसकी आधी कीमत पर आज बिजली मिल रही है। इसकी बचत प्रदेश को हो रही है और इसका डायरेक्ट फायदा पब्लिक को जा रहा है। स्पीकर सर, वह वक्त चला गया जब कुछ आफिसर्ज बैठकर पोलीटिकल लोगों से मिलकर अपने लैवल पर ही फैसला कर लिया करते थे। अब बिल्कुल ट्रांसपिरेंसी है। उस परचेज कमेटी में हर डिपार्टमैंट के अधिकारी बैठे होते हैं और बाकायदा मार्किट के रेट को देखकर रेट तय किया जाता है। मार्किट रेट को आप देख सकते हैं

पंजाब के रेट्स से आप हमारे रेट्स कम्पेयर कर सकते हैं हर प्रकार के रेट से 20,25,30,40 प्रतिशत कम रेट में हर आईटम की खरीद की जाती है और इस प्रकार प्रदेश को उन पर बचत होती है। इसी प्रकार से विपक्ष के कई माननीय सदस्यों ने कहा कि बिजली की दरें बढ़ रही हैं। इस सरकार के आने के बाद 11.3 प्रतिशत बिजली के दाम बढ़े हैं। चौधरी भजन लाल जी की सरकार के समय 49 प्रतिशत बिजली के दाम बढ़े, चौधरी बंसी लाल जी के समय में 35 प्रतिशत बिजली के दाम बढ़े। दूसरा इन्होंने ट्यूबवैल्ज कनैक्शंज के बारे में कह दिया। स्टैटिस्टिकल डाटा के अनुसार आज ट्यूबवैल्ज बहुत कम हो गये हैं। स्पीकर सर, मैं इन साथियों से पूछना चाहता हूँ कि आज क्या हर आदमी ट्यूबवैल के कनैक्शन को रखता है। कहीं पर जमीन बेच दी जाती है, कहीं पर सैलिन वाटर हो जाने पर ट्यूबवैल बन्द कर दिया जाता है। कई बार ट्यूबवैल कनैक्शन को हार्टीकल्चर के कनैक्शन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। कई बार वाटर लैवल लो होने के कारण ट्यूबवैल बंद कर दिया जाता है। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने अपने समय में क्या कंट्रीब्यूट किया है। वर्तमान सरकार ने 24000 नये ट्यूबवैल के कनैक्शन जोड़े हैं। जहां पहले की सरकारों ने एक हजार कनैक्शन भी नहीं जोड़े थे। इसी तरह से टी० एंड डी० लोसिज कहां 32 प्रतिशत थे। 32 प्रतिशत नहीं थे यह आंकड़ों का हेरफेर है। हरियाणा इलैक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के आंकड़े मैं बता रहा हूँ। 1998-99 में टी० एंड डी० लोसिज 48.96 प्रतिशत थे 32 प्रतिशत नहीं थे। इस 48.96 प्रतिशत को घटाकर हमने साढ़े चार प्रतिशत कम किया है। यह ट्रांसमिशन में काम किया गया है और डिस्ट्रीब्यूशन में काम किया गया है उसकी वजह से है। सड़कों का जिक्र आया। आज चौधरी साहब ने सोनीपत-गोहाना-जीन्द की सड़क का जिक्र किया था। स्पीकर सर, कहीं सेम की वजह से कहीं कोई पैच रह गया हो तो अलग बात है अदरवाईज आज हरियाणा की सड़कें हिन्दुस्तान की सड़कों में सबसे बढ़िया हैं। पहले जब दिल्ली जाते थे तो रोहतक होकर दिल्ली जाते थे लेकिन आज सोनीपत, गोहाना होकर दिल्ली जाना पसन्द करते हैं। बरवाला की सड़क पहले दस फुट चौड़ी होती थी और आज उस पर चार-चार गाड़ियां बराबर चल सकती हैं। बरवाला की ही नहीं अग्रोहा जाने वाली सड़क और अग्रोहा की ही नहीं आदमपुर जाने वाली सड़क को चार-चार फुट ऊपर उठाया जा रहा है। चौधरी भजन लाल जी, आपने यह कहा था कि आपके गांव वाली सड़क को ठीक करायें। आज सदलपुर वाली सड़क चार फुट ऊपर उठ रही है क्योंकि आप पार्टी विशेष के प्रधान हो इसलिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने विशेष कृपा आप पर की है। वैसे हमारे एम०पी० चौधरी अजय सिंह चौटाला का भी लोक सभा का क्षेत्र है इसलिए आप दोनों ही बड़े हो। आप वह सड़क आज जाकर देखेंगे तो पायेंगे कि वह सड़क चार फुट ऊपर उठी हुई मिलेगी। पैसा खर्च करने का जहां तक सवाल है, चौधरी भजन लाल जी की सरकार के समय 1991-92 से 1996-97 तक 77 करोड़ रुपया खर्च हुआ। 1996-97 से 1998-99 तक जब चौधरी बंसी लाल जी की सरकार थी 68 करोड़ रुपये खर्च हुए और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार के समय में 443 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं ये लोग तो इसके लवै धवै भी नहीं हैं। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, अब मैं ऐजुकेशन के बारे में कहना चाहूँगा। (शोर एवं व्यवधान) प्रदेश में ऐजुकेशन के हालात बहुत खराब थे। अंग्रेजी सिस्टम जो चल रहा था, ब्रिटिश हकूमत ने जो सिस्टम दिया था किसी ने उसको छेड़ा नहीं। उसी पर चलते गए। लेकिन मुख्य मंत्री महोदय ने आते ही पहले सभी टीचर्ज, प्रोफैसर्ज और वाइस चांसलर्ज जितने भी इंटेलैक्चुअल थे उन सबको बुलाकर एक ऐजुकेशन पॉलिसी बनाई जो जोब ओरियंटिड हो। जिससे प्रोफैशनल ऐजुकेशन, फंक्शनल ऐजुकेशन और स्पैशलाइज ऐजुकेशन मिल सकें। ऐसी ऐजुकेशन पॉलिसी बनाने से हरियाणा प्रदेश में टैक्नीकल ऐजुकेशन, प्रोफैशनल ऐजुकेशन आज बच्चे प्राप्त कर रहे हैं। 30-35 हजार बच्चे आज हर साल इस तरह के तैयार हो रहे हैं, जो अपने आप रोजगार प्राप्त कर सकेंगे। अध्यक्ष महोदय, सरकारी

[प्रो० सम्पत सिंह]

रोजगार को आप रोजगार नहीं मान सकते। हुड्डा साहब ने आंकड़ा पढ़ दिया कि 2001 में बेरोजगार 6 लाख थे और आज वे बढ़कर 8 लाख हो गये हैं। यह वह आंकड़ा है जो सरकारी नौकरियों की तलाश वाले लोग हैं। सरकारी नौकरी आप भी नहीं दे सकते और कोई भी नहीं दे सकता। आज विकास करो, काम करो जिससे मैनडेज पैदा होंगे, उससे काम मिलेगा। वह काम होता है और वही सरकार ने किया है। प्रोफैशनल बच्चे आज तैयार किए गए हैं। जैसा अभी कहा गया कि स्कूलों का इन्फ्रास्ट्रक्चर बहुत खराब हो रहा है इसमें कोई दो राय नहीं कि स्कूलों की हालात बहुत बुरी थी, मैं नहीं कहता कि हमने उसको 100 प्रतिशत ठीक किया है लेकिन हमने काम किए हैं। अध्यक्ष महोदय, आपको जानकर खुशी होगी कि DPEP और HRDF दोनों ने मिलकर 177 स्कूलों की बिल्डिंग बनाई हैं। मैं स्कूलों के कमरों की भी बता देता हूँ कि हमने 3966 स्कूलों के कमरे बनाए हैं, इतने शायद 30 सालों में भी इन लोगों ने नहीं बनाए होंगे। स्कूलों में 400 एडीशनल कमरे बनाने का एस्टीमेट तैयार हो रहा है और वे भी बन जाएंगे। जहां तक स्कूलों की मुरम्मत की बात है तो 1114 स्कूलों के कमरों की मुरम्मत की गई है। बच्चे नीचे न बैठें इसके लिए हरियाणा हिन्दुस्तान में पहला प्रदेश होगा जहां जून से पहले-पहले तीसरी क्लास तक का कोई भी बच्चा नीचे नहीं बैठेगा, डियूल डैस्क पर बैठेंगे। 20 करोड़ रुपये के डियूल डैस्क खरीदने के ऑर्डर हरियाणा सरकार कर चुकी है। इसी तरह से लड़कियों के लिए प्रदेश के अन्दर हर स्कूल में टॉयलैटस का प्रबन्ध करवा दिया गया है। इसी प्रकार आपने कह दिया कि रैशनेलाइजेशन में आप इनकी छंटनी करोगे तो मैं हाउस के अंदर कैटेगिरीकली बताना चाहूँगा कि हमने आज तक जब से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्य मंत्री बने हैं, हरियाणा प्रदेश के एक भी सरकारी कर्मचारी की छंटनी नहीं की है और न ही आगे हम किसी सरकारी कर्मचारी की छंटनी करने जा रहे हैं। हमने उनका यूटीलाइजेशन किया है।

कैप्टन अजय सिंह यादव : ********

श्री अध्यक्ष : कैप्टन साहब, जो कुछ कह रहे हैं, वह रिकॉर्ड न किया जाए।

प्रो० सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, पहले मंजूरे नजर लोगों को ये लोग फरीदाबाद, गुड़गांव और पंचकूला तक सीमित रखते थे, तनख्वाहें लेते थे डबवाली से, तनख्वाहें लेते थे सदलपुर से और लग जाते थे फरीदाबाद और गुड़गांव में। वही रैशनेलाइजेशन है जहां जरूरत है वहीं हमने भेजे हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि आज कोई भी अस्पताल ऐसा नहीं है जहां कम से कम एक डॉक्टर न हो। सरकार आने से पहले 52 अस्पताल ऐसे थे जहां गधे, घोड़े और खच्चर घूमते थे वहां डॉक्टर्ज का काम नहीं था। हमने ऐसे काम किए हैं जिससे स्कूलों में टीचर्ज जा सकें। कोई स्कूल ऐसा नहीं रहा जहां कोई टीचर न हो। ऐसी पॉलिसी हमने रखी है न कि रिटैंचमैंट की है बल्कि हमारी सरकार ने तो आने के बाद 6-7 हजार टीचर्ज भर्ती किए हैं और भी वकैंसीज निकाली हैं और वह कमीशन के पास भेजी हुई हैं। छंटनी हम नहीं कर रहे हैं, आप गलत प्रचार करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। जहां तक स्कूलों को अपग्रेड करने की बात है तो यह ओल्ड रिकॉर्ड की बात है कि जब यह सरकार आई है उससे पहले साल का मैं पढ़ रहा था मिडल स्कूल—निल, हाई स्कूल—निल, सैकेण्डरी स्कूल—निल। बाद में हमारी यह सरकार आने के बाद मिडल स्कूल 474, हाई स्कूल 295, सैकेण्डरी स्कूल 294 कुल मिलाकर पूरे हरियाणा प्रदेश में हमारी सरकार आने के

* चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

बाद 1063 स्कूल अपग्रेड किए गये। इससे पता लगता है कि हमारी सरकार शिक्षा के बारे में कितनी सीरियस है। स्पीकर सर, मेरे विपक्ष के भाइयों को कुछ पता तो है नहीं ये ऐसे ही फालतू की बात करते रहते हैं। किसी ने चौधरी भजन लाल जी से पूछा कि इस बार का हरियाणा का बजट कैसा है, इन्होंने कहा कि बहुत गंदा है, इससे गलत बजट नहीं हो सकता। स्पीकर सर, ये बहुत सीनियर हैं इनको ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए थी। हम मानते हैं कि विपक्ष में होने के नाते इन्हें बजट का विरोध करना था लेकिन गंदा या गलत शब्द यूज इनको नहीं करने चाहिएं थे। विपक्ष में होने के नाते यदि इन्हें विरोध ही करना था तो ये कह देते कि यह बजट प्रदेश के हित में नहीं है या इससे किसानों को कोई राहत नहीं मिलेगी तब तो ठीक था लेकिन इन्होंने गंदा और गलत शब्द यूज किए जो बड़े शर्म की बात है। मैंने अखबार में पढ़ा है कि भजन लाल जी ने ये शब्द कहे। स्पीकर सर, जहां तक एस०वाई०एल० की बात है, विपक्ष के साथियों ने एस०वाई०एल० के बारे में बहुत कुछ कहा है और हुड्डा साहब भी बार-बार खड़े होकर राजीव लौंगोवाल समझौते के बारे में जिक्र कर रहे थे। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूँगा कि एस०वाई०एल० के पानी के बंटवारे के बारे में पहली नोटिफिकेशन 24 मार्च, 1976 में हुई थी उसमें हमारे और पंजाब के हिस्से के पानी का जिक्र है वह इस प्रकार से है—

"The State of Haryana will get 3.5 M.A.F. and the State of Punjab will get the remaining quantity not exceeding 3.5 M.A.F." स्पीकर सर, यह 3.5 एम०ए०एफ० हरियाणा के लिए नहीं है, यह पंजाब के लिए है कि यदि पानी में बढ़ौतरी होगी तो पंजाब को 3.5 एम०ए०एफ० से अधिक पानी नहीं मिलेगा, जो बढ़ेगा वह हरियाणा को मिलेगा। हम 1976 की नोटिफिकेशन के खिलाफ नहीं थे। स्पीकर सर, उसके बाद 1981 में एग्रीमैंट हुआ उसके बारे में चौधरी भजन लाल जी कहते हैं उस पर सरदार दरबारा सिंह ने साईन किए, मैंने साईन किए उसने साईन किए। उस समय एस०वाई०एल० को लेकर दो पैटीशन डली हुई थीं। हरियाणा ने एस०वाई०एल० बनाने के बारे में डाली हुई थी और पंजाब ने पानी के बंटवारे को लेकर डाली हुई थीं। उसमें क्या हुआ :—

"It is now hereby agreed that the main supply of 17.17 M.A.F. flow and storage may be reallocated." और दोबारा बंटवारा हुआ तो क्या हुआ :—

"Share of Punjab that will be 4.22 M.A.F. and that of Haryana 3.50."

3.5 एम०ए०एफ० से पंजाब का 4.22 एम०ए०एफ० हो गया। उसके बाद राजीव लौंगोवाल समझौता हुआ। इस समझौते में एक 9.1 क्लाज है जिसका हमने विरोध किया और स्वर्गीय चौधरी देवी लाल जी के नेतृत्व में इसके कारण हमारे 21 विधायकों ने सेक्रीफाईस भी किया था और त्याग पत्र दिया था, आज ये कहते हैं कि हम इस्तीफा दे दें। स्पीकर सर, उस समय हमने इस्तीफा क्यों दिया था क्योंकि हमें मालूम था कि चाहे कल को कोई भी कमीशन बैठे उसको समझौते की क्लाज में बंधना पड़ेगा। जो भी टर्म्ज एंड कंडीशंज कमीशन के सामने रखी जायेंगी उसको उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। यही कारण है कि उसके बाद जो इनटैरिम रिपोर्ट आई उसमें पंजाब का हिस्सा 4.22 एम०ए०एफ० से बढ़कर 5 एम०ए०एफ० हो गया और हमारा 3.83 एम०ए०एफ० रह गया।

चौ० भजन लाल : स्पीकर सर, हरियाणा का भी पानी बढ़ा है।

प्रो० सम्पत सिंह : स्पीकर सर, जबकि शुरू में यह था कि पंजाब का पानी 3.5 एम०ए०एफ०

[प्रो० सम्पत सिंह]
से नहीं बढ़ेगा जो भी बढ़ेगा वह हरियाणा का ही बढ़ेगा और अब कम्पैरेटिविली उनका शेयर बढ़ गया। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : चौधरी भजन लाल जी और हुड्डा साहब प्लीज बैठिये।

श्री कर्ण सिंह दलाल : *********

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब आप चेयर की इजाजत के बगैर बोल रहे हैं इसलिए आपकी कोई बात रिकॉर्ड नहीं की जा रही। प्लीज आप बैठें। (शोर एवं व्यवधान)

13-00 बजे

चौ० भजन लाल : स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : भजन लाल जी बैठिये। (शोर एवं व्यवधान)

चौ० भजन लाल : स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट ऑफ ऑर्डर यह है कि ये पंजाब से मिले हुए हैं और पंजाब की वकालत कर रहे हैं और हरियाणा को नुकसान पहुंचा रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : ये हरियाणा के अहित की बात कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप सभी बैठिये। हुड्डा साहब क्या ये आपके लीडर नहीं हैं, आप बतायें। आप सारे ही इकट्ठे खड़े हो गए। (शोर एवं व्यवधान) सारी पार्टी एकदम खड़ी हो गई। जब आपका लीडर बोल रहा हो तो आप बैठिये। लीडर किस लिए बनाया जाता है। आप पार्टी को बाहर खड़ी करके बुला लेना। यहां पर सदन में एक-एक बोलेगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : ये बात ही ऐसी कह रहे हैं कि हम ही क्या सारा हरियाणा खड़ा होकर कहेगा क्योंकि यह हरियाणा की जीवन रेखा का सवाल है। (शोर एवं व्यवधान)

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता और सदस्य तथ्यों पर आधारित बातें नहीं सुन सकते। आप लोग बोल रहे थे, अध्यक्ष महोदय जी की इस बात के लिए सराहना की जायेगी कि इन्होंने आपको बोलने के लिए खुलकर समय दिया और पूरा समय दिया। लेकिन आप सदन में कोई सुझाव नहीं दे पाये। अब जब सदन में आपको सही आंकड़े दिए जा रहे हैं तो आप आराम से इस बात को सुनें, सदन का समय क्यों खराब कर रहे हो। (शोर एवं व्यवधान) कहां सुन रहे हो। चौधरी बंसी लाल जी तो बोल नहीं पाते। लोबी में बोलते हैं कि भाखड़ा का पानी चौटाला में चला गया। इनको हरियाणा की भौगोलिक स्थिति का ज्ञान नहीं। इन्हें सराहना करनी चाहिए कि चौटाला टेल पर है, यह तो सब को पता है कि भाखड़ा की टेल पर है, राजस्थान और हरियाणा की टेल पर है। अगर टेल पर पूरा बनकर पानी जाता है तो पूरा हरियाणा सैलाब होता है कि नहीं होता है। चौधरी बंसी लाल जी बाहर जा करके लोगों से फार्म मंगाते हैं कि लाओ तुम्हें नौकरी दिलवा दूंगा। सदन में कहते हैं कि नौकरियां मत दो। बजट का घाटा कम किया करो, नौकरी मत लगायें और वहां बाहर फार्म मांग कर कहते हैं कि मैं नौकरी लगवा दूंगा। कब लगवा दूंगा जब मैं बनकर आऊंगा। ये तो ख्वाब आज भी ले रहे हैं। भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने सदन के 40 मिनट बर्बाद कर दिए। एक भी आंकड़ा प्रस्तुत नहीं

* चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

किया। इन्होंने सदन को गुमराह किया कि अनएम्पलाएमैंट बढ़ी है। जबकि अनएम्पलाएमैंट हमारी सरकार ने 3 प्रतिशत कम की है। हमारी सरकार ने जो काम किए हैं वे विस्तार से बताए हैं बराए मेहरबानी करके आप सुनिये। जो बात ठीक हो उसको सुनने में आपको काहे की आपत्ति हो रही है। हमने आपको आराम से सुना है। अब ये आपको नहीं सुहा रहे हैं। ये आपके माध्यम से प्रदेश की जनता को बता रहे हैं। आप अब तो बैठे हो लेकिन दो सालों के बाद तो होंगे ही नहीं लेकिन लोगों को तो बताएंगे कि या नहीं। (शोर एवं व्यवधान)

चौ० बंसी लाल : आप मेरी बात सुनिये। मुख्य मंत्री जी की आदत है छींटाकशी करने की। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बंसी लाल जी, आप बैठिये। आप बगैर परमिशन के न बोलें। (शोर एवं व्यवधान) कर्ण सिंह जी, आप भी बैठिये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : इन्होंने कहा कि हम गुमराह कर रहे हैं। आप पूरे गलत आंकड़े देकर के गुमराह कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हुड्डा साहब, आप बैठिये।

डॉ० रघुबीर सिंह कादियान : स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट ऑफ ऑर्डर है।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : मैं डॉक्टर साहब की तसल्ली करवा देता हूँ। ये बार-बार हर मामले में उठ जाते हैं कि बेरी की सड़क, बेरी की सड़क। यह मैं मानता हूँ कि बेरी की सड़क पर गधों का आवागमन ज्यादा होने की वजह से टूट जाती है। (शोर एवं व्यवधान) आपकी तसल्ली करवा दूं। यह ठीक है कि आवागमन ज्यादा होने की वजह से सड़कें टूट जाती हैं, उनकी मुरम्मत निरन्तर कर रहे हैं। आपके इस क्षेत्र में कलानौर से ले करके बेरी तक सड़क जैसी हालत में आज है वैसी जब से हरियाणा बना तब से नहीं बनी। आपके क्षेत्र की जो सड़कें बेरी जाती हैं। वह मैं बता देता हूँ। बेरी से बहादुरगढ़ छारा रोड़ तथा बेरी से कलानौर रोड़ पर 8 करोड़ रुपये की लागत से अगले महीने काम शुरू होने जा रहा है। रोहतक से झज्जर सड़क का कार्य मुक्कमल होने जा रहा है। बेरी से गुजरते हुए बेरी से रोहतक व डीघल रोड़ पर मुरम्मत का कार्य जारी है। बेरी से झज्जर वाया धौड़ सड़क पर काम जारी है। आपके हल्के में प्रोपर बेरी में गड़बड़ है और खच्चे होते हैं क्योंकि वहां पर गलत लोगों का आवागमन है, इसे ठीक करवा देंगे। (शोर)

डॉ० रघुबीर सिंह कादियान : स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट ऑफ ऑर्डर है। (शोर)

श्री अध्यक्ष : आप सभी अपनी-अपनी सीटों पर बैठें। (विघ्न एवं शोर) कादियान साहब, आपको गधा नहीं कहा गया है इसलिए आप बैठें। (विघ्न एवं शोर) आप सभी बैठें। (विघ्न एवं शोर) आपको कुछ नहीं कहा गया है इसलिए आप बैठ जाइये। (विघ्न) नहीं, आपको कुछ नहीं कहा इसलिए आप बैठें (विघ्न एवं शोर) प्रोफैसर सम्पत सिंह जी, आप बोलें। (विघ्न एवं शोर)

प्रो० सम्पत सिंह : स्पीकर साहब, आप डैकोरम करवाएं तभी मैं बोल सकूंगा। (विघ्न एवं शोर)

श्री अध्यक्ष : आप सभी लोग अपनी सीटों पर बैठें। (विघ्न एवं शोर) बड़ी अच्छी-अच्छी बातें यहां पर आ रही हैं बजट रिप्लाई आ रहा है और बहुत ही बढ़िया बजट पेश हुआ है, आप रिप्लाई सुनें। (विघ्न एवं शोर)

डॉ० रघुबीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, *******

श्री अध्यक्ष : डॉक्टर साहब, आप बैठें। (विघ्न एवं शोर) इनकी कोई बात रिकॉर्ड न की जाए। आप बैठिये नहीं तो मुझे आपको वार्न करना पड़ेगा। (विघ्न एवं शोर)। I warn you, please sit down. (विघ्न एवं शोर) जय प्रकाश जी, आप बिना परमिशन के खड़े हैं आप बैठिये आपको बोलने की कोई इजाजत नहीं है। (विघ्न एवं शोर) डॉ० रघुबीर सिंह कादियान जी, आप बैठें। (विघ्न एवं शोर) मैं भी बेरी का ही हूँ। (विघ्न एवं शोर) मुझे तो कोई तकलीफ नहीं है हमारे और आपके तो बहुत गये हैं। (विघ्न) अब आप बैठें।

प्रो० सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने बार-बार कहा है कि अनइक्वल डिस्ट्रिब्यूशन हो रहा है, फलां हो रहा है मैं थोड़ा सा इनको स्पष्ट करना चाहता हूँ ताकि रिकॉर्ड स्ट्रेट रहे। हरियाणा में रावी ब्यास का जो पानी अब है जो हमने अभी इन्टैरिम रिपोर्ट में दिया है 3.83 एम०ए०एफ० किया है उसका 1.76 एम०ए०एफ० मिलता है इसमें .62 एम०ए०एफ० भाखड़ा क्षेत्र में जा रहा है और 1.14 एम०ए०एफ० डब्ल्यू०जे०सी० क्षेत्र में जा रहा है जो दक्षिणी हरियाणा में है और .62 और 1.14 एम०ए०एफ० दक्षिणी हरियाणा में डब्ल्यू०जे०सी० की मार्फत वहां पर जा रहा है और आज की स्थिति और भी अच्छी है। आज 1.02 एम०ए०एफ० से भी फालतू पानी डब्ल्यू०जे०सी० में चल रहा है और स्पीकर सर हम तो और पानी भी देने को तैयार हैं क्योंकि माननीय मुख्य मंत्री जी की ओर से इस बारे में कोई बहुत खास प्रयास नहीं हुए थे लेकिन अब उन्होंने प्रयास किए हैं और जो पानी डब्ल्यू०जे०सी० के अन्दर रावी ब्यास का सरप्लस पानी जाना है उसके लिए चैनल तो नरवाना ब्रांच है इस चैनल की जो कैपेसिटी है वह 4022 क्यूसिक है जो इससे घटकर 3200 कुछ रह गई थी। कैपेसिटी को रैस्टोर करवाते- करवाते आज यह 3700 क्यूसिक तक तो लाए हैं। लेकिन 4022 क्यूसिक की कैपेसिटी जब हो जाएगी तो उसमें और पानी दे देंगे। अध्यक्ष महोदय, आज के दिन स्टेट के अन्दर चार ग्रुप्स बने हुए हैं और प्रत्येक ग्रुप में 8 दिन तक पानी चलता है यानि 32 दिन में एक बार पानी मिलता है जो आठ दिन चलता है कोई अनइक्वल डिस्ट्रिब्यूशन नहीं हो रहा है तथा सारी स्टेट में एक जैसा व्यवहार हो रहा है। पानी के मामले में कोई भी भेदभाव कहीं पर नहीं हो रहा है। (विघ्न एवं शोर) (इस समय कई माननीय सदस्य अपनी सीटों पर खड़े होकर बोलने लगे)।

श्री अध्यक्ष : आप सभी लोग बैठें। (विघ्न एवं शोर) इनकी कोई भी बात रिकॉर्ड नहीं की जाए। (विघ्न एवं शोर) आप सभी लोग अपनी सीटों पर बैठें। धर्मबीर जी, आप बैठिए, (विघ्न एवं शोर) आप सभी बैठें और फाईनैंस मंत्री जी की बात सुनें। डॉक्टर कादियान साहब, आप भी बैठें, कोई प्वायंट ऑफ ऑर्डर नहीं है। (विघ्न एवं शोर) आपके नेता पेशैंसली सुन रहे हैं इसलिए आप भी अपनी सीटों पर बैठें और रिप्लाई सुनें (विघ्न एवं शोर) कैप्टन साहब, आप बैठिये, धर्मबीर जी, आप भी बैठें (विघ्न एवं शोर) I warn you. आप बैठिए। बिना परमिशन के बोलने के लिए खड़े मत हों। (विघ्न) रघुबीर सिंह बैठिए। (विघ्न) रघुबीर सिंह जी आप अपनी सीट पर बैठें। (विघ्न) वित्त मंत्री जी जो कह रहे हैं उसको सुन लें। (विघ्न) कैप्टन साहब बैठ जाएं। (विघ्न) आपके नेता बड़ी सैंसली सुन रहे हैं। रघुबीर सिंह जी आप बैठिए। (विघ्न) नो, नो, कोई प्वायंट ऑफ आर्डर नहीं है। आप अपनी सीट पर बैठें। (विघ्न) कैप्टन साहब बैठ जाएं, रघुबीर सिंह जी या तो जाएं या बैठ जाएं।

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

(विघ्न) रघुबीर सिंह I warn you. नहीं नहीं, आप अपनी सीटों पर बैठ जाएं। (विघ्न)

डॉ रघुबीर सिंह कादियान : *********

श्री अध्यक्ष : कादियान जी, जो भी बोल रहे हैं वह कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया जाए।

प्रो० सम्पत सिंह : स्पीकर सर, आप हाउस का डैकोरम बनवाएं। हमने जो बताया है वह फैक्चुअल पोजीशन बताई है। (विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : स्पीकर सर, अगर ये चाहते हैं कि हम इनकी बात सुनें तो इनको सही बात कहनी चाहिए और सही फैक्टस सदन में बताने चाहिएं।

Mr. Speaker : No, No. Please take your seat. (विघ्न) ये सही बता रहे हैं। (विघ्न) हुड्डा जी, आप अपनी सीट पर बैठें। (विघ्न)

प्रो० सम्पत सिंह : स्पीकर सर, इनके भागने की सलाह है। ये भागेंगे। भागेंगे। (विघ्न) ये रुकने वाले नहीं हैं ये तो भागेंगे। (विघ्न)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : आप वाक-आउट करके खबर छपवाना चाहते हैं। (विघ्न) आप आराम से बैठिए। सुनने की कोशिश करें। (विघ्न) बड़ी हैरानी की बात है आपको वार्न किया जाता है और फिर भी आप खड़े होकर बोलने लग जाते हैं। (विघ्न) आपने वाक-आउट करना है क्या? खबर बनवानी है क्या? (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, आपने जिसको वार्न किया हुआ है उसको नेम कर दो। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : आप सब बैठिए। बैठिए। (विघ्न) चौधरी भजन लाल जी बैठिए।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : आप वाक-आउट करके खबर छपवाना चाहते हैं। (विघ्न) क्या आप वाक आउट करोगे, कल की खबर में आने के लिए। (विघ्न) इन्होंने बिल्कुल गलत बात नहीं कही है। यह तथ्यों पर आधारित बात कही है। (विघ्न) तुम्हारी सुनने की हैसियत नहीं है। (विघ्न) तुम्हारे में सुनने की कहां पर हिम्मत है। (विघ्न)

वाक-आउट

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, आप हमारी बात नहीं सुन रहे हैं और ये गलत ब्यानी सदन में कर रहे हैं इसलिए हम सदन से वाक-आउट करते हैं।

प्रो० सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, इन लोगों को सच्ची बात कड़वी लगती है। (विघ्न)

श्री राम किशन फौजी : स्पीकर सर, आप हमारी बात नहीं सुन रहे हैं इसलिए हम भी वाक-आउट करते हैं।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, आप हमारी बात नहीं सुन रहे हैं और ये गलत ब्यानी सदन में कर रहे हैं इसलिए हम भी इनकी गलत ब्यानी पर सदन से वाक-आउट करते हैं। **(इस समय सदन में उपस्थित इण्डियन नेशनल कांग्रेस के सभी सदस्य, हरियाणा विकास पार्टी के सभी सदस्य और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इण्डिया के माननीय सदस्य श्री कर्ण सिंह दलाल सदन से वाक-आउट कर गए।)**

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

वर्ष 2003-2004 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा
(पुनरारम्भ)

वित्त मंत्री (प्रो० सम्पत सिंह) : अध्यक्ष महोदय, ऐसे आदमी भी वाक-आउट करते हैं जिनमें से एक कहता है कि मैं 12 साल मुख्य मंत्री रहा और दूसरा कहता है कि मैं 10 साल मुख्य मंत्री रहा। इन्होंने अपने राज में कुछ किया तो है नहीं। ये लोग उस टाईम कहाँ गए थे। आज जब मुख्य मंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है तो उसके अगेन्स्ट ये वाक-आउट कर रहे हैं। जब ये दोनों मुख्य मंत्री बैठे हुए थे खब्बी खाँ बने हुए, उस टाइम इन्होंने कुछ किया नहीं और आज इनको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की याद आ रही है। स्पीकर सर, हमारी सरकार ने पानी का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया है हरियाणा प्रदेश के 90 के 90 हल्के मुख्य मंत्री जी के लिए बराबर हैं। चाहे वह हलका आदमपुर का हो, चाहे वह हलका तोशाम का हो। सारा हरियाणा मुख्य मंत्री जी के लिए बराबर है। अध्यक्ष महोदय, मैं चौधरी बंसी लाल जी के लिए कहना चाहता हूँ कि इन्होंने जो अनइम्प्लाइमैंट अलाउंस देने के लिए फार्म भरवाने शुरू करे हुए हैं। स्पीकर सर, पिछली बार इन्होंने कहा था कि मैं पैट्रोल पम्प दूंगा, मैं गैस एजैन्सी दूंगा, मिट्टी के तेल के डिपोज दूंगा और इन्होंने क्या दिया इन्होंने उनके हाथ में पकड़ा दी शराब की थैलियां और शराब की बोतलें। इनकी वजह से जो लोगों की गत बनी जो उनको रोजगार मिला, डेढ़ लाख को तो रोजगार जेल में मिल गया था। डेढ़ लाख बच्चों को तो जेल की रोटियां खानी पड़ी। मुख्य मंत्री ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार आने के बाद वे मुख्यधारा में आए हैं। अब उस बात से ये फिर रहे हैं। अब ये कहते हैं कि 25 लाख फार्म भरवा लिए हैं। 25 लाख जो फार्म भरवा लिए हैं तो स्पीकर सर, उसका हिसाब तो कोई बनिया मांगे राम जैसा ही कर सकता है। अगर 250 रुपये प्रति मास दे दें तो 20 लाख लोगों का जिनके फार्म भरने का टारगेट रखा है तो 600 करोड़ रुपये लगेंगे। गुप्ता जी क्या दे देंगे। नहीं दे सकते। (विघ्न) ये तो अपनी बात कह देंगे और बाद में छोड़ कर चले जाएंगे। स्पीकर सर, अभी मुख्य मंत्री जी ने जवाब इम्पलायमैंट के बारे में दिया था। मैं विद् इन इनवर्टिड कौमाज आपको बता देता हूँ। हिन्दुस्तान की औद्योगिक जगत की सबसे बड़ी जो संस्था है वह ऐसोसिएटिड चैम्बर ऑफ कामर्स एंड इन्डस्ट्री है। जिसको एसोचम बोलते हैं। (विघ्न) अब ये हरेक चीज को कह देंगे कि ये झूठे आंकड़े हैं। आंकड़े गलत हैं। उनकी रिपोर्ट 28 जुलाई, 2002 को जो प्रकाशित हुई थी वह मेरे पास है। उन्होंने उसमें लिखा है कि पिछले पाँच वर्षों में हरियाणा में लगभग 2.4 प्रतिशत वर्ष की दर से रोजगार के अवसर बढ़े हैं। क्या दो वर्ष वह थे या डेढ़ वर्ष जो उनका है उसकी आप बात कर रहे हैं। पिछले दस वर्षों में बेरोजगारी की दर 6.5 प्रतिशत से घटकर 4.77 रह गई है और पिछले तीन सालों में यह बेरोजगारी लगभग तीन परसैंट कम हुई है। स्पीकर साहब, यह क्यों घटी है इसके बारे में मैं इनको बताना चाहता हूँ कि सरकार ने तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा दिया है नयी-नयी औद्योगिक इकाइयां आयी हैं, कम्प्यूटर शिक्षा और इंफोरमेशन टैक्नोलोजी को बढ़ावा दिया गया है इस वजह से यह बेरोजगारी घटी है न कि सरकारी नौकरियों की वजह से यह घटी है। इसी तरह से जो काम करने वाले लोग हैं उनके आंकड़े भी तीन साल के मैं इनको देना चाहता हूँ। रजिस्टर्ड फैक्ट्री, रजिस्टर्ड शोप्स एवं कमर्शियल ऐस्टेब्लिसमैंट के अंदर दो साल में इम्पलाईज और वर्कर्ज के नम्बर चार लाख 98 हजार, 2001 में पाँच लाख 19 हजार और 2002 में पाँच लाख 40 हजार हैं यानि कहने का मतलब यह है कि उनका रोजगार बढ़ता जा रहा है। शोप्स एवं कामर्शियल ऐस्टेब्लिसमैंट में वर्कर्ज और इम्प्लाइज के नम्बर्ज पहले जहाँ 1 लाख 21 हजार थे वहीं अब यह हो गए 1 लाख 54 हजार 738। अध्यक्ष महोदय, यह इंडीकेशन क्या है? यह इंडीकेशन यह

है कि ज्यादा बच्चों को रोजगार मिला है। हुड्डा साहब ने रोडवेज की बसिज का भी जिक्र कर दिया। अध्यक्ष महोदय, सारा देश तो हरियाणा रोडवेज की बसिज की सराहना कर रहा है और उनमें बैठने के लिए लोग वेट करते हैं और ये इस तरह की बात कर रहे हैं। ये तो हरियाणा रोडवेज की बसिज का सत्यानाश करके, बेड़ा गर्क करके चले गए थे। उस समय रोडवेज की बसिज में कोई आदमी बैठता नहीं था क्योंकि उनके रोशनदानों की खिड़कियां साफ थीं लोगों के कपड़े फट जाया करते थे। लेकिन आज 1600 बसिज से ऊपर अशोक अरोड़ा जी ने हरियाणा रोडवेज में और जोड़ी हैं और 500 बसिज इस साल और जोड़ देंगे। इसी तरह से फ्यूल का भी इन्होंने जिक्र कर दिया। मैं इनको तुलनात्मक स्टेटमैंट देकर बताना चाहूंगा कि पंजाब जोकि हमारे साथ लगता हुआ है वहां पर फ्यूल 4.28, पेप्सू का 4.1, डी.टी.सी. दिल्ली के 3.84, जहां कांग्रेस की इनकी अपनी सरकार है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष जी, ये दिल्ली का जिक्र क्यों कर रहे हैं। वहां पर तो बसिज पहले और दूसरे गियर में चलती हैं इसलिए तो वहां फ्यूल ज्यादा आएगा ही। इनको राजस्थान से तुलना करनी चाहिए दिल्ली से ये क्यों तुलना कर रहे हैं?

प्रो० सम्पत सिंह : स्पीकर सर, मैं इनको गियर लगाकर, बैक गियर लगाकर ही बता देता हूं। मैं पीछे का बता देता हूं। 1991-92 से 1995-96 तक एम०पी०एल० 4.33 से 4.41 तक था, 1996 से 1998-99 तक यह 4.44 था और जब से ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार बनी है और अशोक अरोड़ा जी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बने हैं तब से यह 4.44 से 4.53 तक हो गई है। इन्होंने राजस्थान का जिक्र किया। इन्होंने कल कहा था कि 4.7 समथिंग। इन्होंने दिल्ली के बारे में तो कह दिया कि वहां गियर लगाने पड़ते हैं इसलिए फ्यूल ज्यादा आएंगे लेकिन इनको राजस्थान और हरियाणा में फर्क नहीं लगता। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश में हर गांव में हर ढाणी में बस जाती है जबकि राजस्थान में केवल मात्र बड़ी सड़कों पर ही वहां की रोडवेज की बसिज चलती हैं।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : वहां की सड़कें भी तो आप बताएं कि कितनी अच्छी हैं।

प्रो० सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, हर गांव में हरियाणा में बसें जाती हैं। सारे प्राइवेट रूट्स गांवों के दिए हुए हैं। हर गांव के अन्दर बस जाती है। फ्यूल बढ़ने का कारण यह भी है कि तेल की कीमतें बढ़ी हैं। चौधरी भजन लाल जी के समय में टोटल इंक्रीज इन रेटस ऑफ डीजल 38.91% बढ़े थे जबकि बंसी लाल जी के समय में 46.44% बढ़े थे। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का भाव यह है कि इसके बावजूद बचत हुई है। तेल के रेट 87 परसैंट बढ़े हैं उसके बावजूद भी फायदा। कहां तो कितना नुकसान हो रहा था उस नुकसान को भी कम किया। उसके बावजूद रोडवेज का मुनाफा हुआ है। कल चौधरी बंसी लाल जी ने जिक्र कर दिया कि पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन पर खर्च कम बताया है। खर्चा कम नहीं बताया अगर आप आंकड़ों को देखें तो पायेंगे कि 1995-96 में 191 करोड़ रुपया रखा गया था, 1998-99 में चौधरी बंसी लाल जी के टाईम में 364 करोड़ रुपये थे और अब जो रखे हैं वह 535 करोड़ 26 लाख रुपये इस बजट में रखे हैं और जो वर्क्स किये हैं वह भी आप सब जानते हैं। चौधरी भजन लाल जी के समय में 1991 से 1995 तक नौ पुलिस स्टेशन बने थे और बंसी लाल जी के समय में 5 पुलिस स्टेशन बने थे और आज 20 पुलिस स्टेशन बन गए हैं यह दोनों के टाईम से फालतू बने हैं। हाउसिज जो कि वैल्फेयर स्कीम है कांस्टेबल्ज को, ऑफिसर्ज को सभी को मकान चाहिएं तो चौधरी भजन लाल के समय में 432 मकान बने थे, बंसी लाल जी के टाईम में 1500 बने थे और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के समय में 2206 मकान बन चुके हैं और 190 के टेंडर हो

[प्रो० सम्पत सिंह]
चुके हैं। पुलिस लाइन पिछली दोनों सरकारों के समय में एक भी नहीं बनी थी और आज सात अंडर कम्पलीशन हैं इसके अलावा वायरलैस सैट्स भी आपसे कई गुना ज्यादा खरीदे हैं। जहाँ तक व्हीकल्ज की बात है, चौधरी भजन लाल जी के समय में 177 खरीदे गए थे और धक्कामार चलते थे, चौधरी बंसी लाल जी के समय 362 व्हीकल्ज खरीदे गये और आज चौटाला साहब के समय में 937 व्हीकल्ज पुलिस को चुस्त दुरुस्त करने के लिये खरीदे गये हैं ताकि लोगों के जान माल की सुरक्षा रह सके। वैल्फेयर ग्रांट 1998-99 में चौधरी साहब बंद करके चले गए थे वह चौटाला साहब की सरकार आने के बाद मिली है। गवर्नमैंट ऑफ इंडिया से जो मॉडर्नाइजेशन के लिए पैसा आता है वह मुफ्त में नहीं आता है उसमें 50 परसैंट स्टेट गवर्नमैंट को देना पड़ता है 25 परसैंट लोन के रूप में मिलता है और 25 परसैंट ग्रांट के रूप में मिलता है और यूटीलाइजेशन करने वाली वन ऑफ दि बैस्ट स्टेट कोई है तो वह हरियाणा है इस मद में चौधरी भजन लाल जी के समय में 2 करोड़ 91 लाख रुपये बढ़े। बंसी लाल जी के समय में 1 करोड़ 79 लाख रुपये व ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार के समय में ग्रांट और लोन दोनों मिला करके 78 करोड़ रुपया सैंटर से आया है और 78 करोड़ रुपया हमारी स्टेट का कुल मिलाकर 156 करोड़ रुपया मिला है यह यूटीलाइजेशन की वजह से मिला है। आपके बजट में पैसा नहीं होगा तो कोई कौडा नहीं देगा, कोई आपको नया पैसा नहीं देगा। स्पीकर सर, एक इन्होंने शूगर मिल की पेमेन्ट का जिक्र कर दिया।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष : यदि हाउस की सहमति हो तो हाउस का समय एक घंटे के लिए बढ़ा दिया जाए।

आवाजें : ठीक है जी।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, हाउस का समय एक घंटे के लिए बढ़ाया जाता है।

वर्ष 2003-2004 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा
(पुनरारम्भ)

प्रो० सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। पेमेन्ट की बात थी। बड़े आंसू बहा रहे थे और कह रहे थे कि पेमेन्ट लेट हो रही है, ब्याज नहीं मिल रहा। भजन लाल जी, 1991-92 में आप मुख्य मंत्री थे 1991-92 की पेमेन्ट 31-5-93 को की, यानी डेढ़ साल बाद की गन्ने की पेमेन्ट। 1992-93 का 31-11-94 को पेमेन्ट किया यानी डेढ़ साल बाद पेमेन्ट किया। 1993-94 की 31-3-96 को पेमेन्ट की यानी ढाई साल बाद और 1994-95 की 31-3-96 को डेढ़ साल बाद पेमेंट की, 1995-96 की 31-10-98 को यानी ढाई साल बाद पेमेन्ट हुई, 1996-97 की 15-11-98 को डेढ़ साल बाद, 1997-98 की 12-11-98 को जब चौटाला साहब मुख्य मंत्री बन गए उनके बनने के बाद जो इनके समय की पुरानी पेमेन्ट रह रही थी वह भी चौटाला साहब ने की। 1998-99 में 31-10-99 को 21 करोड़ बकाया था। वो भी पूरी पेमेन्ट हमने कर दी है। बाद में जब हमारी सरकार शुरू होती है जो सही सरकार होती है मैनडेट लेकर आयी उस सरकार ने क्या-क्या किया। 1999-2000 की जो पेमेंट की गयी वह 5-7-2000 को सातवें महीने में उसी साल सारी पेमेन्ट फारिग कर दी। 2000-2001 की पेमेन्ट 24-7-2001 को सातवें महीने में उसी साल सारी पेमेन्ट फारिग कर दी। 2001-2002 की पेमेन्ट आठवें महीने में फिर सारी पेमेन्ट फारिग कर दी और 2002-2003 की भी जल्दी

पेमेन्ट हो जाएगी। आपका रिकॉर्ड देख लें आपने दो-दो साल, अढ़ाई-अढ़ाई साल और तीन-तीन साल तक पेमेन्ट नहीं की थी और आज इसी साल पेमेंट होती है। क्या हुआ दो महीने, तीन महीने या चार महीने लेट हो सकती है। लेकिन आपके समय में तो काफी लेट होती थी। इसके बाद इन्होंने चीनी मिलों की बात की। आज गोदामों में 425 करोड़ रुपये की चीनी पड़ी हुई है। आपको पता है कि चीनी के रेट कितने डाऊन चले गये हैं। इनको तकलीफ हो रही है। स्पीकर सर, ज्यादा न कहते हुए मैं तो यह कहूँगा कि इस बजट प्रस्ताव को जो इस सदन में रखा है ध्वनि मत से और सर्वसम्मति से पास करें ताकि प्रदेश का हित हो सके। धन्यवाद, जयहिन्द।

बजट 2003-2004 की अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now discussion and voting on Demands for Grants on Budget Estimates for the year 2003-2004 will take place.

As per the past practice and in order to save the time of the House, the demands on the order paper will be deemed to have been read and moved. Hon'ble Members can discuss any demand but they are requested to indicate the demand number on which they wish to raise discussion.

That a sum not exceeding Rs. 8,42,50,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2003-2004 in respect of charges under **Demand No. 1—Vidhan Sabha.**

That a sum not exceeding Rs. 1,21,07,43,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2003-2004 in respect of charges under **Demand No. 2—General Administration.**

That a sum not exceeding Rs. 5,87,13,74,000/- for revenue expenditure and Rs. 30,00,00,000/- for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2003-2004 in respect of charges under **Demand No. 3—Home.**

That a sum not exceeding Rs. 1,65,97,96,000/- for revenue expenditure and Rs. 15,00,00,000/- for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2003-2004 in respect of charges under **Demand No. 4—Revenue.**

That a sum not exceeding Rs. 48,40,78,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2003-2004 in respect of charges under **Demand No. 5—Excise & Taxation.**

That a sum not exceeding Rs. 8,51,53,79,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2003-2004 in respect of charges under **Demand No. 6—Finance.**

That a sum not exceeding Rs. 5,14,58,78,000/- for revenue expenditure and Rs. 3,00,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2003-2004 in respect of charges under **Demand No. 7—Other Administrative Services.**

That a sum not exceeding Rs. 2,15,76,50,000/- for revenue expenditure and

[Mr. Speaker]

Rs. 4,08,04,77,000/- for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2003-2004 in respect of charges under **Demand No. 8—Buildings & Roads.**

That a sum not exceeding Rs. 18,15,35,89,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2003-2004 in respect of charges under **Demand No. 9—Education.**

That a sum not exceeding Rs. 7,36,84,40,000/- for revenue expenditure and Rs. 2,25,22,40,000/- for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2003-2004 in respect of charges under **Demand No. 10—Medical & Public Health.**

That a sum not exceeding Rs. 56,19,98,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2003-2004 in respect of charges under **Demand No. 11—Urban Development.**

That a sum not exceeding Rs. 59,67,00,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2003-2004 in respect of charges under **Demand No. 12—Labour & Employment.**

That a sum not exceeding Rs. 5,40,25,61,000/- for revenue expenditure and Rs. 1,05,00,000/- for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2003-2004 in respect of charges under **Demand No. 13—Social Welfare & Rehabilitation.**

That a sum not exceeding Rs. 25,76,27,000/- for revenue expenditure and Rs. 13,77,88,03,000/- for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2003-2004 in respect of charges under **Demand No. 14—Food & Supplies.**

That a sum not exceeding Rs. 15,22,98,00,000/- for revenue expenditure and Rs. 2,69,67,10,000/- for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2003-2004 in respect of charges under **Demand No. 15—Irrigation.**

That a sum not exceeding Rs. 37,10,09,000/- for revenue expenditure and Rs. 54,60,000/- for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2003-2004 in respect of charges under **Demand No. 16—Industries.**

That a sum not exceeding Rs. 2,91,65,00,000/- for revenue expenditure and Rs. 2,50,00,000/- for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2003-2004 in respect of charges under **Demand No. 17—Agriculture.**

That a sum not exceeding Rs. 1,41,12,30,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2003-2004 in respect of charges under **Demand No. 18—Animal Husbandry.**

That a sum not exceeding Rs. 9,73,00,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2003-2004 in respect of charges under **Demand No. 19—Fisheries.**

That a sum not exceeding Rs. 82,68,00,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2003-2004 in respect of charges under **Demand No. 20—Forests.**

That a sum not exceeding Rs.1,53,79,36,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2003-2004 in respect of charges under **Demand No. 21—Community Development.**

That a sum not exceeding Rs. 23,28,40,000/- for revenue expenditure and Rs. 14,00,00,000/- for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2003-2004 in respect of charges under **Demand No. 22—Co-operation.**

That a sum not exceeding Rs. 5,30,04,00,000/- for revenue expenditure and Rs. 55,66,00,000/- for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2003-2004 in respect of charges under **Demand No. 23—Transport.**

That a sum not exceeding Rs. 1,65,29,000/- for revenue expenditure and Rs. 3,00,00,000/- for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2003-2004 in respect of charges under **Demand No. 24—Tourism.**

That a sum not exceeding Rs. 2,29,21,76,000/- for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2003-2004 in respect of charges under **Demand No. 25—Loans & Advances by State Government.**

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर सर, हमने एक कट मोशन दिया है।

श्री अध्यक्ष : कैप्टन साहब, आपको पता है कि आपने यह कट मोशन आज ही दिया है और आपको पता है कि इसके लिए कितने दिन पहले देना होता है।

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर सर, इसके लिए पांच दिन का समय चाहिए लेकिन आपने इस डिमांड को टेबल पर कल ही रखा है इसलिए हम इसे पहले कैसे दे सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : आपको पता है कि दो दिन पहले देना चाहिए।

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर सर, सैक्शन 129 के अन्दर 5 दिन क्लीयर दे रखे हैं डिमाण्ड कल रखी है तो 5 दिन पहले कैसे हो सकता है।

श्री अध्यक्ष : आपका कट मोशन कई टैक्नीक्लटिज की वजह से डिस-अलाउ कर दिया है अब आप बैठ जायें।

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर सर, आज ही हमने दो और कट मोशन दिये हैं डिमाण्ड न० 11 और 15 के बारे में।

Mr. Speaker : Captain Sahib, your notice of cut motion on demand No. 17 received at 12.20 P.M. today i.e. 13-3-2003. So, it is disallowed due to lack of period of 2 days.

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर सर, आपने हमें ये डिमाण्ड कल दिये हैं तो टू डेज पहले कट मोशन कैसे दी जा सकती है?

श्री अध्यक्ष : यह सब बजट के साथ ही आ जाती हैं। बजट पर सभी कांग्रेस पार्टी के सदस्य 251 मिनट बोले हैं, जबकि इंडियन नैशनल लोकदल के सदस्य 297 मिनट बोले हैं और रेशो में कितना फर्क है तीन गुणा और बोलने के टाईम में मामूली सा अंतर है। आपने जो अपनी बात कही थी वह सभी कह चुके हैं और वित्त मंत्री जी बजट का रिप्लाई भी दे चुके हैं। आपने जो कुछ कहना था वह कह चुके हैं।

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर सर, आपने कल ही तो दिया है।

Mr. Speaker : Hon'ble members in Rule-194 (2) it is clearly mentioned that—

> "Notice of such motions shall be given two clear days before the day on which such item or such grant comes up for discussion:
>
> Provided that the Speaker may in his discretion allow a motion to be moved at shorter notice."

Capt. Ajay Singh Yadav : Let me quote the Rule 129. स्पीकर सर, आपने कल ही तो दिया है। सर, आपकी डिसक्रिशन हैं।

श्री अध्यक्ष : डिसक्रिशन को मैं इस्तेमाल नहीं करता, जो प्रोसीजर है उसको मानता हूँ, जो प्रैक्टिस है उसको मानता हूँ। आप बैठ जायें।

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर सर, आपने कल ही तो दिया है। दो दिन क्लीयर इसमें कर देने चाहियें थे तब तो आपकी बात सही थी लेकिन जब दो दिन इसमें क्लीयर नहीं हैं तो हम दे सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : उसकी मैं रूलिंग दे चुका हूँ। आप बैठ जाइये।

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, मैंने सवेरे ही सदन के सभी सम्मानित सदस्यों को एक बात कही थी कि ये समय पर तो कोई चीज प्रस्तुत नहीं कर सकते, रूल और रेगुलेशंज के मुताबिक नहीं दे सकते। आप चेयर का एतराम करना नहीं जानते, आप कोई चीज समय पर नहीं देते, खैर स्पीकर साहब जब उसको डिसअलाउ कर दें तो उस पर आपको नहीं बोलना चाहिए। जब इन्होंने डिसअलाउ कर दिया कि आप द्वारा यह समय पर नहीं दी गई। फिर उसके बाद क्यों बहस कर रहे हो। बोलने का आपको बहुत लम्बा समय दिया गया। जब आपको बोलने का समय दिया जाता है तब आपके पास पेश करने को कुछ होता नहीं। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Now, the Demands will be put to the Vote of the House.

Question is—

That a sum not exceeding Rs. 8,42,50,000/- for revenue expenditure and be

granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2003-2004 in respect of charges under **Demand No. 1—Vidhan Sabha.**

That a sum not exceeding Rs. 1,21,07,43,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2003-2004 in respect of charges under **Demand No. 2—General Administration.**

That a sum not exceeding Rs. 5,87,13,74,000/- for revenue expenditure and Rs. 30,00,00,000/- for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2003-2004 in respect of charges under **Demand No. 3—Home.**

That a sum not exceeding Rs. 1,65,97,96,000/- for revenue expenditure and Rs. 15,00,00,000/- for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2003-2004 in respect of charges under **Demand No. 4—Revenue.**

That a sum not exceeding Rs. 48,40,78,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2003-2004 in respect of charges under **Demand No. 5—Excise & Taxation.**

That a sum not exceeding Rs. 8,51,53,79,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2003-2004 in respect of charges under **Demand No. 6—Finance.**

That a sum not exceeding Rs. 5,14,58,78,000/- for revenue expenditure and Rs. 3,00,000 for the capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2003-2004 in respect of charges under **Demand No. 7—Other Administrative Services.**

That a sum not exceeding Rs. 2,15,76,50,000/- for revenue expenditure and Rs. 4,08,04,77,000/- for the capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2003-2004 in respect of charges under **Demand No. 8—Buildings & Roads.**

That a sum not exceeding Rs. 18,15,35,89,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2003-2004 in respect of charges under **Demand No. 9—Education.**

That a sum not exceeding Rs. 7,36,84,40,000/- for revenue expenditure and Rs. 2,25,22,40,000/- for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2003-2004 in respect of charges under **Demand No. 10—Medical & Public Health.**

That a sum not exceeding Rs. 56,19,98,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2003-2004 in respect of charges under **Demand No. 11—Urban Development.**

[Mr. Speaker]

That a sum not exceeding Rs. 59,67,00,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2003-2004 in respect of charges under **Demand No. 12—Labour & Employment.**

That a sum not exceeding Rs. 5,40,25,61,000/- for revenue expenditure and Rs. 1,05,00,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2003-2004 in respect of charges under **Demand No. 13—Social Welfare & Rehabilitation.**

That a sum not exceeding Rs. 25,76,27,000/- for revenue expenditure and Rs. 13,77,88,03,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2003-2004 in respect of charges under **Demand No. 14—Food & Supplies.**

That a sum not exceeding Rs. 15,22,98,00,000/- for revenue expenditure and Rs. 2,69,67,10,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2003-2004 in respect of charges under **Demand No. 15—Irrigation.**

That a sum not exceeding Rs. 37,10,09,000/- for revenue expenditure and Rs. 54,60,000/- for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2003-2004 in respect of charges under **Demand No. 16—Industries.**

That a sum not exceeding Rs. 2,91,65,00,000/- for revenue expenditure and Rs. 2,50,00,000/- for the capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2003-2004 in respect of charges under **Demand No. 17—Agriculture.**

That a sum not exceeding Rs. 1,41,12,30,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2003-2004 in respect of charges under **Demand No. 18—Animal Husbandry.**

That a sum not exceeding Rs. 9,73,00,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2003-2004 in respect of charges under **Demand No. 19—Fisheries.**

That a sum not exceeding Rs. 82,68,00,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2003-2004 in respect of charges under **Demand No. 20—Forests.**

That a sum not exceeding Rs. 1,53,79,36,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2003-2004 in respect of charges under **Demand No. 21—Community Development.**

That a sum not exceeding Rs. 23,28,40,000/- for revenue expenditure and Rs. 14,00,00,000 for the capital expenditure be granted to the Governor to defray

charges that will come in the course of payment for the year 2003-2004 in respect of charges under **Demand No. 22—Co-opration.**

That a sum not exceeding Rs. 5,30,04,00,000/- for revenue expenditure and Rs. 55,66,00,000/- for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2003-2004 in respect of charges under **Demand No. 23—Transport.**

That a sum not exceeding Rs. 1,65,29,000/- for revenue expenditure and Rs. 3,00,00,000/- for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2003-2004 in respect of charges under **Demand No. 24—Tourism.**

That a sum not exceeding Rs. 2,29,21,76,000/- for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2003-2004 in respect of charges under **Demand No. 25—Loans & Advances by State Government.**

The motion was carried.

विधान कार्य—

(i) दि हरियाणा एप्रोप्रिएशन (नं० 1) बिल, 2003

Mr. Speaker : Now, the Finance Minister will introduce the Haryana Appropriation (No.1) Bill, 2003 and will also move the motion for its consideration.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh) : Sir, I beg to introduce the Haryana Appropriation (No.1) Bill, 2003.

Sir, I also beg to move—

> That the Haryana Appropriation (No.1) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

> That the Haryana Appropriation (No.1) Bill be taken into consideration at once.

श्री मांगे राम गुप्ता (जीन्द) : अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी ने सदन में बजट पर चर्चा होने के बाद आज विस्तार से जवाब देने का प्रयास किया। अध्यक्ष महोदय, मैं व्यक्तिगत तौर पर यह बात कह सकता हूँ कि वित्त मंत्री जी की काबलियत और ईमानदारी पर मुझे किसी प्रकार की शंका नहीं है लेकिन अध्यक्ष महोदय, यह वित्त मंत्री जी की मजबूरी है, मैं समझता हूँ कि काम स्टेट का हो, व्यक्ति का हो, साधनों से चलता है। सरकार के पास जितने पैसे की अवेलेबिलिटी होती है उससे ही काम किये जाते हैं। वित्त मंत्री जी सरकार की जो नीति हो जिस तरह की डायरेक्शंज हों उसके मुताबिक फण्ड अलाट करने का प्रयास करते हैं और करते रहे हैं लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि वित्त मंत्री जी ने विस्तार में चर्चा पर जवाब देने का प्रयास किया है। एक तो मुझे अभी भी शंका

[श्री मांगे राम]

है कि जो 780.53 करोड़ के घाटे का जो बजट प्रस्तुत किया गया है, आज तक हरियाणा के रिकॉर्ड में इतना बड़ा घाटे का बजट किसी सरकार के समय में नहीं पेश हुआ।

श्री अध्यक्ष : गुप्ता जी, आप पहले भी कह चुके हैं, बजट स्पीच पर भी यही बोल चुके हैं, चाहे पन्ने निकलवा कर देख लें। वही घिसी पिटी बातें हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मांगे राम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, एक सुझाव की बात कहना चाहूँगा इनकी ऐप्रीशिएशन की बात पर कहना चाहूँगा। जैसा इन्होंने बताया, खैर इनकी मजबूरी है।

श्री अध्यक्ष : मजबूरी नहीं हुआ करती, पेश किया जाता है और इनका दायित्व होता है।

श्री मांगे राम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, बजट की ऐप्रीशिएशन पर इन्होंने दो लैटर पेश किए। एक तो सी०आई०आई० का और दूसरा चैम्बर ऑफ कॉमर्स का। बजट हरियाणा के लोगों के लिए पेश किया गया। मैं समझता हूँ कि अगर वित्त मंत्री जी कोई ऐसा लैटर दिखाते जिसमें हरियाणा के किसानों ने ऐप्रीशिएट किया होता, हरियाणा के व्यापारियों ने एप्रीशिएट किया होता। एसोसिएशन व्यापार मंडल ने किया होता या इम्प्लाइज एसोसिएशन ने ऐप्रीशिएट किया होता। हरियाणा के किसी भी वर्ग ने आपके बजट को सराहा नहीं है। आप मानें न मानें मुझे कोई दिक्कत नहीं है।

प्रो० सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, चैम्बर ऑफ कॉमर्स कोई विदेशी नहीं है, कोई श्रीलंका की संस्था नहीं है, सी०सी०आई० नार्थ जोन अमेरिका का नहीं है। (शोर एवं व्यवधान) वे जानते हैं कि कौन प्रदेश किधर जा रहा है, किधर आ रहा है, कौन प्रदेश क्या कर रहा है, उसकी अर्थ व्यवस्था कैसी है, ये उनके ही आंकड़े हैं, यह कोई वैसे ही किसी जनरल आदमी के नहीं हैं। ये जो एक्सपर्ट्स आदमी हैं जो कान्फ्रैंस करते हैं, सेमीनार करते हैं उनके आंकड़े हैं। स्पीकर सर, गुप्ता जी जो बात बजट पर बोलते हुए कह चुके उनको ही दोबारा दोहरा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : गुप्ता जी, जो बात आप कह रहे हैं यह आप पहले भी कह चुके हैं और वित्त मंत्री जी जवाब भी दे चुके हैं। प्लीज आप बैठिये।

श्री मांगे राम गुप्ता : स्पीकर सर, वित्त मंत्री जी की इस बात से मुझे बड़ी खुशी हो रही है जो इन्होंने बताया कि किस प्रकार से घाटे को पूरा करेंगे।

श्री अध्यक्ष : गुप्ता जी आप किस पर बोल रहे हैं। यह ऐप्रोप्रिएशन बिल है और यह ऐस्टिमेटस कमेटी ने जो सप्लीमैंटरी ऐस्टिमेटस पास किए थे उनके बारे में है। यह ऐप्रोप्रिएशन बिल बजट पर नहीं है। प्लीज आप बैठिये।

प्रो० सम्पत सिंह : स्पीकर सर, गुप्ता जी तो बजट का ऐप्रोप्रिएशन बिल समझ रहे हैं। मैं इनको बताना चाहूँगा कि वह तो कल आयेगा। इनको इतनी समझ नहीं कि ये किस पर बोलना चाहते हैं और किस पर बोल रहे हैं। मैं तो इनसे ऐसे ही सीखने की बात कर रहा था।

चौ० भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, ******

श्री अध्यक्ष : भजन लाल जी, पहले मंत्री जी को बिल पेश करने दो। उसके बाद आप अपनी

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

बात कहना। भजन लाल जी की कोई बात रिकॉर्ड न की जाये। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Question is—

That the Harayana Appropriation (No.1) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the house will consider the Bill Clause by Clause.

Clause - 2

Mr. Speaker : Question is—

That the Clause-2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause - 3

Mr. Speaker : Question is—

That the Clause-3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Schedule

Mr. Speaker : Question is—

That Schedule be the Schedule of the Bill.

The motion was carried.

Clause - 1

Mr. Speaker : Question is—

That the Clause-1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Finance Minister will move that the Bill be passed.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh) : Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(ii) चौधरी देवी लाल यूनिवर्सिटी सिरसा बिल, 2003

Mr. Speaker : Now, the Education Minister will introduce Chaudhary Devi Lal University Sirsa Bill, 2003 and will also move the motion for its consideration.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh) : Sir, I beg to introduce Chaudhary Devi Lal University Sirsa Bill, 2003.

Sir, I also beg to move—

That Chaudhary Devi Lal University Sirsa Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved —

That Chaudhary Devi Lal University Sirsa Bill be taken into consideration at once.

श्री धर्मबीर सिंह : स्पीकर साहब, आप हमारी बात सुनिये। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० रघुबीर सिंह कादियान : स्पीकर साहब, हम अपनी बात कहना चाहते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर साहब, हम इस पर बोलना चाहते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये। क्या सारे एक साथ ही बोलोगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री धर्मबीर सिंह (तोशाम) : अध्यक्ष महोदय, आप हमारी बात सुनिये। इस बारे में मेरा कहना है कि भिवानी जिले को रोहतक यूनिवर्सिटी के साथ ही रहने दिया जाये। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर साहब, आप हमारी बात तो सुनें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप सभी सदस्य बैठें।

श्री धर्मबीर सिंह : सर, भिवानी जिले को रोहतक यूनिवर्सिटी के साथ ही रहने दिया जाये। चौधरी देवी लाल यूनिवर्सिटी जो बनाने जा रहे हैं यदि उसके साथ हमारे जिले को जोड़ा जायेगा तो हमें 150 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कैप्टन साहब, आप क्या कहना चाहते हैं, आप बोलिये।

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर साहब, मैं यह कहना चाहता हूँ कि—(शोर एवं व्यवधान)

प्रो० सम्पत सिंह : स्पीकर साहब, ये कौन सी क्लाज पर बोलना चाहते हैं। पहले आप क्लाज पढ़ें कि कौन सी क्लाज पर आपको एतराज है। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अजय सिंह यादव (रिवाड़ी) : स्पीकर साहब, रिवाड़ी रिजनल सैंटर को अपग्रेड करने की बात करके जो यूनिवर्सिटी चौधरी देवी लाल जी के नाम से बना रहे हैं इसमें मेरा कहना है कि रिवाड़ी जिले का जो रिजनल सैंटर है उसका आफिस वहां पर 1995 में एस्टेब्लिश हो गया था। हमारे दक्षिणी हरियाणा में चार जिले आते हैं। वहां पर कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। मेरा आपसे यह कहना है कि वहां पर एक चौथाई जनता रहती है इसलिए वहां पर भी इन चार जिलों में से किसी एक जिले में यह यूनिवर्सिटी खोली जाये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यूनिवर्सिटी डिस्ट्रिक्ट वाइज नहीं हुआ करती। आप बैठिये। (शोर एवं व्यवधान) जहां जरूरत होती है वहां बनायी जाती हैं। अब आप बैठिये। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अजय सिंह यादव : सर, वहां पर 4 जिले पड़ते हैं। आपके हिसार में दो यूनिवर्सिटी हैं, एक रोहतक में है, एक कुरुक्षेत्र में है जबकि हमारे इन चार जिलों में कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। हमारी मांग है कि रिवाड़ी के अन्दर भी कोई यूनिवर्सिटी खोली जाये। मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री से पुनः अनुरोध करूंगा कि हमारे एरिया में यूनिवर्सिटी खोली जाये।

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, कैप्टन साहब को मैं यह बताना चाहूँगा कि कम से कम एक यूनिवर्सिटी बढ़ रही है। किसी भी अच्छे काम में तो सराहना करनी चाहिए। आपको दिक्कत क्या हो रही है। (शोर एवं व्यवधान) एक अलग से यूनिवर्सिटी बन रही है आपने उसका समर्थन करना चाहिए। आपका समर्थन मिला और ज्यादा प्रोग्रेस की तो हरेक डिस्ट्रिक्ट में भी ये यूनिवर्सिटी बन सकती है। एजुकेशन को बढ़ावा मिल रहा है। हम एजुकेशन को बढ़ावा देने के पक्षधर हैं। ज्यादा से ज्यादा सुविधा लोगों को मिले। आपकी सुविधाओं को ध्यान में रख कर निर्णय लेंगे। जो यूनिवर्सिटी बनने जा रही है उसे बनने दीजिए। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अजय सिंह यादव : चौधरी साहब, मैं इसका समर्थन कर रहा हूँ। मैं इसके विरोध में नहीं कह रहा। यूनिवर्सिटी बननी चाहिए। हमारा तो कहना यह है कि साऊथ हरियाणा में कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, इसलिए वहां पर कोई यूनिवर्सिटी बनायी जाये।

चौधरी भजन लाल : ये यूनिवर्सिटी बनाने के खिलाफ नहीं हैं। ये जो कह रहे हैं कि इनके उन इलाके के लोगों को जो तकलीफ है यानि उनके जो कॉलेज हैं वे रोहतक यूनिवर्सिटी के साथ ही अटैच रहने चाहिए, ये तो यह कह रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

प्रो० सम्पत सिंह : स्पीकर साहब, ये बोलने से पहले कोई क्लाज तो बताएं कि किस क्लाज पर बोल रहे हैं। इसमें ऐसी कौन सी एतराज वाली बात है। (शोर एवं व्यवधान)

चौधरी भजन लाल : इनके जो कॉलेज रोहतक यूनिवर्सिटी के साथ अटैच थे और उन्हें अब चौधरी देवी लाल यूनिवर्सिटी के साथ अटैच करने की बात है उसको आप मान लीजिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : चौधरी भजन लाल जी आप मेरी बात सुनिये। गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी का जो हश्र हुआ है, क्या वही हश्र इस यूनिवर्सिटी का करवाना चाहोगे। वह यूनिवर्सिटी सिमट कर रह गई। वह कहीं से फली-फूली नहीं। यह तो गनीमत हुई कि सरकार बदल गई और हमने

[श्री ओम प्रकाश चौटाला]
उसको थोड़ा बहुत प्रोत्साहित किया नहीं तो आप और हम दोनों रोया करते थे, इस टोपी वाले से। यह हमारी कोई बात नहीं सुना करता। आपको याद नहीं है कि उसकी क्या हालत हो गई थी। हम एजुकेशन को बढ़ावा दे रहे हैं, यह यूनिवर्सिटी ठीक बन रही है, इसे बनने दीजिए, इसमें आपको आपत्ति क्या है। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अजय सिंह : इसमें एतराज यही है कि सारी की सारी यूनिवर्सिटी एक तरफ खोल दी गई हैं, यह ठीक नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Question is—

That Chaudhary Devi Lal University Sirsa Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now the House will consider the Bill Clause by Clause.

Sub Clause-2 of Clause-1

Mr. Speaker : Question is —

That Sub Clause - 2 of Clause - 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clauses-2 to 36

Mr. Speaker : Question is —

That Clauses-2 to 36 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Schedule

Mr. Speaker : Question is —

That Schedule be the Schedule of the Bill.

The motion was carried.

Sub Clause (1) of Clause-1

Mr. Speaker : Question is —

That Sub Clause (1) of Clause-1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is —

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is —

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, a Minister will move that the Bill be passed.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh) : Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is —

That the Bill be passed

The motion was carried.

(iii) दि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी (अमैंडमैंट) बिल, 2003

Mr. Speaker : Now, a Minister will introduce the Kurukshetra University (Amendment) Bill, 2003 and will also move the motion for its consideration.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh) : Sir, I beg to introduce the Kurukshetra University (Amendment) Bill, 2003.

Sir, I also beg to move—

That the Kurukshetra University (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Kurukshetra University (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा (किलोई) : अध्यक्ष महोदय, इस बिल की क्लाज 3 में दिया हुआ है कि "Section 11-A of the principle Act shall be omitted" इसके बारे में मुझे चर्चा करनी है इसके अनुसार एक पोस्ट प्रो वाईस चांसलर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से खत्म की जानी है और सरकार ने इसके लिए जो कारण दिया है वह खर्चे के कम होने का दिया है। पी०वी०सी० को हटाने से 10 लाख रुपये का खर्चा शायद कम हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो सरकार शिक्षा की तरफ ज्यादा खर्च करना चाहती है लेकिन जहां तक मैं इनकी भावना को समझ सका हूँ इस बारे में मैं बड़े स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि यह बिल खर्च को कम करने के लिए नहीं लाया गया है बल्कि यह तो कुछ व्यक्तियों को हटाने के लिए लाया गया है। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, चूंकि यह बिल व्यक्तियों को हटाने के लिए लाया गया है इसलिए इस बिल का हम विरोध करते हैं।

चौ० जय प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, *********

श्री अध्यक्ष : जय प्रकाश जी, आप बैठें, (विघ्न) इनकी कोई बात रिकॉर्ड न की जाए।

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से विपक्ष के नेता और सभी सम्मानित सदस्यों को तथ्यों से जानकारी हासिल करवाने की कोशिश करूंगा। इनके दिमाग में जो बात बिठाई गई है वह गलत बिठाई गई है। यह बिल किसी दुर्भावना से नहीं लाया गया है बल्कि बचत के दृष्टिगत लाया गया है। यहां पर मैं यह कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से यह बिल परो वाईस चांसलर का पद हटाने के लिए बनाया गया है वह पहले कैबिनेट में आया था और कैबिनेट ने सर्वसम्मति से निर्णय ले कर यह तय किया था कि पी०वी०सी० के पद को समाप्त कर दिया जाए। वाईस चांसलर और परो वाईस चांसलर के आपस में मतभेद रहते हैं जिसकी वजह से काम में रुकावट आती है। अध्यक्ष महोदय, तीन सौ से अधिक यूनिवर्सिटीज इस देश में हैं और इनमें से करीब 23 यूनिवर्सिटीज में ही पी०वी०सी० की पोस्ट है। इससे आगे बढ़ कर मैं आपको एक बात और बताऊं परो वाईस चांसलर ने स्वयं ही लिखित रूप में यह कहा है कि इस पद को हटा दिया जाए। यह ठीक है कि इसमें 10 लाख रुपये की बचत भी होगी और हमें बचत करनी भी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, हम चाहते हैं कि मतभेदों की वजह से बच्चों की शिक्षा में फर्क न पड़े इसलिए हम यह बिल लाए हैं इसमें हमारी कोई बदनीयती नहीं है, हमारी भावना अच्छी है और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके इसके दृष्टिगत यह बिल लाया गया है। यह ठीक है कि अगर इन्होंने हर बात में सरकार का विरोध करना है तो करें लेकिन अगर कोई अच्छी बात हो तो उसको इन लोगों को मान लेना चाहिए।

Mr. Speaker : Question is—

That Kurukshetra University (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Clauses-2 to 6

Mr. Speaker : Question is—

That Clauses-2 to 6 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause - 1

Mr. Speaker : Question is—

That Clause-1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

Title

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Finance Minister will move that the Bill be passed.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh) : Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(iv) दि महर्षि दयानन्द यूनिवर्सिटी (अमैंडमैंट) बिल, 2003

Mr. Speaker : Now, a Minister will introduce the Maharshi Dayanand University (Amendment) Bill, 2003 and will also move the motion for its consideration.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh) : Sir, I beg to introduce the Maharshi Dayanand University (Amendment) Bill, 2003

Sir, I also beg to move—

That the Maharshi Dayanand University (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Maharshi Dayanand University (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

डॉ० रघुबीर सिंह कादियान (बेरी) : अध्यक्ष महोदय, इस बिल में यह जो परो वाईस चांसलर की पोस्ट के बारे में जिक्र आया है मैं उसके बारे में कहना चाहता हूँ। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, पिछले बिल पर बोलते हुए यह जो दो आफिसर्ज के बीच में मतभेद वाली बात आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने कही है, ऐसे तो सरकार के अन्दर ऊपर से लेकर नीचे तक कई आफिसर्ज में डिफरैंसिज होते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि उनको हटाने के बारे में विचार कर लिया जाए। मेरे ख्याल से जब ये परो वाईस चांसलर की पोस्ट क्रिएट की गई थीं तो क्या उस वक्त इस पोस्ट को क्रिएट करते हुए वहां पर वर्क लोड को नहीं देखा गया था कि इस पोस्ट की जरूरत है कि नहीं है। इस बारे में हमें बता दिया जाए।

श्री अध्यक्ष : कादियान जी, यह तो वक्त की बात होती है। जब चौधरी भजन लाल जी मुख्य मंत्री होते थे तो उस वक्त पंचायत का समय 2 साल रिड्यूस किया गया था और उसके बाद फिर से 5 साल किया गया था। यह तो समय की मांग के अनुसार प्रावधान होता रहा है। (विघ्न) अब आप बैठ जाएं। आपको महर्षि दयानन्द यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ बोलना है तो बोलें। (विघ्न) नहीं, नहीं, अब आप बैठ जाएं।

Mr. Speaker : Question is—

That the Maharshi Dayanand University (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Clauses - 2 to 6

Mr. Speaker : Question is—

That Clauses-2 to 6 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause - 1

Mr. Speaker : Question is—

That Clause-1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Finance Minister will move that the Bill be passed.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh) : Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(v) दि हरियाणा म्यूनिसिपल (अमैंडमैंट) बिल, 2003

Mr. Speaker : Now, the Minister of State for Urban Development will introduce the Haryana Municipal (Amendment) Bill, 2003 and will also move the motion for its consideration.

शहरी विकास राज्य मंत्री (श्री सुभाष गोयल) : अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2003 प्रस्तुत करता हूँ।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूँ कि—

हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Haryana Municipal (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

कैप्टन अजय सिंह यादव (रिवाड़ी) : स्पीकर साहब, इस बिल में क्लॉज 2 की सैक्शन (ii) का जो प्रोविजो है—

"Provided that the State Election Commission shall consult the State Government before announcing the date of elections.

मेरा इस बारे में कहना यह है कि जो स्टेट इलैक्शन कमीशन है वह एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, एक इंडीपैंडेंट बॉडी है इसलिए इसमें चेंज करना ठीक नहीं है। क्या इलैक्शन कमीशन को मालूम नहीं है कि इलैक्शन किस डेट को करवाने हैं उसके पास पूरा स्टाफ है। मुझे लगता है कि यह आज की ही बात नहीं है कल को और भी स्टेट में गवर्नमैंटस आएंगी इसलिए कल को सबको दिक्कत आ सकती है। इसके आगे कान्सिक्वैन्सिज ठीक नहीं होंगे। होगा यह कि सरकार अपनी मर्जी से इनके इलैक्शन पहले करवा लेगी। जैसे कि हो सकता है कि इनके इलैक्शन आप असैम्बली के इलैक्शन से भी पहले करवा लें। इसलिए एक तो इसमें मेरा यह अन्देशा है।

श्री अध्यक्ष : कैप्टन साहब, आप कौन सी क्लॉज पर बोल रहे हैं।

कैप्टन अजय सिंह यादव : मैं इस बिल की क्लॉज दो के सैक्शन (ii) के प्रोविजो पर बोल रहा हूँ।

"Provided that the State Election Commission shall consult the State Government before announcing the date of elections......"

श्री अध्यक्ष : आप कौन सी क्लॉज पर बोल रहे हैं।

कैप्टन अजय सिंह यादव : मैंने आपके सामने क्लॉज पढ़ी तो है। मैं इस बिल की क्लॉज 2 के सैक्शन (ii) के प्रोविजो पर बोल रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय, आप इसको सीरियसली लें क्योंकि

[कैप्टन अजय सिंह यादव]

इससे बुरी बात नहीं हो सकती। स्टेट कमीशन एक स्टेच्यूटरी बॉडी है इसलिए यह चेंज करना अच्छी बात नहीं है। यह केवल लॉ एंड ऑर्डर की ही बात नहीं है। इसके बाद तो आप अपनी सुविधा के अनुसार काम करेंगे। यह चेंज करना गलत है। इसका मतलब यह है कि जो डेट आपको सूट करेगी वही आप करेंगे। इसमें बहुत ज्यादा राजनैतिक हस्तक्षेप होगा। यह गलत बात है। इसको आप न करें। इलैक्शन कमीशन को पावर होनी चाहिए। जब इनकी टर्म खत्म हो जाए तभी इलैक्शन करवाने के लिए डेट डिक्लेयर होनी चाहिए। यह चेंज करना गलत है।

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : कप्तान साहब, जिस इलैक्शन कमीशन का आप जिक्र कर रहे हो वह तो केवल पंचायत और म्यूनिसिपल कमेटीज का इलैक्शन करवाता है इसमें आपका और मेरा दखल नहीं है। फिर आप क्यों चिन्ता कर रहे हो। इसमें असैम्बली की पावर नहीं है। इसलिए इसमें आपत्ति की क्या बात हो गयी है। चुनाव होते हैं चुनाव की समय सीमा तय है उसके मुताबिक ही चुनाव होते हैं इसलिए इसमें आपको क्या दिक्कत है।

वित्त मंत्री (प्रो० सम्पत सिंह) : स्पीकर सर, इसमें क्लीयर दे रखा है। इसमें सिर्फ कंसलटेशन की बात है कि मान लें कि फ्लड आ गया या कुछ और हो गया तो इसमें डेट की ही बात है। ये तो ऐसा कह रहे हैं जैसे टर्म तीन साल कर रहे हों या पांच साल कर रहे हों। इवन सैंट्रल इलैक्शन कमीशन भी तो स्टेट गवर्नमैंट से इलैक्शन करवाने से पहले बात करता है कि इलैक्शन करवाने के हालात हैं या नहीं। जैसे हिमाचल में अभी दो तीन सीट्स के चुनाव नहीं हुए हैं इसलिए यह तो कोई बात नहीं है इसमें कोई विशेष बात नहीं है। इसमें स्टाफ ही देना होता है और कोई बात नहीं है।

डॉ० रघुबीर सिंह कादियान (बेरी) : अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी ने कहा कि सिर्फ कंसलटेशन की ही बात है। लेकिन बिल में तो लिखा है कि मेन्डेटरी है। मेन्डेटरी और कंसलटेशन में तो फर्क होता है।

श्री अध्यक्ष : कादियान साहब, आप बैठें। ऐसा कहां लिखा है?

डॉ० रघुबीर सिंह कादियान : स्पीकर साहब, इसमें लिखा है।

Mr. Speaker : Question is—

That the Haryana Municipal (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Clause - 2

Mr. Speaker : Question is—

That Clause - 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause - 1

Mr. Speaker : Question is—

That Clause - 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

14-00 बजे

Mr. Speaker : Now, the Minister of State for Urban Development will move that the Bill be passed.

नगर विकास राज्य मंत्री (श्री सुभाष गोयल) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि—

विधेयक पारित किया जाए।

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(vi) दि पंजाब विलेज कामन लैंडज (रेगुलेशन) हरियाणा अमैंडमैंट बिल, 2003

Mr. Speaker : Now, the Parliamentary Affairs Minister will introduce the Punjab Village Common Lands (Regulation) Haryana Amendment Bill, 2003 and will also move the motion for its consideration.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh) : Sir, I beg to introduce the Punjab Village Common Lands (Regulation) Haryana Amendment Bill, 2003.

Sir, I also beg to move—

That the Punjab Village Common Lands (Regulation) Haryana Amendment Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Punjab Village Common Lands (Regulation) Haryana Amendment Bill be taken into consideration at once.

कैप्टन अजय सिंह यादव (रिवाड़ी) : अध्यक्ष महोदय, यह जो अमैंडमैंट लेकर आ रहे हैं सैक्शन-2 की सब क्लॉज-1 (ए) में इसमें यह कहा है कि A panchayat may, with the previous approval of the State Government शामलात लैंड किसी प्राइवेट आदमी को गिफ्ट कर सकते हैं। कोई भी डिस्पैंसरी, अस्पताल या चैरिटेबल अस्पताल के लिए गिफ्ट कर सकते हैं। मेरा कहना है कि सरकार कोई सरकारी अस्पताल बनाए उसके लिए जमीन कोई गिफ्ट कर दे यह ठीक है लेकिन इस तरीके से यदि प्राइवेट लोगों को लैंड देंगे तो यह लैंड को ग्रैब करने का तरीका बन जाएगा। किसी प्राइवेट एजैंसी को या चैरिटेबल के लिए इस तरह लैंड देना गलत है।

प्रो० सम्पत सिंह : स्पीकर साहब, इसमें लिखा है for the benefit of the inhabitants of the village concerned. स्पीकर सर, उसी गांव के बाशिंदे हैं, उनके लिए ग्राम पंचायत जमीन देती है तो यह कोई धक्का नहीं है। चैरिटेबल काम के लिए, स्कूल के लिए, अस्पताल के लिए जमीन कोई दे तो उसका भी ये साथी विरोध करते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, यह कोई तरीका है बिल पास करने का। इस तरह से बुलडोजिंग आप नहीं कर सकते हैं।

वाक - आउट

चौ० भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, आप मैंबर्ज की बात सुनें। यह हमारा निवेदन है। (शोर एवं व्यवधान) अगर हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तो हम वाक-आउट करेंगे।

(इस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदन में उपस्थित सभी सदस्य श्री भजन लाल को छोड़कर सदन से वाक आउट कर गए।)

प्रो० सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, केवल मात्र सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए यह वाक-आउट किया गया है। वैसे ये अपनी सारी बात कह चुके हैं।

चौ० भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, आप अगले बिल को मूव करने से पहले उसके प्रोन्स एंड कौंस मैंबर्ज को बताएं।

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, पूरे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने वाक-आउट नहीं किया है भजन लाल जी यहां बैठे हैं।

चौ० भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो मैं उनके साथ ही हूँ।

विधान कार्य—

(vi) दि पंजाब विलेज कामन लैंडज (रेगुलेशन) हरियाणा अमैंडमैंट बिल, 2003 (पुनरारम्भ)

Mr. Speaker : Question is—

> That the Punjab Village Common Lands (Regulation) Haryana Amendment Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clause - 2

Mr. Speaker : Question is—

That Clause-2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause - 1

Mr. Speaker : Question is—

That Clause-1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Parliamentary Affairs Minister will move that the Bill be passed.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh) : Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, मैं इसको थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं। सरकार की मंशा कहीं बुरी नहीं है। ओशी चौहान गांव में स्पोर्टस कम्पलैक्स बन रहा है उसके लिए भी सरकार ने पैसे दिए हैं। लेकिन कई जगह गांव के लोग अपने फायदे के लिए अगर स्वयं प्रस्ताव पास करके भेजते हैं तो उसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। सरकार कहीं कोई जमीन नहीं बेच रही है। (विघ्न) चौधरी भजन लाल जी आप इन अनपढ़ों में कहां फंस गये। अब क्या बतायें आपकी सरकार के वक्त में पहले जो कानून था उस समय प्राइवेट लोगों को भी जमीन दी गई थी और कौड़ियों के दाम पर दी गई थी। गांवों में जितने भी लोगों को शामलात की जमीन दी हुई है उस पर किसी ने डेयरी खोल रखी है किसी ने डिसपैंसरी आदि खोल रखी है। हमारी सरकार तो अगर सरकारी जमीन भी लेती है तो उसका पैसा देती है। हम तो गांव के विकास के पक्षधर हैं। हम यह मानकर चलते हैं कि अगर गांव की प्रोपर्टी समाप्त हो जायेगी तो गांव का काम नहीं चल पायेगा। जो गांव की जमीन ली

[श्री ओम प्रकाश चौटाला]
जाती है उसका पैसा गांव की पंचायत के खाते में जमा कराया जाता है। हमारी मंशा बुरी नहीं है लेकिन कई जगह ऐसा होता है कि गांव के लोग स्वेच्छा से यह कहते हैं कि हम इस जमीन को देने के लिए तैयार हैं हमारी सुविधा के लिए यहां पर यह चीज बने। वैसे बिना समझे ही कोई चल पड़े तो उसका कोई इलाज क्या है।

चौ० भजन लाल (आदमपुर) : स्पीकर साहब, थोड़ा सा संशय इस बात का है कि गांव की जमीन का रैजोल्यूशन पास करवा लिया जाता है मिसाल के तौर पर ये मुख्य मंत्री हैं यह डी०सी० को आदेश दे दें कि इस गांव की पंचायत का रैजोल्यूशन पास करवा कर भिजवा दें तो वह इस प्रस्ताव को पास करा देंगे।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मौजूदा सरकार ने जो नाजायज इंक्रोचमेंट हैं उसके लिए हमने बड़े खुलकर यह कहा है कि ओपन जगह में किसी ने जाने-अनजाने में अपने मकान बना लिए और किसी को आवागमन में उससे कोई दिक्कत नहीं है तो उसका मकान हम तोड़ेंगे नहीं बल्कि जितनी जमीन को उसने इन्क्रोचमैंट कर रखी है हम उसकी कीमत तय करेंगे। इसके साथ यह हिदायत दी है कि डी०सी० पंचायत की सहमति से उस जमीन की कीमत तय करेंगे और जो पैसा मिले उसे पंचायत के खाते में जमा करायें और हम उस आदमी के नाम उस जमीन की रजिस्ट्री करायेंगे। हमारी ऐसी मंशा है हम गांव की सुविधा के हिसाब से करते हैं हमें पता है हमने गांव का जीवन देखा है आपने तो मौज लूटी है। कहां आप गांव में गये हो।

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(vii) दि हरियाणा पंचायती राज (अमैंडमैंट) बिल, 2003

Mr. Speaker : Now, a Minister will introduce the Haryana Panchayati Raj (Amendment) Bill, 2003 and will also move the motion for its consideration.

नगर विकास राज्य मंत्री (श्री सुभाष गोयल) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2003 प्रस्तुत करता हूँ—

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूँ—

कि हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Haryana Panchayati Raj (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is—

That the Haryana Panchayati Raj (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Clauses - 2 to 4

Mr. Speaker : Question is—

That Clauses - 2 to 4 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause -1

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, a Minister will move that the Bill be passed.

नगर विकास राज्य मंत्री (श्री सुभाष गोयल) : स्पीकर सर, मैं प्रस्ताव करता हूँ —

कि विधेयक पारित किया जाए।

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(viii) दि हरियाणा म्यूनिसिपल कारपोरेशन (अमैंडमैंट) बिल, 2003

Mr. Speaker : Now, the Minister of State for Urban Development will introduce the Haryana Municipal Corporation (Amendment) Bill, 2003.

नगर विकास राज्य मंत्री (श्री सुभाष गोयल) : अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2003 प्रस्तुत करता हूँ।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूँ—

कि हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाये।

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Haryana Municipal Corporation (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is—

That the Haryana Municipal Corporation (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now the House will consider the Bill Clause by Clause.

Clauses - 2 & 3

Mr. Speaker : Question is —

That Clauses-2 and 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-1

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Minister of State for Urban Development will move that the Bill be passed.

नगर विकास राज्य मंत्री (श्री सुभाष गोयल) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ—

कि विधेयक पारित किया जाये।

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(ix) गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार (अमैंडमैंट) बिल, 2003

Mr. Speaker : Now, a Minister will introduce Guru Jambheshwar University, Hisar (Amendment) Bill, 2003 and will also move the motion for its consideration.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh) : Sir, I beg to introduce Guru Jambheshwar University, Hisar (Amendment) Bill, 2003.

Sir, I also beg to move—

That Guru Jambheswar University, Hisar (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That Guru Jambheswar University, Hisar (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is—

That Guru Jambheshwar University, Hisar (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Clauses - 2 to 4

Mr. Speaker : Question is—

That Clauses - 2 to 4 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-1

Mr. Speaker : Question is—

That Clause-1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, a Minister will move that the Bill be passed.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh) : Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(x) दि पंजाब एक्साईज (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 2003

Mr. Speaker : Now, a Minister will introduce the Punjab Excise (Haryana Amendment) Bill, 2003 and will also move the motion for its consideration.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh) : Sir, I beg to introduce the Punjab Excise (Haryana Amendment) Bill, 2003.

Sir, I also beg to move—

That the Punjab Excise (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Punjab Excise (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is—

That the Punjab Excise (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Clause - 2 to 13

Mr. Speaker : Question is—

That Clauses-2 to 13 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause - 1

Mr. Speaker : Question is—

That Clause-1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, a Minister will move that the Bill be passed.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh) : Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(xi) दि रेवेन्यू रिकवरी (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 2003

Mr. Speaker : Now, a Minister will introduce the Revenue Recovery (Haryana Amendment) Bill, 2003 and will also move the motion for its consideration.

नगर एवं ग्राम आयोजना मंत्री (श्री धीरपाल सिंह) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्व वसूली (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2003 प्रस्तुत करता हूँ।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूँ—

कि राजस्व वसूली (हरियाणा संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाये।

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Revenue Recovery (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is—

That the Revenue Recovery (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Clause - 2

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause - 1

Mr. Speaker : Question is—

That Clause-1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, a Minister will move that the Bill be passed.

नगर एवं ग्राम आयोजना मंत्री (श्री धीरपाल सिंह) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ—

कि विधेयक पारित किया जाये।

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(xii) दि हरियाणा जनरल सेल्ज टैक्स (अमैंडमैंट) बिल, 2003

Mr. Speaker : Now, a Minister will introduce the Haryana General Sales Tax (Amendment) Bill, 2003 and will also move the motion for its consideration.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh) : Sir, I beg to introduce the Haryana General Sales Tax (Amendment) Bill, 2003.

Sir, I also beg to move—

That the Haryana General Sales Tax (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Haryana General Sales Tax (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is—

That the Haryana General Sales Tax (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Sub-Clause (2) of Clause-1

Mr. Speaker : Question is—

That Sub-Clause (2) of Clause-1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clauses - 2 & 3

Mr. Speaker : Question is—

That Clauses-2 & 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Sub-Clause - 1 of Clause - 1

Mr. Speaker : Question is—

That Sub-Clause-1 of Clause-1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now a Minister will move that the Bill be passed.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh) : Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(xiii) दि हरियाणा वैल्यू एडिड टैक्स बिल, 2003

Mr. Speaker : Now, a Minister will introduce the Haryana Value Added Tax Bill, 2003 and will also move the motion for its consideration.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh) : Sir, I beg to introduce the Haryana Value Added Tax Bill, 2003

Sir, I also beg to move—

That the Haryana Value Added Tax Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Haryana Value Added Tax Bill be taken into consideration at once.

कैप्टन अजय सिंह यादव (रिवाड़ी) : स्पीकर साहब, मेरा कहना यह है कि आप जो यह वैट का बिल ला रहे हैं यह बात तो ठीक है कि पूरे देश में यूनिफार्म टैक्स हो जायेगा जैसा कि शैड्यूल बी० और सी० बना रखा है। मेरा इसमें कहना यह है कि जो हमारी स्टेट है वह मैन्युफैक्चरिंग स्टेट है और दिल्ली के साथ लगती है। आपके कहे के अनुसार यहां पर मैक्सिमम इण्डस्ट्रीलाइजेशन हो रही है। (विघ्न) मैं यह कह रहा हूँ कि बहुत सारी इण्डस्ट्रीज यहां पर लग रही हैं जैसा कि आपने हमें बताया है। अध्यक्ष महोदय, जो सैन्ट्रल टैक्स है वह पहले साल में 100 परसैंट होगा, दूसरे साल में 75 परसैंट होगा और तीसरे साल में 25 परसैंट हो जायेगा। इसमें मेरा यह कहना है कि 3 साल के बाद आप जीरो लैवल पर आ जाओगे। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : आप कौन सी क्लॉज पर बोल रहे हैं।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अभी तो जनरल बोल रहा हूँ। मैं क्लाजवाईज भी आऊंगा। अगर सेल्ज टैक्स में हम जीरो परसैंट पर आ गए तो यह ठीक नहीं होगा क्योंकि हमारी स्टेट मैन्युफैक्चरिंग स्टेट है। वित्त मंत्री जी यह बता दें कि सी०एस०टी० कितना मिलता है। मेरे हिसाब से एक करोड़ रुपया मिलता होगा। इसके लागू हो जाने के 3 साल के बाद आपको सैंट्रल सेल्ज टैक्स का पैसा बिल्कुल नहीं मिलेगा क्योंकि आप जीरो लैवल पर आ जाओगे। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि इसमें आपका पेपर वर्क बहुत बढ़ जायेगा। इसमें आपने लम्प-सम का जिकर किया है। मेरा यह भी कहना है कि इसमें आपने इसके सैक्शन 11 में रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन की भी कंडीशन रखी है। कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति सेल्ज टैक्स का नम्बर रजिस्टर करवायेगा उससे आप 500 रुपये लेंगे। आप देखें कि जो छोटे दुकानदार हैं या छोटा आदमी है उसके लिए यह राशि देनी मुश्किल हो जायेगी, इस पर आपको विचार करना चाहिए। इसके अलावा स्पीकर साहब, इस में पैनल्टी भी दिखाई है कि यदि कोई 90 दिन के अन्दर-अन्दर नहीं आयेगा तो उस पर 3 परसैंट पैनल्टी लगायी जायेगी। यदि इसी प्रकार से आप यह करते रहे तो इससे व्यापारियों को दिक्कत हो जायेगी। इस बारे में मैं आपको इसके सैक्शन 28 के बारे में बताना चाहूँगा। सर, सैक्शन 28 की सब क्लॉज डी देखिए। इसमें लिखा है—

> "(d) preserve a carbon copy of every invoice or delivery note issued under clause (a) or clause (c) for a period of eight years following the close of the year when the sale was made and where some proceedings under this Act are pending, till the completion of such proceedings."

मेरे कहने का मकसद यह है कि वह आठ साल तक अपना रिकॉर्ड उठा कर रखेगा। इसमें यह भी कहा गया है कि अगर आई दी के वह चीज नहीं मिलती तो फिर पैनल्टी लगायी जायेगी। यदि आप आठ साल से ज्यादा कर देंगे तो फिर यह पैनल्टी डेढ़ से तीन परसैंट कैसे रखी है। इस बारे में मेरा कहना है कि ऐसे करने से तो पेपर वर्क बढ़ेगा और इन्सपैक्टरी राज बढ़ेगा और यह ट्रेडर्ज के लिए एक टूल ऑफ हासमैंट हो जायेगी। दूसरे आपने अनक्लेमड गुड्ज के बारे में कह रखा है। सैक्शन 29 की क्लॉज 7 में आपने कह रखा है कि आई दी के अगर कोई गुड्ज कहीं पर कोई लेकर जाए या आपने छापा मार दिया और वहां पर किसी ने उसको अण्डर वैल्यू दिखा दिया तो सारा फाइनैंस जोड़ कर यह टोटल डिस्क्रिशन उस अधिकारी का हो जाएगा और वह कह देगा कि उसकी इतनी प्राइस है तथा तीन टाइम मल्टीप्लाई करके खुद पैनल्टी लगा देगा। इसका मतलब यह है कि करप्शन का एक और द्वार खुल जाएगा इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि बिल में इस प्रकार की क्लाजें

[कैप्टन अजय सिंह यादव]

न लगाएं बल्कि इसे टोटली सिम्पलीफाई करें। इसके बारे में मेरा यह भी कहना है कि इसमें आपने काण्ट्रैक्टर्ज को भी ले लिया और सब काण्ट्रैक्टर्ज को भी ले लिया। एक और गलत बात जो इस बिल में है वह इसके शैड्यूल के सैक्शन सी में है। इसमें आपने माचिस के ऊपर भी 4% टैक्स लगा दिया फायर वर्क्स पर भी टैक्स लगा दिया और जो हाउस होल्ड यूटैंसिल्ज हैं उस पर भी आपने 4% टैक्स लगा दिया। इस प्रकार का जो टैक्स लगाने की बात आप कह रहे हैं इसके बारे में मेरा कहना यह है कि हालांकि यह बिल हमें कल ही मिला उसके बावजूद भी हमने इसे देखने की कोशिश की है लेकिन इसको देखने का ज्यादा समय नहीं मिला। मेरा कहना यह है कि इस पर एक सिलैक्ट कमेटी बनाएं और जल्द बाजी में इस बिल को पास न करके उस सिलैक्ट कमेटी को सौंप दें। हमारी दिल्ली गवर्नमैंट ने भी इसको तीन महीने के लिए डैफर कर दिया है इसलिए मेरा निवेदन है कि आप भी इस बिल को डैफर करें और एक सिलैक्ट कमेटी बना कर इस पर थौरो डिस्कशन करें। ट्रेडर्ज से उनकी राय लेकर उसके बाद इस बिल को पास करें। मैं इस बिल का विरोध करता हूँ यह बिल ठीक नहीं है और हरियाणा स्टेट के लिए भी यह ठीक नहीं है। (विघ्न)

श्री कर्ण सिंह दलाल (पलवल) : सर, हरियाणा वैल्यू एडिड टैक्स का बिल अभी प्रो० सम्पत सिंह जी ने इण्ट्रोड्यूस किया है। कैप्टन साहब ने जो बातें इस बारे में बताई हैं मैं उनका समर्थन करता हूँ और आपके माध्यम से सरकार को यह सुझाव देता हूँ कि जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि वैट का जो इण्ट्रोडक्शन है यह यूरोपीय देशों में ज्यादा चलता है। यूरोप की ज्योग्रोफिकल और व्यापारिक स्थिति है वह और तरह की है। वहां के लोगों की जो व्यापारिक स्थिति है वह हमारे से बिल्कुल भिन्न है। अध्यक्ष महोदय, इसमें बड़े तरीके से जो मल्टीनैशनल कम्पनीज हैं उन्होंने अपने दवाब में एक यह तरीका बनाने की कोशिश की क्योंकि आज तक जो टैक्स लगता था एक्साईज के नाम पर वह जहां गुडज का प्रोडक्शन होता था उसकी ड्यूटी वहां पर लगाई जाया करती थी और उसमें कोई चोरी या किसी और तरीके की बात का भी प्रावधान नहीं था। अब उन बड़े-बड़े लोगों ने क्या सोचा कि अपनी आफत को छोटे व्यापारियों के ऊपर डालने के लिए यह वैल्यू एडिड टैक्स का सिस्टम उन्होंने बनवाया है। यह ठीक है कि यह टैक्स सारे देश के अन्दर प्रभावी होगा इसमें कोई दो राय नहीं हैं। स्पीकर सर, महाराष्ट्र में और केरल में भी यह बिल इण्ट्रोड्यूस हुआ था वहां पर यह फेल हुआ दिल्ली में भी इन्ट्रोड्यूस हुआ वहां पर भी उसको वापिस किया गया। अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि इससे छोटे व्यापारियों की शामत आएगी। कैप्टन साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है कि इस बिल से इन्सपैक्टरी राज को बढ़ावा मिलेगा और इसमें मुकदमा दर्ज करने का भी प्रोविजन है। (विघ्न) इसको लेकर अगर व्यापारियों के विरुद्ध मुकदमे दर्ज होंगे तो फिर क्या व्यवस्था रह जाएगी।

श्री अध्यक्ष : अगर कहीं पर कोई ओफैंस कमिट होगा तो उसके खिलाफ पुलिस की कार्यवाही तो होगी ही।

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर साहब, व्यापारियों के साथ बैठ कर सरकार बात करे अगर सरकार इस बिल को लाना ही चाहती है तो आपके माध्यम से मेरा सरकार से निवेदन है कि इसमें मुकदमे की बात वापिस ले ली जाए।

प्रो० सम्पत सिंह : स्पीकर सर, इसमें मुकदमे की बात कहां पर है, कौन सी सजा है, यह तो बताएं कहां पर कौन सी क्लॉज है?

श्री कर्ण सिंह दलाल : चैप्टर 8 में सैक्शन 37 पर आप देखें मैं इसे पढ़ देता हूँ :

"An officer appointed to assist the Commissioner under sub-section (1) of section 55 shall, for the purpose of investigation of all or any of the offences punishable under this Act, have the powers conferred by the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974), upon an officer in charge of a police station for the investigation of a cognizable offence."

प्रो० सम्पत सिंह : यह तो पुराना एक्ट है इसमें कोई नई चीज नहीं है।

श्री कर्ण सिंह दलाल : लेकिन आप इसमें साथ लगा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, अगर व्यापारियों पर मुकद्दमे दर्ज होंगे तो व्यापारियों की हालत खराब होगी। अध्यक्ष महोदय, सरकार व्यापारियों के नुमाइन्दों को बुलाए और उनके साथ बैठ कर बात करें। बात करके उनको सारे प्रोविजन बताइये और उसके बाद जो सलाह वे दें उसको विचार करके इस बिल को आप ले आना। आप इस बिल को अगले सैशन में ले आना यह मेरी सबमिशन है।

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, किसान भी अगर रिकवरी नहीं देता तो पंजाब लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 11 डी के तहत उसकी भी सजा है, यह नहीं है कि किसान को कोई सजा नहीं है कानून तो कानून के हिसाब से ही चलेगा। अगर कोई ओफैन्स कमिट करता है तो कानून अपना काम करेगा। अब आप बैठें।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष : यदि हाउस की सहमति हो तो हाउस का समय 15 मिनट के लिए बढ़ा दिया जाए।

आवाजें : ठीक है जी।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, हाउस का समय 15 मिनट के लिए बढ़ाया जाता है।

विधान कार्य—

(xiii) दि हरियाणा वैल्यू एडिड टैक्स बिल, 2003 (पुनरारम्भ)

श्री अनिल विज (अम्बाला छावनी) : अध्यक्ष महोदय, यह सरकार इस बात के लिए बधाई की पात्र है कि जो व्यापारियों के मन में शंका थी कि इसमें सजा का प्रावधान रखा जाएगा। जो ड्राफ्ट बिल सारे हिन्दुस्तान में केन्द्र द्वारा बनाया गया है, उसमें भी सजा का प्रावधान था। इस सरकार ने सजा का प्रावधान इसमें नहीं रखा है। लेकिन लोगों और व्यापारियों के मन में इस बिल के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। इस बारे में मैंने पहले भी बोलते हुए कहा था कि जब भी कोई चीज इन्ट्रोड्यूस की जाती है तो उसमें कई स्टीचिंग प्रोब्लम्ज होती हैं, उनके बारे में हमें जरूर समझना चाहिए। उन प्रोब्लम्ज को ध्यान में रखते हुए, उसको इन्ट्रोड्यूस करने से पहले हमें स्थान-स्थान पर कुछ सैमीनार्ज आर्गनाइज करने चाहिए ताकि इस नई पद्धति के बारे में व्यापारियों को अच्छी तरह से बताया जा सके इसमें विशेष तौर से जो सैक्शन 2(1)(c) में अप्वायंटिड डे है—

" "appointed day" means the 1st day of April, 2003, unless declared,

[श्री अनिल विज]

> by notification in the Official Gazette, otherwise by the State Government."

स्टेटमैंट ऑफ आब्जैक्टस एंड रीजन्ज में लिखा है कि :—

> "As a part of reforms in the field of domestic trade taxes in the country all the States have agreed to introduce value added tax (for short 'VAT') simultaneously with effect from 1-4-2003."

और इसमें कहा गया है लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। हमारे साथ लगती स्टेट ने भी यही कहा है कि हम इसको नैक्सट क्वार्टर से 3 महीने बाद लागू करेंगे। मैं यह कहना चाहता हूँ कि इसको लागू करने में इतनी जल्दी न की जाए। इसमें जो अप्वायंटिड डे फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल लिखा गया है इसको अमैन्ड किया जाए। यह बिल जब सारे देश में पारित हो जाए। सारे देश में एक तारीख तय करके इकट्ठा ही इसको लागू किया जाए। नहीं तो इसमें बहुत सारी कठिनाईयां उत्पन्न हो सकती हैं। दूसरी बात मैं रजिस्ट्रेशन के बारे में कहना चाहता हूँ। रजिस्ट्रेशन के बारे में जो दोबारा से नए सिरे से फार्म दिए जाएंगे, सिक्योरिटी दी जाएगी और फीस दी जाएगी इसको भी इसमें नहीं रखना चाहिए। जो आलरेडी 1973 के रजिस्टर्ड डीलर्ज हैं, उनको इस नए एक्ट के तहत भी रजिस्टर्ड डीलर माना जाना चाहिए। अगर उनको कोई नया नम्बर अलॉट करना है तो बेशक कर दीजिए लेकिन जो दोबारा से नई सिरे से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है, उसमें पुराने रजिस्टर्ड डीलर्ज को न डाला जाए।

श्री मांगे राम गुप्ता (जींद) : अध्यक्ष महोदय, यह जो बिल प्रो० सम्पत सिंह जी लाए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सारे हिन्दुस्तान में हर स्टेट के फाईनैंस मिनिस्टर की सलाह के बाद ही यह फैसला हुआ है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, इस बारे में कल मुख्य मंत्री जी से और सम्पत सिंह जी से बात हुई थी। जब इसके बारे में सारे अखबारों में छपा था उसको आपने पढ़ा होगा जबकि व्यापारियों पर यह टैक्स एक अप्रैल से लागू होने की बात आई उससे पहले सारी स्टेटों के व्यापारी वर्ग ने इसका बड़ा भारी विरोध किया था और हड़तालें हुई थी। इस बारे में व्यापारियों के डैपुटेशन केन्द्र और स्टेट्स के मिनिस्टर्ज से भी मिले हैं। अध्यक्ष महोदय, यह बिल बहुत खतरनाक साबित होगा जिस तरह से कर्ण सिंह दलाल जी भी कह रहे थे। अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने सुना है कि कई स्टेट्स ने अभी इस बिल को डैफर ही किया है और वे लागू नहीं कर रहे हैं। हरियाणा की सरकार हरियाणा के हर व्यक्ति की हर वर्ग की भलाई की बात सोचती है तो हरियाणा के व्यापारी भी आपके ही प्रदेश के नागरिक हैं। इसलिए मेरा आपसे यह कहना है कि इस बिल को अभी जल्दी में पास न किया जाए। इसको सारे भारत में एक साथ ही लागू किया जाना चाहिए था और इसका एक यूनिफार्म बिल बनाना चाहिए था। अब हर स्टेट अपने-अपने लैवल पर इसको पास करने जा रही है। इसको लागू करने की डेट हर स्टेट अलग-अलग तय कर रही है। इसमें बहुत बड़ी गड़बड़ देश के अन्दर हो जाएगी। व्यापारी स्ट्राईक पर आ गए हैं, व्यापार का सत्यानाश हो जाएगा। स्टेट का बहुत नुकसान होगा। मेरा अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा वित्त मंत्री जी से निवेदन है कि हाल में इस बिल को रोक लिया जाए और सारे हिन्दुस्तान में व्यापारियों के साथ सलाह करके इसको लागू करें। वरना इसके बहुत बुरे इफैक्ट होंगे।

चौधरी भजन लाल (आदमपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्री जी से और इस सरकार से यह कहना चाहूँगा कि सभी मैम्बर्ज की भावनाओं को देखते हुए आप इस बिल को सिलैक्ट कमेटी

को दे दें और इस पर दोबारा से विचार कर लें। 3–4 महीने बाद फिर से सैशन आएगा उसमें इसको आप पास कर लेना। इससे आपको क्या फर्क पड़ेगा।

मुख्यमंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, कई किस्म की शंकाएं सदस्यों ने व्यक्त की हैं। सरकार की मंशा किसी को परेशान करने की नहीं है। कप्तान साहब ने शंका व्यक्त की कि जब यह बिल पास हो जाएगा तो सैंट्रल सेल्ज टैक्स का पैसा हमारा आना बन्द हो जाएगा। यह चिन्ता हमारी सरकार को भी थी लेकिन इसमें हम क्या करें। यह तो लिब्रेलाइजेशन पॉलिसी के साथ आया। जब भूतपूर्व प्रधान मंत्री पी०वी० नरसिम्हाराव जी लिब्रेलाइजेशन पॉलिसी लेकर आए थे तब यह वैट और यूनिफार्म टैक्स की पॉलिसी भी वे उसके साथ ही लेकर आए थे। (विघ्न) दूसरा विज साहब ने एक और अन्देशा जाहिर किया और कहा कि इस पर दोबारा विचार किया जाए और यह कंसीड्रेशन के लिए लोगों के समक्ष पेश किया जाए। अध्यक्ष महोदय, इस पर विचार तो बहुत लम्बे समय से हो रहा है। सारी प्रादेशिक सरकारों के फाईनेंस मिनिस्टर्ज और हमारे फाईनेंस मिनिस्टर भी कई मर्तबा इस बारे में मीटिंग में गए। बंगाल जहां कम्यूनिस्ट पार्टी की सरकार है जो विशेष रूप से ट्रेडर्ज के खिलाफ होते हैं और जो ज़मींदारों को आज भी बुरजवा कहते हैं, वे तो अपने आपको क्राप पुअर कहते हैं, वे अपने आपको पिछैन्टरी क्लास के लोग कहते हैं वे वर्कर्ज की नुमाइंदगी करते हैं, कर्मचारियों की नुमाइंदगी करते हैं वे इस कमेटी के चेयरमैन हैं। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की सरकार ने ताजा ही इस बारे में बिल पास किया है। जैसा कर्ण सिंह दलाल अंदेशा जाहिर कर रहे थे कि इसमें सजा का प्रावधान है ठीक है इसमें सजा का प्रावधान है। राजस्थान सरकार ने इसमें सजा का प्रावधान किया भी है लेकिन हमारा इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। उन्होंने 6 महीने की सजा का बिल पास किया है। इस प्रकार से जब पूरे देश के स्तर पर ये चीजें होंगी तब आप उससे अलग नहीं हट पाओगे। यूनीफार्म टैक्स का मामला बहुत लम्बे समय तक चला आखिर सभी इस पर सहमत हो गये। सहमत इसलिए हो गये क्योंकि केन्द्र की सरकार ने कहा है इसलिए हम इसको मानेंगे। केन्द्र की सरकार ने हमें यह आश्वासन दिया है कि सैंट्रल सेल्ज टैक्स का जो नुकसान हमारा होगा उसको वे पहले साल में शत प्रतिशत देंगे, दूसरे साल में 75 प्रतिशत देंगे और उसके बाद पचास प्रतिशत देंगे। अध्यक्ष महोदय, कितनी ही केन्द्र की ऐसी योजनाएं हैं जिनमें हमें पहले ग्रांट की शक्ल में सहायता मिलती है लेकिन फिर आहिस्ता–आहिस्ता उसको समाप्त कर दिया जाता है। एक अवसर प्रदान किया जाता है अपने पांव पर खड़े होने का। आज की स्थिति में आपके प्रदेश को इससे कम से कम डेढ़ दो सौ करोड़ रुपये का लाभ होगा और वह लाभ जो है वह किसी से हम जबरदस्ती वसूल नहीं करेंगे बल्कि जो टैक्स की चोरी करते हैं उनसे यह वसूल किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, अब फाईनेंस मिनिस्टर इस बारे में इनकी तसल्ली पूरी तरह से करवा देंगे। हमारी कोई दुर्भावना नहीं है।

वित्त मंत्री (प्रो० सम्पत सिंह) : स्पीकर साहब, मुख्य मंत्री जी ने काफी बात कह दी हैं। मैं इस बारे में कहना चाहूँगा कि यह कोई एक मंत्री या एक कैबिनेट का फैसला नहीं है बल्कि यह सारे हिन्दुस्तान के प्रदेशों के फाईनेंस मिनिस्टर्ज की मीटिंग्ज का फैसला है। इन मीटिंग्ज में सैंट्रल फाईनेंस मिनिस्टर भी आते रहे हैं। यह मामला अब से नहीं है जैसा मुख्य मंत्री जी ने कहा कि माननीय पी०वी० नरसिम्हाराव जी जब प्रधान मंत्री थे तो जैसा मैंने सुबह भी कहा था कि लिब्रेलाइजेशन के इस जमाने में हम आइसोलेशन में नहीं रह सकते। पहले कभी ऐसा जमाना था जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट की तुलना करते थे लेकिन आज तो दुनिया के साथ आपका मुकाबला है। जिस जर्मनी और फ्रांस ने कभी भयंकर लड़ाई लड़ी थी और जिस फ्रांस में आज भी मिलियन बारूद पड़ा होगा उन्हीं फ्रांस और जर्मनी

[प्रो० सम्पत सिंह]

के बीच में आज कोई बोर्डर नहीं है इसलिए वे आज तरक्की कर रहे हैं। यू०एस० डालर से आज यूरो ऊपर जाने लग रहा है यह क्यों हो रहा है यह इसलिए हो रहा है क्योंकि यूरोपियन यूनियन बनी हुई है। अध्यक्ष महोदय, जब वहां ऐसा है तो क्या हम अपने देश में सभी स्टेट्स को एक नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इस तरह के कन्सैप्ट को लेकर यह शुरूआत की गयी थी। यह आज से नहीं बल्कि 1994 से विचार चल रहा है पिछले नौ सालों से इस पर विचार-विमर्श चल रहा है। विचार-विमर्श करके ही जब श्रीमान सिन्हा जी देश के फाईनैंस मिनिस्टर थे तो उस समय प्रधान मंत्री जी ने सभी स्टेट के मुख्य मंत्रियों की एक मीटिंग बुलायी थी और मुख्य मंत्रियों की मीटिंग में ही यह फैसला हुआ था कि एक इमपॉवर्ड कमेटी स्टेट के मिनिस्टर्ज की बनायी जाए और वह कमेटी ही यूनिफार्म सेल्ज टैक्स एवं इंडस्ट्रियल इन्सैंटिव्ज दिए जाते हैं, के बारे में फैसला करे। अध्यक्ष महोदय, आज स्टेट्स में आपस में एक बार लग रही है, एक होड़ सी लग रही है। हरियाणा कहता है कि मैं यह इन्सैंटिव दे दूंगा, पंजाब कहता है कि मैं यह दे दूंगा जबकि यू०पी० कहता है कि मैं वह दे दूंगा। इस तरह से दौड़ लग जाती है। इंडस्ट्रीज वाले कभी इधर कभी उधर चले जाते हैं सबसिडी खाते हैं और बाद में अपनी-अपनी इंडस्ट्रीज बंद करके चले जाते हैं। इस दौड़ को बंद करने के लिए पहले तो यूनिफार्म सेल्ज टैक्स की तरफ चलें और लगभग 205 आईटम्ज पर आलमोस्ट सभी स्टेट एग्री हो गये। इक्के-दुक्के छोटे-मोटे आईटम्ज बचे हुए होंगे नहीं तो लगभग सभी आईटम्ज पर सभी स्टेट्स ने ऐग्री कर लिया है। बहुत बड़ी सफलता उसमें सभी स्टेट्स के फाईनैंस मिनिस्टर्ज के प्रयासों से मिली है सभी पार्टीज के लोग उसमें शामिल हैं और मैक्सिमम उसमें कांग्रेस पार्टी के चीफ मिनिस्टर थे, कांग्रेस पार्टी के फाईनैंस मिनिस्टर थे। आपने जैसा कहा है आप लोग दिल्ली का जिक्र तो कर देते हैं आप पंजाब का जिक्र नहीं कर रहे हैं। पंजाब इसको पास कर चुका है, केरल इसको पास कर चुका है मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार है वे भी इसको पास कर चुके हैं। महाराष्ट्र भी पास कर चुका है। (विघ्न) 23 स्टेट्स ने भारत सरकार को अपने-अपने बिल पास करके भेजे थे। यानि 23 स्टेट्स में ये पास हो गए हैं और जो बाकी प्रदेश रहे हैं वह हैं दिल्ली, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में चुनाव हो रहे थे इस वजह से वहां रह गया अब नयी असैंबली आई है वे भी इस बारे में फैसला लेंगे। इसी तरह से त्रिपुरा और दिल्ली की भी यही पोजीशन है वहां आपस में रस्साकशी चल रही है। केरल, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश इन स्टेट्स में आलरेडी से क्लीयर हो चुके हैं Maharashtra has already imposed VAT on select commodities on a trial basis. महाराष्ट्र ने आलरेडी इसको इम्पोज कर दिया है। मैं तथ्यों पर आधारित बात कह रहा हूँ। हमारे साथी कह रहे हैं कि इसमें सजा की बात है वह राजस्थान में है मुख्य मंत्री जी ने इस बारे में क्लीयर कर दिया है राजस्थान वाले में क्लीयर लिखा हुआ है Tax or in commission of any of the offences as aforesaid ; on a complaint being made against such person by the assessing authority or any other competent officer after having sanction from the Deputy Commissioner (Administration) having jurisdiction, he shall on conviction by a judicial Magistrate having jurisdiction, be punishable with simple imprisonment of which may extend up to three years. तीन साल तक की सजा राजस्थान ने इसमें की है हमने सजा की कोई बात नहीं रखी है हम इस तरह का कोई लॉ नहीं चाहते जिससे व्यापारियों को नुकसान हो। हमने इसको आसान किया है। अभी विपक्ष के साथ पढ़ते-पढ़ते पढ़ गए थे (विघ्न) हमने यह किया है कि तीन महीने तक की देरी करने पर 1.5 परसैंट टैक्स लगेगा और तीन महीने से अधिक की देरी करने पर 3 परसैंट टैक्स लगेगा। पहले यह 150 परसैंट तक लगता था हम तो इसको घटाकर 1.5 और 3 परसैंट कर रहे हैं। इससे बढ़िया बात और क्या होगी कि

जो छोटे व्यापारी हैं जिनकी टर्न ओवर 25 लाख तक थी वे खरीद मूल्य पर सिर्फ एक परसैंट टैक्स अदा करें इतना हमने आसान बनाने की कोशिश की है। सभी स्टेटों से ज्यादा इसे सरल किया गया है। इसमें किसी को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। जहां तक सैमीनार्ज और कांफ्रैंसिज की बात है इसके लिए पिछले 4 साल से व्यापारियों को और ट्रेडर्ज को इसमें ऐजूकेट किया गया है हमारे यहां वैट सिस्टम आलरेडी मैन्यूफैक्चिरिंग में हरियाणा में है और इससे व्यापारियों को फायदा मिलता है जैसे एक स्टेज पर टैक्स पे कर दिया तो उस टैक्स का दूसरी स्टेज पर उनको लाभ मिल जाएगा। इससे बढ़िया कोई नहीं हो सकता इसलिए इसको यूनैनिमसली पास कर देना चाहिए।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष : यदि हाउस की सहमति हो तो हाउस का समय पंद्रह मिनट के लिए बढ़ा दिया जाए।

आवाजें : ठीक हैं जी।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, हाउस का समय पंद्रह मिनट के लिए बढ़ाया जाता है।

विधान कार्य –

(xiii) दि हरियाणा वैल्यू एडिड टैक्स बिल, 2003 (पुनरारम्भ)

Mr. Speaker : Question is—

That the Haryana Value Added Tax Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Sub Clause-2 of Clause-1

Mr. Speaker : Question is—

That Sub Clause-2 of Clause-1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Sub Clause-3 of Clause-1

Mr. Speaker : Question is—

That Sub Clause-3 of Clause-1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clauses-2 to 63

Mr. Speaker : Question is—

That Clauses-2 to 63 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Schedules A to G

Mr. Speaker : Question is—

That Schedules A to G be the Schedules of the Bill.

The motion was carried.

Sub-Clause (1) of Clause-1

Mr. Speaker : Question is—

That Sub-Clause (1) of Clause-1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, a Minister will move that the Bill be passed.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh) : Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(xiv) दि हरियाणा डिवैल्पमैंट एंड रैगुलेशन ऑफ अर्बन एरियाज (अमैंडमैंट) बिल, 2003

Mr. Speaker : Now, the Town and Country Planning Minister will introduce the Haryana Development and Regulation of Urban Areas (Amendment) Bill, 2003 and will also move the motion for its consideration.

नगर एवं ग्राम आयोजना मंत्री (श्री धीरपाल सिंह) : स्पीकर सर, मैं हरियाणा नगरीय क्षेत्र

विकास तथा विनियमन (संशोधन) विधेयक प्रस्तुत करता हूँ—

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूँ—

कि हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Haryana Development and Regulation of Urban Areas (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is—

That the Haryana Development and Regulation of Urban Areas (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Sub-Clause (2) of Clause-1

Mr. Speaker : Question is—

That Sub-Clause (2) of Clause-1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Sub-Clause (3) of Clause-1

Mr. Speaker : Question is—

That Sub-Clause (3) of Clause-1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clauses-2 to 9

Mr. Speaker : Question is—

That Clauses-2 to 9 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Sub-Clause (1) of Clause-1

Mr. Speaker : Question is—

That Sub-Clause (1) of Clause-1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Town and Country Planning Minister will move that the Bill be passed.

नगर एवं ग्राम आयोजना मंत्री (श्री धीरपाल सिंह) : स्पीकर सर, मैं प्रस्ताव करता हूँ—

कि विधेयक पारित किया जाए।

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House stands adjourned till 9.30 A.M. on Friday, the 14th March, 2003.

*14.50 hrs. The Sabha then *adjourned till 9.30 A.M. on Friday, the 14th March, 2003.

37369—H.V.S.—H.G.P., Chd.